खण्ड-07 सत्र-03 अंक-21

शुक्रवार 25 मार्च, 2022 04 चैत्र, 1944 (शक)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्यमेव जयते

सातवीं विधान सभा

तीसरा सत्र

अधिकृत विवरण

(खण्ड-07 (भाग-01) में अंक 19 से अंक 24 तक सम्मिलित हैं)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

राज कुमार

सचिव

RAJ KUMAR

Secretary

महेन्द्र गुप्ता

उप-सचिव (सम्पादन)

MAHENDRA GUPTA

Deputy Secretary (Editing)

विषय सूची

सत्र-03 शुक्रवार, 25 मार्च, 2022/4 चैत्र, 1944 (शक) अंक-21

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1-2
2.	विशेष उल्लेख (नियम-280)	3-29
3.	दिल्ली का आर्थिक सर्वेक्षण (2021-22)	30
4.	आउटकम बजट (2021-22) की 31 दिसंबर, 2021 तक की स्टेटस रिपोर्ट	31-51
5.	धन्यवाद प्रस्ताव	52-54
6.	अल्पकालिक चर्चा (नियम-55)	55-151

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-03 शुक्रवार, 25 मार्च, 2022/4 चैत्र, 1944 (शक) अंक-21

दिल्ली विधान सभा

सदन पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुआ।

सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए:

1. श्री अजेश यादव
2. श्री ए. धनवंती चंदीला ए.
3. श्री अजय दत्त
4. श्रीमती आतिशी
5. श्री अमानतुल्ला खान
6. श्री अब्दुल रहमान
7. श्रीमती बंदना कुमारी
8. सुश्री भावना गौड़
9. श्री बी.एस. जून
10. श्री दिनेश मोहनिया
11. श्री गिरीश सोनी
12. श्री हाजी युनूस
13. श्री जरनैल सिंह
14. श्री करतार सिंह तंवर
15. श्री कुलदीप कुमार
16. श्री नरेश यादव
17. श्रीमती प्रीति जितेंद्र तोमर
18. श्री प्रवीण कुमार
19. श्रीमती प्रमिला धीरज टोकस
20. श्री प्रकाश जारवाल

21. श्री ऋतुराज गोविंद
22. श्रीमती राजकुमारी ढिल्लों
23. श्री सोम दत्त
24. श्री सोमनाथ भारती
25. श्री सौरभ भारद्वाज
26. श्री सही राम
27. श्री विशेष रवि
28. श्री विनय मिश्रा
29. श्री वीरेंद्र सिंह कादियान
30. श्री अभय वर्मा
31. श्री अनिल कुमार बाजपेयी
32. श्री अजय कुमार महावर
33. श्री जितेंद्र महाजन
34. श्री मदन लाल
35. श्री मोहन सिंह बिष्ट
36. श्री ओमप्रकाश शर्मा
37. श्री पवन शर्मा
38. श्री प्रलाद सिंह साहनी
39. श्री राजकुमार आनंद
40. श्री शोएब इकबाल
41. श्री एस. के. बग्गा
42. श्री सुरेंद्र कुमार
43. श्री विजेंद्र गुप्ता

दिल्ली विधान सभा
की
कार्यवाही

सत्र-03 शुक्रवार, 25 मार्च, 2022/4 चैत्र, 1944 (शक) अंक-21

दिल्ली विधान सभा

सदन पूर्वाह्न 11.03 बजे समवेत हुआ ।

माननीया अध्यक्ष महोदया (श्रीमती राखी बिरला) पीठासीन हुईं।

माननीया अध्यक्षः रूल-280 श्री वीरेंद्र सिंह कादियान जी।

विशेष उल्लेख (नियम-280)

श्री वीरेंद्र सिंह कादियानः माननीय अध्यक्ष जी दिल्ली कैंट विधानसभा क्षेत्र दिल्ली के बिल्कुल मध्य में है और ये नई दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल और छावनी क्षेत्र, दो भागों में बंटा हुआ है। आधे में होम मिनिस्टरी का और आधे में रक्षा मंत्रालय का कार्य चलता है। दिल्ली सरकार की यहां मात्र 14 एकड़ भूमि है वो भी मायापुरी की तरफ यहां पर मैं आपका संज्ञान एक बेहद ज्वलंत मुद्दे पर दिलाना चाहता हूँ। यहां पर दो झुग्गी बस्तियाँ है, किब्री प्लेस और बरार square प्रधानमंत्री आवास से 10-12 किलोमीटर की दूरी पर इन दोनों झुग्गियों में पिछले लगभग 25 वर्ष से बिजली की व्यवस्था नहीं है। और जब हम कोशिश करते हैं तो यहां पर रक्षा

मंत्रालय के अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के लोग बाधा पहुंचाते है। अभी हाल ही में हमने एक ट्यूबल लगाने की कोशिश की थी वो ट्यूबल भी नहीं लगने दिया। तो मैं आपका संज्ञान इस विषय पर दिलाना चाहता हूँ कि अभी 40 से 50 डिग्री टैंपरेचर हो जाएगा यहां पर बच्चे भी हैं, बुढ़े, महिलाएं, बीमार। बिजली की आवश्यकता आज सभी को है, जिस झुग्गियों में करीब-करीब 10 हजार लोग रहते हैं और ये 10 हजार लोग बिजली से वंचित है। हमारे अनेकों प्रयास करने के बाद भी इन झुग्गियों में बिजली नहीं लग पाई है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस हाउस के माध्यम से माननीय बिजली मंत्री को ये आग्रह करना चाहूँगा कि वहां पर बिजली की कुछ व्यवस्था, चाहे वो सौर ऊर्जा के द्वारा हो या और कोई संसाधन से बिजली मुहैया कराई जाए। ऐसी स्थिति में हम जब भी वहां जाते हैं तो उनकी एक ही बात रहती है जी आपने ठीक है आपने ये काम कर दिया, वो काम कर दिया पर बिजली कब लाओगे। तो बिजली की व्यवस्था की जाए, इन झुग्गियों में जो की दिल्ली के बिल्कुल मध्य में जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर इन दो झुग्गियों में बिजली नहीं है और 10 हजार लोग बिजली से वंचित है। इस समस्या का मैं संज्ञान माननीय बिजली मंत्री को भी और सदन को दिलाना चाहूँगा, बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी।

माननीया अध्यक्षः श्रीमती वंदना कुमारी जी।

श्रीमती बंदना कुमारीः थैंक्यू स्पीकर मैडम, मैं सदन का ध्यान, ये सभी साथियों की लगभग समस्या होगी, यू.डी विभाग कार्यान्वयन एजेंसी के विधायक फंड आवंटन करने के तरीके में कुछ नीतिगत बदलाव लाना बहुत ही आवश्यक है। मैं एक उदाहरण के द्वारा समझाना चाहूंगी- यदि कोई कार्यान्वयन एजेंसी हमें किसी जनहित के कार्य के लिए कुछ राशि का अनफमान, राशि का एस्टिमेटिड कॉस्ट देती है, यू.डी. उसमें से 50 प्रतिशत राशि एमएलए फंड के माध्यम से उस कार्यान्वयन एजेंसी को जारी कर देता है, टैंडर अमाउंट जिसको हम लोग बोलते है। सामान्यतः अनफमानित मूल्य, एस्टिमेटिड कॉस्ट का लगभग 50-60 प्रतिशत, कहीं-कहीं तो 40 प्रसैंट वो रिलीज होता है और वर्ष के अन्त में एमएलए फंड का लगभग 40 से 50 प्रतिशत के करीब अंतर राशि अगले वित्तीय वर्ष के आगे नहीं बढायी जाती, बल्कि वो राशि समाप्त हो जाती है। इस प्रकार निर्वाचन क्षेत्र में हमारे जनहित के कार्य की मात्र भी सीमित हो जाती है क्योंकि इस अंतर की राशि को हम अपने क्षेत्र के विकास कार्यो में आसानी से लगा सकते थे। परन्तु वो इस नीति के कारण लैप्स हो जाती है और प्रभावी तौर पर एमएलए फंड सरकार द्वारा आवंटित वास्तविक फंड मूल्य का केवल 50-60 प्रसैंट ही रह जाता है। इस मामले पर अति गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। इस नीति में उचित परिवर्तन लाना जरूरी है जिससे एक निर्वाचन क्षेत्र मे सार्वजनिक लाभार्थी कार्यो को बढ़ाने में एमएलए फंड के पूरे उपयोग में मद्द मिलेगी। इस नियम के तहत हम लोग एम.एल.ऐ फंड 50 परसैंट विधानसभा में विकास के लिए

इस्तेमाल होता है। बजट इस्तेमाल के आते-आते जून-जूलाई हो जाता है। उसके बाद जमीन पर लगते नवम्बर-दिसम्बर कर देते हैं। उसके बाद जब काम शुरू हो जाता है, बिल बताने फिर फरवरी मार्च हो जाती है। तो वो जो 4 करोड़ का फंड है वो 2 करोड़ ही हमारे क्षेत्र में लग पाता है और फिर 2 करोड़ अगले साल उसको कैरी पफोरवर्ड नहीं करते और साथ में वो 2 करोड़ अमाउंट ही हमारे क्षेत्र में यूज होता, 2 करोड़ लैप्स हो जाता है जबकि पहले ऐसा नहीं था। लेकिन लगभग इस 5 साल में हमने देखा कि जो कैरी पफॉरवर्ड नहीं होता अगले साल हम उसको उपयोग में नहीं ला सकते और अधिकारियों की इतनी लापरवाही होती है जो sanction होते-होते जो हमारा अप्रैल में बजट होगा वो ग्राउंड पर sanction होने में मार्च-जून-जुलाई तक आ जाता है। फिर काम को sanction पूरा करके ग्राउंड पर आने में नवंबर, दिसम्बर बना देते हैं। जब तक वो बिल नहीं जमा करेंगे तब तक वो बचा हुआ अमाउंट हमारा रिलीज नहीं होगा। तो जबकि एस्टीमेटिड कॉस्ट तो 4 करोड़ का जो है हमारा वो 2 करोड़ ही हुआ। तो फिर भी हम लोग कहते हैं काम को।

माननीया अध्यक्षः धन्यवाद, नरेश यादव जी।

श्रीमती बंदना कुमारीः छोटे-छोटे काम को करने के लिए नहीं हो पता, तो मेरी सदन से इसपर अच्छे से विचार किया जाए और इस बात को गम्भीरता से ली जाए ताकि हम अपने क्षेत्र में जितने

भी एमएलए फंड का सही इस्तेमाल कर पाएं और क्षेत्र के विकास का कार्य कर पाएं, जय हिन्द, जय भारत।

माननीया अध्यक्षः नरेश यादव जी, रोहित कुमार जी।

श्री रोहित कुमारः धन्यवाद माननीय अध्यक्षा जी आपने नियम-280 के तहत मुझे अपने क्षेत्र की समस्या उठाने का मौका दिया। मैं आपका और सदन का ध्यान अपने क्षेत्र की पानी की समस्या के लिए दिलाना चाहता हूँ। मेरे त्रिलोकपुरी विधानसभा का वार्ड है, वार्ड नम्बर-4 ई न्यू अशोक नगर। वहां पर पिछले कई सालों से पानी की बहुत गम्भीर समस्या है, गर्मियों में तो बहुत हालत खराब हो जाती है। बिना टैंकर के काम नहीं चलता है, टैंकरों के लिए भी बहुत लम्बी-लम्बी कतारें लगती है वहां पर और लोग जिस कारण बहुत परेशान है। कारण ये है कि वहां पर जो पानी आता है वो दल्लूपुरा यूजीआर से आता है और दल्लूपुरा यूजीआर से जो पाइप लाइन चलती है वो वसुंधरा एंक्लेव की सैकड़ों सोसाइटीज के बीच में से गुजरती हुई जब यहां तक पहुंचती है तो पानी बिल्कुल नहीं बचता है। क्योंकि वसुंधरा एंकलेव की सैकड़ों सोसाइटीज में बड़े-बड़े बूस्टर लगे हुए हैं जिससे सारी पानी की खपत वहीं पर हो जाती है, बहुत कम पानी यहां तक पहुंचता है। तो मेरा आग्रह था डिपार्टमेंट में भी मैंने लिखकर दिया हुआ है, इसके लिए प्रयासरत हूँ पिछले काफी समय से कि वहां के लिए न्यू अशोकनगर के लिए, दल्लूपुरा से एक सैपरेट पाइप लाइन डाली जाए, ताकि

पानी सीधा न्यू अशोक नगर वासियों के लिए वहां पर पहुंचे। तो ये काम आपको बताना चाहूँगा, प्रस्तावित भी है, पहले से ही इसकी फाइल चल रही है लेकिन उस काम की गति इतनी स्लो है कि अभी तक पानी की बूँद-बूँद के लिए तरस रहे हैं। तो मैं आपके जरिए माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा कि मेरे विधानसभा के न्यू अशोकनगर लोगों की, न्यू अशोकनगर वासियों की समस्या पर संज्ञान लेते हुए पानी मुहैया कराने का कष्ट करें, वर्ना इस गर्मी में फिर से लोग, क्योंकि लोगों की फिर से वही पानी को लेकर मारा-मारी रहती है। अक्सर झगड़े हो जाते हैं, फसाद वहां पर होते हैं, ऐसा कोई दिन नहीं होता कि पानी के टैंकरों पर झगड़ा नहीं होता है। तो सभी की परेशानियों को देखते हुए कृप्या करके इसके पानी की समस्या का समाधान करने का कष्ट करें। मैं आपका और सदन का, मंत्री जी का बहुत आभारी रहूंगा, जल बोर्ड का आभारी रहूँगा, बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीया अध्यक्षः जरनैल सिंह जी।

श्री जरनैल सिंहः धन्यवाद स्पीकर साहिबा। अध्यक्षा महोदय मैं आपके माध्यम से अलग-अलग विभागों द्वारा क्षेत्र में किए जाने वाले जो डेवलमेंट के काम है, उसमें जरूरत से ज्यादा जो डिले हो रहा है उसपर ध्यान आपका आकर्षित करना चाहता हूँ। कई महीनों पहले लगभग एक साल पहले फंड दिये जाने के बावजूद भी अभी तक काम शुरू नहीं हो पाए हैं। मैं उसकी वजह बता देता हूँ कि पहले तो यूडी से फंड sanction आ गया है, NIT लग गई, थोड़ा

डिपार्टमेंट की तरफ से, तो रूटिन में जितना डिले चलता था चलता रहा। जब वर्क ऑर्डर अवार्ड हो गया तो ठेकेदार ने इतने कम रेट पर ठेका उठाया कि बाद में वो काम करने से ही इंकार कर गया और भाग गया। ऐसा एक काम में नहीं हुआ, डूसिब, एमसीडी और फ्लड तीनों डिपार्टमेंट में अलग-अलग ठेकेदारों द्वारा ये किया गया। अल्टीमेटली हम inauguration भी करके आ गए भई कल से ये आपके गेट लगने शुरू हो जाएंगे, कल से ये सड़क बननी शुरू हो जाएगी। उसके बाद जब काम नहीं शुरू हुआ, डिपार्टमेंट से पूछा तो वो कहते हैं कि जी ठेकेदार काम करने से भाग गया। तो इस तरीके के ठेकेदारों पर डिपार्टमेंट सख्त एक्शन ले, ऐसा कोई सरकार नियम बना दे या कोई ऐसा एक बारी सबकी समीक्षा हो जाए कामों की कि जो ठेकेदार बिना वजह या नाजायज वजह से काम छोड़कर भाग जा रहे है उनके ऊपर डिपार्टमेंट क्या सख्त कार्रवाई कर रहा है वो सुनिश्चित किया जाए, थैंक्यू जी।

माननीया अध्यक्षः सुरेंद्र सिंह जी।

श्री सुरेन्द्र सिंहः माननीय अध्यक्षा नियम-280 के अधीन आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में करीब 150 करोड की योजनाएं लंबित पड़ी हुई है। आदरणीय विकास मंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ कि इन सभी कालोनियों की लंबित पड़ी योजनाओं एवं विकास के लिए फंड देने का कार्य करें जोकि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रॉयोरिटी पर ली गयी

कालोनियों पर फंड देने का आदेश किया गया था। माननीय अध्यक्षा, मेरी विधानसभा क्षेत्र के लोग बहुत परेशान है, एंव विकास को लेकर त्रही त्रही मची हुई हैं। यहां पर कई साल पहले सीवर लाइन डालने के बाद कार्य नहीं किए गए हैं, तब से इस क्षेत्र की कालोंनियों में जल भराव रहता है। एक-एक, डेढ़-डेढ़ फुट के गड़ढ़े हो गये है। माननीय अध्यक्षा इस समस्या के समाधान हेतु मै सदन एंव आपके माध्यम से माननीय विकास मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरी विधानसभा क्षेत्र को फंड देने की कृपा करें जिससे की क्षेत्र का विकास हो सके और समस्या हल हो सके, धन्यवाद।

माननीया अध्यक्षः बाजपेयी जी।

श्री अनिल कुमार बाजपेयीः आदरणीय अध्यक्षा महोदय जी मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने नियम-280 के अंतर्गत मुझे बोलने का अवसर दिया। आरणीय अध्यक्षा महोदय जी मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान दिल्ली की चरमराती स्वास्थ्य व्यवथा की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं का खूब बढ़-चढ़कर प्रचार किया जाता रहा है परन्तु कोरोना महामारी के दौरान दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं की पूरी तरह से पोल खुल गयी। दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लीनिक पूरी तरीके से फेल हो चुके है। सरकारी डिस्पेन्सरियों एवं अस्पतालों में लोगों

को दवाइयाँ आज भी नहीं मिल पाती है। दिल्ली सरकार केन्द्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना को जानबूझकर दिल्ली में लागू नही कर रही है। अध्यक्षा जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए अस्पतालों की स्थिति में सुधार किया जाये, डॉक्टर्स के खाली पद जल्द से जल्द भरे जायें और भारत सरकार की आयुष्मान योजना जो पूरे देश में लागू है उसको दिल्ली में बिना किसी विलम्ब के लागू किया जाये। इसकी घोषणा स्वयं दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय केजरीवाल ने सत्र के पहले, सबसे पहले जब हम लोग जीतकर आये थे तब सदन में की थी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार।

माननीया अध्यक्षः श्री प्रवीण कुमार जी। श्री करतार सिंह तंवर जी।

श्री करतार सिंह तंवरः धन्यवाद अध्यक्षा जी, आपने 280 के तहत मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्षा जी जिस विषय पर मैं बात कर रहा हूँ वो सिर्फ छतरपुर विधान सभा से नहीं बल्कि पूरी दिल्ली के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। दिल्ली सरकार के सहयोग से और सिंगापुर गवर्नमेन्ट के सहयोग से छतरपुर में स्किल सेन्टर का निर्माण करीब तीन वर्ष पहले शुरू हुआ था जो कि प्लानिंग बहुत पहले से थी लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में आने के बाद वो शुरूआत हुई। 175 करोड़ की लागत

से भवन का निर्माण भी शुरू हो चुका था जो फॉरेस्ट विभाग के द्वारा रोक दिया गया है। मेरी विनती है कि जल्दी से जल्दी दोबारा इस कार्य को शुरू कराया जाये। धन्यवाद।

माननीया अध्यक्ष: श्री अभय वर्मा जी।

श्री अभय वर्मा: धन्यवाद अध्यक्षा महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय शहरी विकास मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि पिछले दिनों मैंने एक पत्र के माध्यम से शहरी विकास विभाग में नेमिंग कमेटी के पास एक प्रस्ताव भेजा था कि विकास मार्ग पर स्थित निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन के पास के चौक का नामकरण महाराजा अग्रसेन के नाम से करके उनकी प्रतिमा स्थापित की जाये। इसी प्रकार मदर डेयरी रोड पर गणेश नगर के सामने वाले चौक का नामकरण महान स्वतंत्रता सेनानी बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पर किया जाये और वहाँ पर बाबू वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा भी स्थापित की जाये। उपरोक्त कार्यों को जल्द से जल्द प्रस्ताव पारित कर नामकरण एवं प्रतिमा स्थापित करने का कार्य पूरा किया जाये। एक बात और कहना था 280 में।

माननीया अध्यक्ष: नहीं जो आपने लिखकर दिया है वही है।

श्री अभय वर्मा: मैं 280 में, मैडम पहले कई बार मैंने प्रश्न उठाये हैं जिसका कोई जवाब, कोई उल्लेख हमारे पास नहीं आया। ये आपके ध्यान में ला रहा हूँ।

माननीया अध्यक्षाः आप इसको लिखकर दे दीजिये। श्री मोहन सिंह बिष्ट जी।

श्री मोहन सिंह बिष्टः आदरणीय अध्यक्षा जी, आपने मुझे 280 के तहत बिजली सम्बन्धी लोकहित महत्व के इस विषय पर बोलने का मौका दिया। उसके लिये तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। आदरणीय अध्यक्षा जी, मैं आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय का ध्यान बिजली कम्पनियों द्वारा दिल्ली की जनता को दी जा रही महंगी बिजली और बिजली कम्पनियों द्वारा जनता के साथ की जा रही खुली लूट की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। दिल्ली के उपभोक्ताओं को देश में इस समय सबसे महंगी बिजली दी जा रही है। घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 8 रूपया प्रति यूनिट तक तथा कामर्शियल बिजली उपभोक्ताओं को 13 रूपया प्रति यूनिट वसूला जा रहा है। यही नहीं अध्यक्षा जी फिक्स चार्ज के नाम से घरेलू कनेक्शन पर 125 रूपया प्रति किलोवाट प्रतिमाह, कामर्शियल के रूप में 270 रूपया प्रतिमाह लिया जा रहा है जो कि देश में सर्वाधिक है। इतना ही नहीं बिजली कर्मचारियों और अधिकारियों को दी जाने वाली 700 यूनिट तक मुफ्त बिजली कर्मचारियों को और उनके दी जाने वाली पेन्शन की धनराशि भी दिल्ली के उपभोक्ताओं से ही वसूली जा रही है। इस तरह बिजली कम्पनियों द्वारा उपभोक्ताओं से खुली लूट की जा रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय बिजली मंत्री जी से एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि

दिल्ली की जनता को अधिक से अधिक सस्ती बिजली मुहैया कराने की कृपा की जाये जिससे दिल्ली के लोगों को इसका लाभ मिले और जो बिजली कम्पनी है जो खुली लूट मचा रही है उन पर रोक लग सके। ये मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ। धन्यवाद।

माननीया अध्यक्षः श्री विजेन्द्र गुप्ता जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्षा जी सर्वप्रथम तो आपका स्वागत है। आज आप सदन की कार्रवाई को चला रही हैं। आपका अभिनन्दन है। माननीय अध्यक्षा महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान घरेलू कामगारों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। आज घरेलू कामगारों की देश में बहुत मांग है क्योंकि वे घरों को संचालित करने के लिए अनिवार्य सेवा प्रदान करते हैं। अन्य रोजगार तक पहुंच न होने से बड़ी संख्या में महिलायें और पुरूष घरेलू कामों में लगे हुए हैं जिनमें महिलायें बहुसंख्यक है। ये संख्या बढ़ रही है इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि ऐसे श्रमिकों को उनके वेतन का उचित हिस्सा और सामाजिक सुरक्षा मिले क्योंकि ये विशिष्ट परिस्थितियों में काम करते हैं। जिन घरों में काम करते हैं उनके काम की परिस्थितियों पर भी विचार करने की आवश्यकता है। अध्यक्षा जी, दिल्ली में लगभग पांच लाख से अधिक घरेलू कामगर काम करते हैं। पिछले दो सालों में कोरोना संक्रमण के दौरान उनमें से काफी कामगरों के काम छूट गये है। उनमें से किसी को भी कोई राहत नहीं मिली क्योंकि घरेलू कामगरों की

कोई पहचान व गणना नहीं है। अध्यक्षा जी, मैं आपके माध्यम से दिल्ली की सरकार से, अरविन्द केजरीवाल से, मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल जी से निवेदन करता हूँ कि वो घरेलू कामगारों की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक कानून का प्रस्ताव बनायें जो उन्हें पूरी तरह से सभी सामाजिक सुरक्षा प्रदान करे। अध्यक्षा जी, मैं अन्त में।

माननीया अध्यक्षः धन्यवाद, धन्यवाद। श्री संजीव झा जी। हो गया इतना ही लिखा था आपने। इससे उपर एक भी शब्द लिखा है। नहीं लिखा है इसमें। उसके बाद लिखा है विजेन्द्र गुप्ता जी, सदस्य विधान सभा। कुछ नहीं लिखा। संजीव झा जी। जितना लिखकर दिया उतना ही बोला जायेगा।

श्री संजीव झाः बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्षा महोदय कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और शुभकामनायें भी कि आज आप इसको चेयर कर रही हैं। अध्यक्षा महोदय एक बहुत गम्भीर विषय मैं सदन में उठाना चाहता हूँ और माननीय राजस्व मंत्री का ध्यानाकर्षण भी आपके माध्यम से चाहता हूँ। हमारे यहाँ अनाथराइज कालोनी में जो रेगुलराइज कालोनी है उसमें ग्राम सभा की जमीन है। जनरली राजस्व विभाग क्या करता है चकबन्दी के टाइम में कृषि के नाम पर अनाथराइज कालोनी के अन्दर जो ग्राम सभा की जमीन जो एलाट कर देता है। हमारे यहाँ एक हडवार की जमीन थी। हडवार की जमीन को एलाट नहीं कर सकते हैं, चकबन्दी में कमीबेशी के नाम पर भी। तो 2007 में पहले एलाट किया गया

था। लोगों ने चैलेन्ज किया। रूक गया। फिर 2009 में एलाट किया। उसको लेकर वहाँ के जो आरडब्लूए थी वो गयी डिवीजनल कमिश्नर के पास। अपील किया लेकिन उसके बावजूद एलाट कर दिया गया 2013 में। उसके बाद फिर एसडीएम कोर्ट में लोगों ने अपनी अपील लगायी और अभी आज से दस दिन पहले एसडीएम ने फिर उसको एलाट कर दिया। अब वो बीच कालोनी में है और कालोनी के लोगों का, कालोनी अनाथराइज रेगुलराइज कालोनी है। हालांकि ये प्रोविजन भी था कि अनॉथराइज कालोनी जो 2007 के मैप के अन्दर अगर कोई ग्राम सभा की जमीन है तो ऐसे भी कोई डिपार्टमेन्ट उसको एलाट नहीं कर सकती है। अब इस बात को लेकर हमारे वहाँ के लोकल कालोनी रेजीडेन्ट में या पूरे विध ान सभा में इस बात को लेकर बहुत रोष है। मैं आपके माध्यम से राजस्व मंत्री जी का ध्यानाकर्षण भी कर रहा हूँ। मैंने चिट्ठी भी लिखा है कि पहले उसको इमीडिएटली रोक दिया जाये। चूँकि वो बहुत कीमती जमीन है। ऑनन-फानन में कोलोनाइजर लोग है वो बेच देंगे, फिर गरीब लोग उसका शिकार हो जायेंगे। तो पहले इमीडिएटल रोक दिया जाये और फिर राजस्व विभाग के सभी अधि कारियों को बुलाकर ये पूछा जाये कि आखिर कैसे इस तरह की गलती हुई और इसको क्यों एलाट किया गया और चूँकि ये राजस्व मंत्री खुद बहुत अच्छे वकील भी है, इसमें जो भी कानूनी प्रोविजन है उसको ध्यान में रखते हुए उस ग्राम सभा को बचाया जाये। ध न्यवाद।

माननीया अध्यक्षः श्री एस.के.बग्गा जी। ये आखिरी है।

श्री एस.के.बग्गाः अध्यक्षा महोदया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे नियम-280 के अन्तर्गत बोलने का मौका दिया। अध्यक्षा महोदया मैं आपका ध्यान दिल्ली जल बोर्ड की ओर दिलाना चाहता हूँ। मेरी कृष्णा नगर विधान सभा में ज्यादातर जगह पर पानी के मीटर रीडर रीडिंग करने नहीं जाते हैं। दफ्तर में बैठे मीटर्स स्टॉप लिख देते हैं। लोगों के पानी के बिल रीडिंग के एस्टीमेट बेसिस पर ज्यादा रकम के आ रहे हैं। लोग मेरे दफ्तर में बिल लेकर आते हैं। हम उन्हें दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर में जैडआरओ के पास भेजते हैं तो कोई हल नहीं निकलता। लोग बहुत परेशान हैं। इतना ज्यादा बिल कैसे जमा करायेंगे। आपसे प्रार्थना है कि दिल्ली जल बोर्ड को आदेश देकर पानी के बिल ठीक करवायें जिससे जनता को राहत मिले। धन्यवाद।

माननीया अध्यक्षः देखिये आज मुझे भी इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि अभी तक 14 साथी नियम-280 के तहत अपनी बात रख चुके हैं और अभी समय है अभी भी, तो जितने भी साथी पिछले आधे घण्टे में हम लोग ले सकते हैं उनको जरूर मौका देंगे। श्री सही राम जी। बस इसी तरह से समय का ध्यान रखकर अगर आप बात करेंगे तो साथी सदस्यों का भी नम्बर आयेगा।

श्री सही रामः धन्यवाद अध्यक्षा महोदय, मैं आपका और सदन का ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो पिछले चार साल से पेन्डिंग में पड़ा हुआ है। मेरी विधान सभा में हरकेश नगर गाँव है उसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि उसमें आधे गाँव में सीवर लाईन डल चुकी है। आधे गाँव का आउटफॉल होना है। ओखला इण्डस्ट्रियल एरिया में आधे का जाना है ओखला टैंक में। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि चार साल पहले अब मैं कहूँ भ्रष्ट एमसीडी, चार साल पहले ढाई करोड़ रूपये वहाँ जमा करा चुके हैं लेकिन आज तक वो रोड कटिंग की परमीशन नहीं दे रहे हैं। इसी तरह कितनी बार लेटर लिखे गये हैं। इसी तरह आधे गाँव का आउट फॉल जाना है रेलवे को क्रास करके। रेलवे मंत्रालय से भी कितनी बार पत्राचार हो चुका है। ना तो वो परमीशन दे रहे हैं और ना ही वो परमीशन दे रहे हैं जबकि पैसा जमा है और जो पैसा जमा है जहाँ आधे गाँव में सीवर लाइन डली है उसको रोड को भी मैंने एमएलए हेड से बना दिया है। उसका जो रोड कटिंग का पैसा, एक पैसा एमसीडी ने खर्च नहीं किया। रेलवे मंत्रालय को लिखा है कि वह हमें या तो जल बोर्ड पैसा देने के लिए तैयार है रेलवे डिपार्टमेन्ट को। वो या तो आउट पफाल बना करके बना करके हमें दे दें, नहीं तो हम पैसा देने के लिए तैयार है। वो हमें परमीशन तो दे। पूरे 1 लाख की आबादी है हरकेष नगर गांव की जी। अध्यक्षा जी, नर्क बना हुआ है आधे गांव में सीवर लाइन डली है लोगों ने कनेक्शन कर लिए हैं वो ओवरफ्लो होता रहता है लेकिन

इनके कानों पर जूँ रेंगने के लिए तैयार नहीं, पैसा हम देने के लिए तैयार हैं। परमिशन देने के लिए मैंने अध्यक्ष महोदय को भी कई बार इसमें लेटर लिखा है। अनुरोध किया है कि इनको कमेटी में बुलाया जाए यहां, किसी कमेटी में बुलाया जाए और इनसे पूछा जाए कि पैसा जमा होने के बाद भी इन्हें क्या आपत्ति है जो एनओसी नहीं दे रहे और जो पैसा जमा हुआ है जहां रोड कटिंग हुई है वो एमएलए लैड से बना दिया है मैंने रोड, वो ढाई करोड़ रूपये कहां इन्होंने खर्च किया है उसका भी ब्यौरा इनसे लिया जाए और मेरा आपसे अनुरोध है कि रेलवे को भी लिखा जाए कि वो या तो खुद बना लें, दिल्ली जल बोर्ड पैसा देने के लिए तैयार है। ये पत्र साथ संलग्न कर रहा हूँ, मैं आपको पहुंचा रहा हूँ, इसमें संज्ञान लेने का काम करें, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

माननीया अध्यक्षः राजकुमारी जी।

श्रीमती राजकुमारी ढिल्लोंः माननीय डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे आपने 280 पर बोलने का मौका दिया और यह भी बड़ी खुशी की बात है बींग ए महिला आज अभी सीट पर बैठी हैं और बहुत अच्छे से सदन को आप चला रही हैं मैक्सिमम लोगों को आप 280 पर बोलने का मौका दिया जा रहा है। धन्यवाद। माननीय डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरा एक प्रश्न है मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ ये मेरी विधानसभा का नहीं होगा ये जनरली पूरी दिल्ली के हर वार्ड में, हर

विधानसभा में एक समस्या है जोकि हम लोग एमएलए लैड से डीडीए के पार्क्स में और एमसीडी के पार्क्स में हम लोग जो ओपन जिम लगाते हैं उसकी मेंटेनेंस के लिए हमारे पास कोई एजेंसी या कोई प्रावधान नहीं है। मैं आपकी चेयर की माध्यम से मंत्री जी से ये जानना चाहूँगी कि ऐसी कौन सी एजेंसी है कि हम मेंटेनेंस करवा पाएं क्योंकि अक्सर लोगों की शिकायतें रहती हैं कि एक साल के बाद ओपन जिम का डीडीए के पार्क या एमसीडी पार्क में जितने भी ओपन जिम लगे हैं कोई उसकी रिपेयर वर्क नहीं होता और एक साथ में छोटा सा क्वेश्चन मेरा एक और है कि जितने भी एमएलए लैड से हर क्षेत्र में बूम बैरियर्स लगाए जाते हैं उसके लिए भी जो एजेंसी है सिर्फ एक साल का वो मेंटेनेंस का उनका एक समय है उसके बाद वो कोई उसको मेंटेन नहीं करती जिससे कि आरडब्ल्यूए हमेशा शिकायत करती रहती है, इसका भी कोई प्रावधान होना चाहिए। आपने मुझे 280 पर बोलने का मौका दिया मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।

माननीया अध्यक्षः रामवीर बिधूड़ी जी। जितेंद्र महाजन जी।

श्री जितेंद्र महाजनः धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान श्याम लाल कॉलेज के सामने बने हुए ओवरब्रिज की ओर दिलाना चाहता हूँ। पिछले कई वर्षों से वो ओवरब्रिज बनकर तैयार है मगर इसके अंदर आज तक लिफट और जो स्लोप कोरिडोर बनाया जाता है वो बनाया नहीं गया है जिसके कारण से लोग पैदल सड़क पार करते

हैं और अनेक दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। मैं पीडब्ल्यूडी से अनुरोध करना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी इस ओवरब्रिज में लिफट लगाई जाए और जो स्लोप इसके बनाए जाने हैं ओवरब्रिज के, वो जल्दी से जल्दी बनाए जाएं। धन्यवाद।

माननीया अध्यक्षः अजय महावर जी।

श्री अजय कुमार महावरः धन्यवाद आदरणीय अध्यक्षा जी। नियम 280 के तहत मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली वक्फ बोर्ड को दी जाने वाली धनराशि की ओर करना चाहता हूँ। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली वक्फ बोर्ड को प्रतिवर्ष कितनी धनराशि प्रदान की जाती है, वह धनराशि किन किन मदों में खर्च होती है, यदि वह राशि इमामों और मौलवियों को वेतन के रूप में प्रदान की जाती है तो मंदिरों के पुजारियों, गुरूद्वारों के ग्रंथियों और चर्च के पादरियों को भी वेतन के रूप में इतनी ही धनराशि दी जानी चाहिए। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि आप माननीय मंत्री जी को निर्देश दें कि तुरंत मंदिर के पुजारियों, गुरूद्वारों के ग्रंथियों और चर्च के पादरियों को भी वेतन के रूप में इतनी ही धनराशि का बजट उपलब्ध कराया जाए जिससे उनका जीवनयापन भी सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा।

माननीया अध्यक्षः धन्यवाद। भावना गौड़ जी।

सुश्री भावना गौड़: धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं अपनी पालम विधानसभा के मधु विहार वार्ड में एक समस्या जो निजात पाने का नाम नहीं ले रही, यहां 280 में रखना चाहूँगी। अध्यक्ष महोदय, मेरी पालम विधान सभा क्षेत्र के मधु विहार क्षेत्र में इन दिनों एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है और इस क्षेत्र में भूजल का स्तर बहुत उपर आ गया है। और यह समस्या पिछले 2-3 वर्षो से लगातार बनी हुई है। मैंने इसके बारे में दिल्ली जल बोर्ड को अवगत कराया तो विभाग ने अपने स्तर के उपर पानी की आपूर्ति की लाइनों को अपनी मशीनों के द्वारा चेक करवाया पर इस जल स्रोत का कहीं भी पता नहीं चल पा रहा। अध्यक्ष महोदय, हालांकि विभाग ने इस क्षेत्र की अधिकांश पुरानी लाइनों को बदल दिया है पर भूजल का स्तर बहुत उपर बना हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस क्षेत्र का भूजल स्तर बहुत उपर आ गया है। इस संबंध में विभाग ने सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आने वाले विभाग सीडब्ल्यूसी की सहायता मांगी और उन्हें कई पत्र लिखे पर अभी तक उनसे हमें कोई किसी प्रकार की मदद नहीं मिली है। अध्यक्ष महोदय, मेरी विधानसभा में इस वार्ड में रहने वाले मधु विहार क्षेत्र में रहने वाले लोग सभी बहुत डरे हुए हैं, उन्हें ये डर सताता है कि कहीं ये जल, कहीं ये लीकेज होने वाला पानी जमीन के नीचे से आने वाला पानी हमारे मकानों के स्ट्रक्चर को गिरा न दे। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के मार्फत आपको बताना चाहूँगी कि मधु विहार क्षेत्र को लेकर के मैं स्वयं भी भयभीत रहती हूँ, कभी भी कोई

भी बड़ा हादसा मेरे मधु विहार क्षेत्र में हो सकता है, पानी जमीनों के जो बेसमेंट बनाए हुए हैं रेगुलर बेसमेंट से वो पानी रिस रहा है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है इस समस्या से निजात दिलाने के लिए सभी संबंधित विभाग एक साथ काम करें और यह पता लगाया जाए कि इस भूजल स्तर को हम कैसे रोक सकते हैं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया बहुत बहुत शुक्रिया।

माननीया अध्यक्षः ओम प्रकाश शर्मा जी।

श्री ओमप्रकाश शर्माः धन्यवाद अध्यक्ष महोदया जी, बहुत ही सुचारू रूप से जो आज सदन को चला रही हैं उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। आदरणीय अध्यक्षा जी, मैं माध्यम से दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग के मंत्री महोदय का ध्यान पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना की ओर दिलाना चाहता हूँ। मंत्री महोदय भले ही यह दावा करें कि पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं परंतु मैं अनेकों बार मंत्री महोदय की जानकारी में इस सदन में ला चुका हूँ और मेरे विधान सभा क्षेत्र में विश्वास नगर में आज तक एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लग पाया है। मेरी विधान सभा विश्वास नगर में आज दिन तक क्यों नहीं एक भी सीसीटीवी कैमरा लग पाया है यह दिल्ली सरकार का विश्वास नगर विधान सभा क्षेत्र की जनता के साथ सौतेला व्यवहार है। अध्यक्षा जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि मेरी विधान सभा क्षेत्र विश्वास नगर में

जल्द से जल्द सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं जिससे वहां की जनता को इसका लाभग मिल सके धन्यवाद।

माननीया अध्यक्षः प्रवीन कुमार जी।

श्री प्रवीण कुमारः अध्यक्षा जी, मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्षा जी, ये जो मैं इशु उठा रहा हूँ मेरे क्षेत्र में निजामुद्दीन जंगपुरा विधान सभा क्षेत्र में निजामुद्दीन एरिया आता है, इलाका आता है और निजामुद्दीन क्षेत्र के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें स्कूल की पढ़ाई करने के लिए कई किलोमीटर तक जाना पड़ता है जिसके कारण कई बार उनके एक्सीडेंट भी हो जाते हैं और घर से दूर होने के कारण कई सारे बच्चे पढ़ाई से भी वंचित रह जाते हैं। मैंने कई बार जो है इसके लिए वहां पर एक नया स्कूल खोलने के लिए 12वीं तक का नया स्कूल खोलने के लिए कई बार डिपार्टमेंट को लिखा। एक्चुअली वो जमीन जो है वो जल बोर्ड से रिलेटिड है और जलबोर्ड के पास जमीन है और जलबोर्ड ने एजुकेशन डिपार्टमेंट को कह दिया है कि वो जमीन देने को तैयार है और सिर्फ और सिर्फ उस जमीन का जो है लैंड यूज चेंज होना है। पहले तो क्योंकि जमीन जो है सारी जमीन डीडीए के पास है और लैंड यूज चेंज करने का अधिकार भी डीडीए के पास है। हमारे डीडीए में जो मेंबर हैं हमारे सोमनाथ भारती जी, मैं इनकी तारीफ करना चाहूँगा कि 3 बार डीडीए ने हमारा केस बिल्कुल कूड़े के डिब्बे में डाल दिया लेकिन उस कूड़े के डिब्बे

में से ये दोबारा पर्चा निकाल कर लाए, 3 बार ये पर्चा निकाल के लाए और दोबारा उस मीटिंग में सदन पटल पर रखा और उसके बाद उस कमेटी में रखकर दोबारा उस केस को जिंदा किया और आज मैं दोबारा इस केस को यहां पर सदन पटल के सामने रखना चाहूँगा कि हमारा निजामुद्दीन में जो डीडीए को सिर्फ और सिर्फ उसका लैंड यूज चेंज करना है, एक छोटा सा काम है जब ये डीडीए को प्राइवेट प्लेयर्स को जमीन देनी होती है तुरंत उसका लैंड यूज चेंज कर देते हैं, किसी को लीज पर देनी होती है तुरंत उसका लैंड यूज चेंज कर देते हैं, जहां से प्रोफिटेबिलिटी आनी है वहां से तुरंत इनका काम हो जाता है लेकिन जो जनता से जुड़े हुए काम और अगर आम आदमी पार्टी के एमएलए ने उठा दिया तो वो काम समझ लीजिए बहुत मुश्किल काम हो जाता है इनके लिए। तो मैं सोमनाथ भारती जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा और मैं इस सदन के माध्यम से गुजारिश करना चाहूँगा कि यहां से आपके माध्यम से डीडीए से कुछ वार्तालाप की जा सके, चिट्ठी पत्र के माध्यम से उनको विधान सभा की कमेटी में बुलाया जा सके ताकि जो निजामुद्दीन क्षेत्र के लोग जो स्कूल से इतने सालों से वंचित हैं उनको एक स्कूल मिल पाए ताकि वहां पर बच्चे पढ़ लिख कर आप जैसे कभी बतौर इतनी बड़ी कुर्सी पर आकर बैठ सकें ऐसा वहां के क्षेत्र के लोगों को भी मौका मिलना चाहिए अध्यक्षा महोदय। और मेरी कल विजेंद्र गुप्ता जी से बात हुई थी मैंने उनसे कहा कि जी आप स्कूल बनवा दीजिए फीता आपके

हाथों से कटवा दूँगा। मैं तो वो उस बात के लिए भी एग्री हो गए, वो कह रहे हैं कि ठीक है मैं आपका सपोर्ट करूंगा। और इसमें एक चीज और एड करना चाहूँगा।

माननीया अध्यक्षः धन्यवाद, धन्यवाद प्रवीन जी कुलदीप जी।

श्री प्रवीण कुमारः एक चीज और एड करना चाहूँगा।

माननीया अध्यक्षः धन्यवाद इतना लिखा था आपने।

श्री प्रवीण कुमारः एक चीज और एड करना चाहूँगा।

माननीया अध्यक्षः धन्यवाद। कुलदीप जी। कुलदीप जी। अलाउ नहीं कर रहे आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)...

श्री कुलदीप कुमारः धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्षा जी मुझे समय देने के लिए। अध्यक्षा जी, आज 21वीं सदी के पहले दशक में जब से दिल्ली के अंदर मेट्रो सेवा की शुरूआत हुई है तब से मेरे कोंडली विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत Mayur Vihar फेज 3 इलाका है जहां पर लगभग 11 हजार डीडीए के फ्लैट्स हैं बहुत बड़ी आबादी है, अनआथोराइज्ड कालोनियां हैं, सभी दलित समाज के दबे कुचले समाज के लोग वहां निवास करते हैं, रहते हैं लेकिन अध्यक्षा जी, लगातार मांग उठने के बाद भी अभी तक उस इलाके को मयूर विहार फेज 1 मेट्रो स्टेशन हो गया, फेज 2

स्टेशन हो गया, बगल में चांद सिनेमा मेट्रो स्टेशन हो गया लेकिन मेरी विधान सभा में कोई भी मेट्रो स्टेशन नहीं आया है अभी तक और उसके साथ अभी एनआर सिटीने रेपिड रेल का प्रोजेक्ट शुरू किया। हमने लगातार उसको लिखा कि आप हमारे यहां कोई स्टेशन इसका दे दीजिए लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने वहां पर कोई मेट्रो स्टेशन नहीं दिया उसका भी। तो अध्यक्षा जी, मेरी इस सदन के माध्यम से ये विनती है कि हमारी विधान सभा, कोंडली विध ान सभा क्षेत्र को भी मेट्रो सेवा से दिल्ली के अलग अलग इलाकों से जोड़ने की कृपा की जाए ताकि वहां के लोगों के लिए सुगम यातायात की व्यवस्था हो सके और वो भी दिल्ली के बाकी कोनों से अपने को जुड़ा हुआ महसूस करें और जुड़ पाएं। बहुत बहुत ध न्यवाद।

माननीया अध्यक्षः सोमनाथ भारती जी।

श्री सोमनाथ भारतीः माननीय अध्यक्ष महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आपने मुझे 280 के तहत अपना मुद्दा उठाने का मौका दिया। पहले तो मैं ये प्रवीण जी ने जो बात उठाई थी उसमें एजुकेशन...

...(व्यवधान)...

माननीया अध्यक्षः अपने विषय पर, जो आपने लिखकर दिया है।

श्री सोमनाथ भारतीः एक लाईन अपडेट कर दूँ चूँकि उसको आप रेफर कर सकते हैं। एजुकेशन कमेटी को अगर रेफर कर दें

चूँकि एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग वहां पर आकर के स्टेटमेंट दे चुके हैं कि कोई alternative plot वो ढूढ़ रहे हैं to expediate the matter agar वो कमेटी में चला जाए मेटर आपका तो हो जाएगा, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ।

आज जो आपने मौका दिया है उसमें मैं ये उठाना चाहता हूँ कि एम.सी.डी. में जो हम फंड दे रहे हैं, MLA LAD fund जो एम.सी.डी. को दे रहे हैं क्षेत्र के काम करने के लिए उसमें अगर क्षेत्र का पार्षद भाजपा का है तो किस प्रकार से अड़चन डाल रहा है। 2019 में traffic de-congestion के लिए प्रैस एंक्लेव रोड से मालवीय नगर गोल चक्कर को जो रोड connect करता है उसकी widening का प्रोजेक्ट मैंने एम.सी.डी. को दिया। उन्होंने फंड ले लिया, सब्मिट हो गया, टेंडरिंग हो गई। टेंडरिंग होने के बाद कांट्रेक्टर को अपॉइंट कर दिया गया। उसका उद्घाटन हो गया। उद्घाटन होने के बाद एम.सी.डी. काम नहीं कर रही। हमने पता करने का प्रयत्न किया भई क्यों नहीं कर रहे आप। तो कहा कि जो क्षेत्रिय पार्षद हैं भाजपा की, वो उसमें अड़चन डाल रही हैं। अब वो ये समझ में नहीं आता कि अगर एम.सी.डी. ने फंड ले लिया या तो लेते नहीं और 2019 से लेकर के 2022 आ गया, क्षेत्र के लोग तकलीफ में हैं। environmentally वो प्रोजेक्ट बहुत जरूरी है चूँकि वहां पर जो congestion लगता है, कभी एक घंटा लगता है, कभी दो घंटा लगता है, लोग बहुत तकलीफ में हैं। मैं हाथ जोड़कर विनती कर चुका हूँ, पहली बार जिंदगी में मैंने किसी

भाजपा काउंसलर को फोन किया। मैंने कहा जी आपके हाथों मैं उद्घाटन करवा दूँगा, यहां तक कहा मैंने कि नाम की मुसीबत है, आप नाम ले लीजिए। नाम नहीं चाहिए हमें, आप उस प्रोजेक्ट को अपना बना लीजिए, वो काम होने दीजिए। लेकिन ये भाजपा के साथी बैठे हैं अगर चाहे तो उसपे मुझे आश्वासन दे दें कि ये जाकर बात करेंगे उनसे। तो मैं ये आपके जरिए लाना चाहता हूँ कि कमिश्नर को बुलाया जाए। मुझे लग रहा है कि कई सारे साथियों के पास ऐसी मुसीबते होंगी कि क्षेत्र का पार्षद अगर भाजपा का है तो वो काम नहीं होने दे रहा। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आपके माध्यम से कमिश्नर एस.डी.एम.सी. को बुलाया जाए कि भई ये जो या तो फंड वापस कर दें, कैंसिल कर दें। फंड को भी अटका रखा है, काम भी नहीं होने दे रहे हैं। जनता भी तकलीफ में है। सोमनाथ भारती ने हाथ भी जोड़ ली, भई तुम भले ही भाजपा के पार्षद हो, कोई बात नहीं, जनता के लिए हम हाथ जोड़ सकते हैं। लेकिन ये डेमोक्रेसी का ये कौन सा पहलू है कि अगर कोई और पार्टी का कोई पार्षद हो तो हमारा काम नहीं होने देगा? तो डेमोक्रेसी के अंदर इस प्रकार की अड़चनें डालना भाजपा को शोभा नहीं देता। कल भी मैंने जो एक मामला संज्ञान में लेकर आया था। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस मामले को आप रेफर कर दें किसी कमेटी में जहां कि कमिश्नर को बुलाकर के इस पर संज्ञान लिया जाए और इस काम को कराया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीया अध्यक्षः धन्यवाद जी। आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है पूरे 21 सदस्यों ने आज नियम 280 के तहत अपनी विधान सभा से संबंधित विषयों को उठाया है और ये मुझे लगता है, आप लोगों ने अनुशासन जो बनाकर रखा है, समय-सीमा का ध्यान रखा है, उसी की वजह से संभव हुआ है। मुझे लगता है रोज आप लोगों को इस तरह से सदन में अपना व्यवहार रखना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। अब श्री मनीष सिसोदिया जी, माननीय उप-मुख्यमंत्री, दिल्ली का आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 प्रस्तुत करेंगे।

माननीय उप-मुख्यमंत्री (श्री मनीष सिसोदिया): माननीया अध्यक्षा महोदय, मैं आपकी अनुमति से दिल्ली के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22[1] की हिंदी और अंग्रेजी की प्रति सदन पटल पर प्रस्तुत करता हूँ।

माननीया अध्यक्षः अब श्री मनीष सिसोदिया जी, माननीय उप-मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के आउटकम बजट 2021-22 की 31 दिसंबर, 2021 तक की स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

माननीय उप-मुख्यमंत्रीः अध्यक्षा महोदय, मैं आपकी अनुमति से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के आउटकम बजट 2021-22 की 31 दिसंबर, 2021 तक की स्टेटस रिपोर्ट[2] की हिंदी और अंग्रेजी प्रति सदन पटल पर प्रस्तुत करता हूँ और इसके संदर्भ में कुछ बातें भी मैं आपकी अनुमति से रखना चाहता हूँ। अध्यक्षा महोदय, दिल्ली

---

[1]दिल्ली विधान सभा पुस्तकालय में संदर्भ संख्याः आर-23015 पर उपलब्ध।

सरकार के बारे में आजकल जनरल नॉलेज का एक नया टॉपिक सामने आ गया है। जनरल नॉलेज में एक नया सवाल जुड़ गया है देश में कि जो कहा सो किया, इस तरह का कैरेक्टर रखने वाली सरकार देश में कौन सी है, तो 6 विधायकों को छोड़कर पूरे देश का बच्चा-बच्चा भी बोलता है कि जो कहा सो किया कहने वाली सरकार, करने वाली सरकार कौन सी है, तो बच्चा-बच्चा भी बताता है केजरीवाल सरकार।

...(व्यवधान)...

अध्यक्षा महोदय, मैं कहना चाहता हूँ जो कहा सो किया, इसका जनरल नॉलेज का सवाल अगर किसी बच्चे से कहीं से भी पूरे देश में पूछा जाता है तो लोग कहेंगे केजरीवाल सरकार। बहुत तेजी से कहते हैं केजरीवाल सरकार है। आज देश में और मैं कह रहा हूँ इनको भी चुनौती देकर, इनके भी कई सारे हैं, आज पूरे देश में इतने सारे मुख्यमंत्री हैं और हमेशा रहे हैं, एक मुख्यमंत्री बता दो पूरे देश में जिसने 5 साल सरकार चलाने के बाद चुनाव में जनता के बीच जाकर कहा हो भाइयों और बहनों काम किया हो तो वोट देना, नहीं तो वोट मत देना। एक सरकार बता दो?

...(व्यवधान)...

माननीया अध्यक्षः एक सेकंड।

...(व्यवधान)...

माननीय उप-मुख्यमंत्रीः एक सरकार बता दो?

...(व्यवधान)...

माननीया अध्यक्षः एक सेकंड। देखिए...

...(व्यवधान)...

माननीय उप-मुख्यमंत्रीः एक सरकार...

...(व्यवधान)...

माननीया अध्यक्षः एक सेकंड। एक सेकंड।

...(व्यवधान)...

माननीय उप-मुख्यमंत्रीः अध्यक्षा महोदय, एक सरकार बता दो,

...(व्यवधान)...

माननीया अध्यक्षः माननीय विपक्ष के साथियों से मेरा निवेदन है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके व्यवहार की तारीफ करी है। अनुशासन बनाकर रखें, उप-मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, इस तरीके से आपको बीच में बोल..

...(व्यवधान)...

माननीया अध्यक्षः हां, मैं पूरे सदन को कह रही हूँ।

...(व्यवधान)...

माननीया अध्यक्षः मैं पूरे सदन, मैं, मैं पूरे सदन को कह रही हूँ लेकिन hooting आप लोग कर रहे हैं। hooting आप लोग कर रहे हैं। मैं अब, ये वक्तव्य पूरे सदन के लिए है। लेकिन आप लोग hooting कर रहे हैं, शोभा नहीं देती ये बात।

...(व्यवधान)...

माननीया अध्यक्षः हां जी।

...(व्यवधान)...

माननीया अध्यक्षः जी।

माननीय उप-मुख्यमंत्रीः अध्यक्षा महोदय, पूरे देश में एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो किसी दूसरे राज्य में चुनाव लड़ने जाते हैं, पंजाब के लोगों को भी जाकर कहते हैं कि पंजाब के भाइयों-बहनों अपने दिल्ली के रिश्तेदारों से पूछ लो, अगर दिल्ली में काम किया हो तो वोट देना और पंजाब में भी वोट मिल गए, एकमात्र हैं।

...(व्यवधान)...

माननीय उप-मुख्यमंत्रीः तो अध्यक्ष महोदय, 5 साल पहले जो कहा सो किया को सिर्फ जुमलों की नहीं, काम की कसौटी पर खरा उतारने के लिए और कसकर देखने के लिए हमने एक नई परम्परा शुरू की इस देश की विधान सभा में, पहली बार शुरू की, आउटकम बजट। इस आउटकम बजट में हम ये बताते हैं कि

पिछले एक साल के दौरान, इसी विधान सभा में एक साल पहले जो बजट हम पास कराकर लेकर गये, सरकार पास कराकर लेकर गई उसमें जितनी योजनाएं बनाई, उनमें कौन सी कहां खड़ी है। कौन सी आगे बढ़ गई हंड्रेड परसेंट। कौन सी 80 परसेंट पर खड़ी है। कौन सी किस कारणों से शुरू नहीं हुई। सब कुछ यहां बताते हैं और ब्लैक एंड वाइट में बताते हैं। पूरे देश में कहीं नहीं होता, किसी विधान सभा में नहीं होता। किसी मुख्यमंत्री और किसी वित्त मंत्री की हिम्मत नहीं है जो अपनी विधान सभा में जाकर आउटकम बजट पेश कर दें। केवल और केवल दिल्ली सरकार ऐसी सरकार है जो पिछले 5 साल से ये बजट पेश कर रही है। वो एक हमारे बहुत, मैं एक-आध बार और भी जिक्र कर चुका हूँ, एक बड़े मशहुर शायर हुए हैं, अदम गोंडवी साहब, उन्होंने एक शेर लिखा है-

'कि जो उलझकर रह गई है फाइलों के जाल में,

गांव तक वो रोशनी पहुंचेगी कितने साल मे।'

तो सारी की सारी रोशनियां फाइलों के जाल में ही उलझी रहती हैं। और बाद में कहीं कोई पत्रकार टी.वी. में पूछ ले कि भई वो क्या हुआ तेरा वादा, तो बोलते हैं वो तो जुमला था, ऐसे ही बोल दिया था। इनको पता है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। ...(व्यवधान)...

माननीय उप-मुख्यमंत्रीः वो तो टी.वी. के इंटरव्यू में भी बोल दिया जी वो 15 लाख तो जुमले थे जी, ऐसे ही बोल देते हैं। हम ये फाइलों के जाल में नहीं फंसाते और जुमलों के जाल में नहीं फंसाते, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और जो कहा है वो आगे भी करके दिखायेंगे। हमने खुद को अकाउंटैबल बनाने के लिए ये परम्परा शुरू की ताकि इस सरकार में ये परम्परा बने कि कोई भी मंत्री, कोई भी वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री यहां से खड़े होकर योजना बनाकर, सदन के पटल पर रखकर, पास कराकर लेकर जाते हैं, उनका हुआ क्या। तो आमतौर पर 280 क्वेश्चन, उन सबमें कितने उठते हैं, कितने नहीं उठते, लेकिन असली ये है कि आउटकम बजट में एक-एक योजना रखें, एक-एक चीज रखें इसलिए मैं आज आउटकम बजट की प्रति इस सदन पर रख रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि हमारी हरेक योजना कहां, किस पायदान पर 31 दिसंबर तक खड़ी है। और पूरे देश में कहीं ये रिपोर्ट बनती हो इस तरह के आउटकम रिपोर्ट, तो बता दो मुझे, पूरे देश में?

मैं, दो शब्द हैं अध्यक्षा महोदय, इससे पहले कि मैं थोड़ा सा आउटकम की इस रिपोर्ट के बारे में और कहूँ, ये आउटपुट और आउटकम ये दो शब्द हैं, इनके पीछे का भाव क्या है कि हमने पैसा दिया यहां से, विधान सभा से हम पैसा अप्रूव कराकर ले गये किसी योजना के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए और उस योजना

या प्रोजेक्ट का आउटपुट क्या रहा और आउटकम क्या रहा। उस प्रोजेक्ट का या योजना का आउटपुट तो ये है कि उससे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदा गया, बनाया गया, उसको इंवेस्ट करके कहीं कोई बिल्डिंग बनाई गई या कहीं कोई पुल बनाया गया या कहीं कोई मशीन खरीदी गई या कोई सर्विस हायर की गई, ये उसका आउटपुट है लेकिन वो आउटकम नहीं है, आउटकम ये है कि फिर लोगों को क्या फायदा मिला। आपने मशीन लेकर खड़ी कर ली, आपने कुछ खड़ा कर लिया, आउटकम क्या मिला? तो उस आउटकम का बजट मैं लेकर आया हूँ आपके पास। अगला बजट लेकर आने से पहले। उसमें पूरी डिटेल इसमें है, एक-एक योजना की डिटेल इसमें है जो पिछले साल के बजट में थीं। हरेक योजना किस इंडिकेटर पर कहां खड़ी है उसकी पूरी डिटेल इस पूरे रिपोर्ट में है, उसकी कुछ संक्षिप्त सी जानकारी व ब्यौरा सदन के समक्ष रखना चाहता हूँ।

हमने पिछले बजट में कहा था हम नई स्कूल बिल्डिंग्स और कमरे बनायेंगे और उसके पिछले भी कुछ बजट्स में और कमरों की अप्रूवल लेकर गये थे पैसे की, 13,181 कमरे बनकर तैयार हो गये हैं। और मुझे इस सदन को ये भी बताते हुए खुशी हो रही है कि क्योंकि कमरे बढ़ गये, स्कूलों की संख्या बढ़ गई, स्कूलों के साइज बढ़ गये, वहां की सुविधाएं बढ़ गई, पढ़ाई की क्वालिटी बढ़ गई तो आज बहुत गर्व के साथ मैं आपको बताना

चाहता हूँ और इस सदन को सूचित करना चाहता हूँ कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 15 लाख से बढ़कर 18 लाख हो गई है इस समय, 3 लाख बच्चे बढ़ गये हैं, करीब-करीब 3 लाख बच्चे बढ़ गये हैं।

हमने कहा था एस.ओ.एस.ई. खोलेंगे 20, School of Specialize Excellence पिछले बजट में ये बात रखी थी कि 20 School of Specialize Excellence ने काम करना शुरू कर दिया है और 2300 बच्चे इसमें पढ़ रह हैं, ये आउटकम है इसका। इस बार हम अगले, इस साल हमने तैयारी की है 11 स्कूल और जोड़ रहे हैं और धीरे-धीरे इसकी संख्या 100 करेंगे और ये स्पेशलाइज स्कूल कितनी क्वालिटी intervention, लोगों की जिदंगी में कितना बड़ा बदलाव ला रहे हैं, पढ़ाई की क्वालिटी में कितना बड़ा intervention है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि 11 स्कूल और खुल जाएंगे, सारे मिलाकर अगले सत्र से जो शुरू होंगे 31 स्कूलों में, 4800 सीट हैं उसमें और 4800 सीटों में एडमिशन के लिए हमारे पास में 80 हजार एपलीकेशन आ गई, 80 हजार एपलीकेशन। ये किसी सरकारी स्कूल में नहीं होता। किसी सरकारी स्कूल के लिए इतनी बड़ी मांग नहीं होती।

हमने कहा था हम दिल्ली का अपना एजुकेशन बोर्ड बनायेंगे और खाली ये नहीं कि सी.बी.एस.ई. की तरह से, यू.पी. बोर्ड की तरह से या बिहार बोर्ड की तरह से एक और बोर्ड बनाकर खड़ा

कर दिया और उसमें बस बच्चे को पढ़ना लिखना आये की नहीं आये, बस पास करके टॉपर बनाकर दे दिया करेंगे, जैसा कि कई जगह होता रहता है। इस तरह का बोर्ड नहीं बनाना था। बोर्ड बनाना था कि जहां तक सी.बी.एस.ई. क्वालिटी को लेकर आया है उससे चार कदम और आगे क्वालिटी लेकर जाएंगे। और आज दिल्ली का अपना स्कूल एजुकेशन बोर्ड बन चुका है, काम करना शुरू कर दिया है, उसके अधीन कई स्कूल आ गये हैं और उसने IB curriculum, आई.बी. बोर्ड, जो इंटरनेशनल बोर्ड है, International Baccalaureate Board है, उसके साथ tie-up करके वर्ल्ड क्लास एजुकेशन पर काम करना शुरू किया है world class assessment system पर काम करना शुरू किया है और जो हमारा दिल्ली का अपना बोर्ड बना है आईबी के साथ मिल के उसमें स्कूल शामिल हो गए हैं और अब 2312 बच्चे अगले साल इसका एग्जाम देंगे और धीरे–धीरे इसका विस्तार होता रहेगा। दसवीं और बाहरवीं की परीक्षा अगले सत्र में क्योंकि नवीं और ग्याहरवीं में हमने एडमिशन लिए इस बोर्ड के तहत सीबीएसई अपने भी नवीं और ग्याहरवीं में लेता है एडमिशन। हमने भी नए बोर्ड के तहत लिए 2312 बच्चों के एग्जाम अगले साला होंगे ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। और हमने कहा था यहां सदन में देशभक्ति पाठ्यक्रम लागू करेंगे स्कूलों में। सारे स्कूलों में देश में पहली बार देशभक्ति पाठ्यक्रम लागू किया गया है और अगले साल से प्राइवेट स्कूलों में भी लागू कर दिया जाएगा और 18 लाख बच्चे लगातार रोजाना

देशभक्ति की क्लास ले रहे हैं। हमने कहा था हम business blaster का प्रोग्राम लेकर आएंगे, सारे गवर्नमेंट स्कूलों में इस बार से business blaster का प्रोग्राम लागू किया गया। ग्याहरवीं और बारहवीं में पढ़ने वाले तीन लाख बच्चों को seed money दिया गया जो इस सदन ने पास किया था। 51 हजार business ideas बच्चों ने तैयार किया और उन 51 हजार business ideas में से इतने शानदार-शानदार business ideas थे कि चारों तरफ से इन्टरनेट पर उनकी पब्लिसिटी देख-देखकर लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया और उसके top 126 ideas को लेके जब हमने exhibition लगाई और investment summit लगाया तो देश के सिर्फ और सिर्फ देखकर कि young entrepreneurs निकलकर आ रहे हैं, ग्याहरवीं-बारहवीं के बच्चों में से entrepreneurs निकलकर आ रहे हैं। तो देश-भर से मैं खुद वहां गया था कानपुर से, देहरादून से, चंडीगढ़ से, जाने कहां-कहां से उसमें investor आए थे और वहां 126 हमारे बच्चों की 126 कंपनीज् में investment हो रहा है और उसमें बड़ी चीज ये है कि हम पकौड़ा बेचने वाले की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे बच्चे जब पढ़ के जा रहे हैं तो हम उनको आगे पढ़ाने की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं बिजनेस का आइडियाज़ लाओ, सफलतापूर्वक करके दिखाओ। आप के अंदर अगर अच्छा entrepreneur बनने की क्षमता है तो हम आपको आगे उसी की पढ़ाई कराएंगे और देश की top universities में कराएंगे तो हमारे जो ये बच्चे इन 126 कंपनियों को बनाने वाले निकले हैं, इन 126 कंपनियों को startups को

बनाने वाले बच्चों को आगे की पढ़ाई भी मिल सके और entrepreneurship में ही मिल सके, मैनेजमेंट में ही मिल सके इसके लिए हमने DTU, IGDTUW, IP University, NSUT जैसी world class universities में जहां बच्चे पढ़ने के लिए बड़े बड़े competition देते हैं, बड़ी बड़ी कोटा जा के तैयारियां करते हैं कि मेरा एडमिशन डीटीयू में हो जाए। आज मैं गर्व के साथ बता रहा हूँ कि इन सारी यूनिवर्सिटीज में हमारे यहां 673 एडमिशन सीट्स हमने business blaster के बच्चोंलिए बनाई हैं कि business blaster के competition में जो बच्चे बढ़िया perform करेंगे उनमें से 673सीट्स आईपी यूनिवर्सिटी, डीटीयू, आईजीडीटीयूडब्लयू, एनएसयूटी इन सारी यूनिवर्सिटीज में जो दिल्ली की state universities हैं इसमें एडमिशन मिलेगा सीधे। उनको फिर कोई competition देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे इसमें एडमिशन हो जाएगा। डीटीयू जैसी यूनिवर्सिटी में और इसमें अगले साल से business blaster का प्रोग्राम अभी हमने केवल गवर्नमेंट स्कूल में किया था, अगले साल से हम इसको प्राइवेट स्कूलों के बच्चों के लिए भी करेंगे क्योंकि देश को नौकरी देने वाले चाहिएं, नौकरी मांगने वालों से खाली काम नहीं चलेगा और नौकरी देने वाले प्राइवेट स्कूलों से भी निकल कर आएंगे और गवर्नमेंट स्कूलों से भी निकलकर आएंगे, तो इसको हमने शुरू कर दिया है। हम इस सदन में पास करा कर ले गए थे कि देश के mentor programme शुरू करेंगे। सारे स्कूलों में शुरू हुआ। देश के 50 हजार नौजवानों ने, बहुत रोकने की कोशिश की इसको तरह

तरह की इधर उध्र के ऑब्जेक्शन लगाने की कोशिश की लेकिन 50 हजार पढ़े-लिखे नौजवान आगे आए और उन्होंने एक लाख बच्चों को ग्याहरवीं, बारहवीं के हमारे एक लाख बच्चों को mentoring की है गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ने वाले, उनका बड़ा भाई, उनकी दीदी बन के। हायर ऐजुकेशन में हमने कहा था हम sports university ले के आएंगे। मुझे बहुत खुशी है कि पिछले साल इसका बजट पास कराकर आपसे ले गए थे इसके infrastructure पर काम शुरू हो गया है और इसका एक city campus बना के तैयार कर दिया है और इस साल से माने next academic session से इसमें करीब 250 budding sports person जिनको आगे आने वाले समय में हम Olympian के रूप में भी देख सकते हैं। उस तरह के ढाई सौ budding sport persons को अगले साल से एडमिशन देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसी तरह से पिछले साल हमने इसी सदन से teachers university का बिल भी पास किया था और इसका बजट भी पास करा के ले गए थे। इसका बिल पास करा के एक्ट बन गया, नोटिफाई हो गई। इसका बक्करवाला में campus identify कर लिया गया जहां पर infrastructure का काम शुरू हो रहा है और सिटी कैम्पस इसका शुरू हो गया है और इस पर भी अगले साल से एडमिशन शुरू हो जाएगा टीचर्स बनाने के लिए। हमने merit cum means scholarship का बजट पास कराया था यहां से। पिछले साल हमने 3700 बच्चों को merit cum means में गरीब परिवारों के बच्चों को आर्थिक मदद की थी। इस बार हमने सात

हजार बच्चों को उनके इंजीनियरिंग, मैडिकल और इन सब पढ़ाइयों के लिए मदद की है 48 करोड़ रूपये की राशि यहां से दी गई है। technical education में Delhi Skill and Entrepreneurship university की स्थापना की गई थी उसका बजट हम यहां से पास करा के ले गए थे। उसके 15 कैम्पस में पढ़ाई शुरू हो गई है। 6300 (छह हजार तीन सौ) बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं और 11 कैम्पस अगले साल से शुरू कर देंगे काम करना और उसमें भी ढाई हजार बच्चों के लिए और सीट फुल जाएंगी। तो इस तरह से करीब साढे सात हजार, साढे सात आठ हजार बच्चों के लिए नए पढ़ाई के अवसर स्कूल के बाद के खुल गए हैं। हमने पिछली बार यहां प्रस्ताव रखा था कि दिल्ली में योग को popular बनाने के लिए योगशाला चलाएंगे और दिल्ली की योगशाला का पूरा प्रोग्राम चल रहा है तीन सौ सत्तर केन्द्रों पर करीब नौ हजार लोग रोजाना सुबह दिल्ली सरकार के द्वारा हायर किए गए। instructors दिल्ली सरकार के द्वारा train किए गए और हायर किए गए instructors से योग कर रहे हैं। योग और yoga meditation सीख रहे हैं। योग इस तरह से आगे बढ़ेगा। योग, खाली योग की बात करने से आगे नहीं बढ़ेगा। हमने मोहल्ला क्लीनिक की बात की थी 520 मोहल्ला क्लीनिक functional हैं और इसी साल मैं चाहूँगा कि सभी साथी इस डेटा पर ध्यान दें। इसी साल एक करोड़ 44 लाख मरीज मोहल्ला क्लीनिक्स में देखे गए हैं उनको दवाईयां दी गई है। उनका ईलाज किया है। हर महीने साठ हजार मरीज, करीब करीब 60

हजार मरीज per day इन मोहल्ला क्लीनिक में देखे जा रहे हैं। इसमें हमने अध्यक्षा महोदया, सिर्फ ये नहीं कि कितने शुरू हो गए, कितने मरीज देख लिए गए, सरकार इस बात को लेके भी concerned है। केजरीवाल जी इस बात को ले के निरंतर चिंत्ति रहते हैं कि मोहल्ला क्लीनिक्स और जितने initiative हैं सबमें quality काम होता रहे। तो इस बार के outcome budget से हम इसमें ये परंपरा शुरू कर रहे हैं कि हम जितनी स्कीम्स लेकर जा रहे हैं और खास तौर से मोहल्ला क्लीनिक जैसी स्कीम, इसका हम सर्वे भी कराएंगे तो हमने ये शुरूआत की है कि हर तीन महीने में मोहल्ला क्लीनिक की quality survey किया जाएगा। मोहल्ला क्लीनिक में आने वाले लोगों से बात करके और इस पिछले तीन महीने के सर्वे कराया हमने यहां आने से पहले, ढाई हजार मरीज जो मोहल्ला क्लीनिक में गए आ के गए उन से कॉल पर फीड बैक लिया गया। 85 percent मरीजों ने बताया कि उनको मैक्सिमम बीस मिनट समय लगा मोहल्ला क्लीनिक में इतना शानदार व्यवस्था वहां पर है। 90 percent जिन ढाई हजार लोगों को कॉल किया ओवरऑल सैटिस्फैकशन रेट 90 परसेंट का है। इससे हमें एक एक क्योंकि ये जो डेटा है जो हम सर्वे करा रहे हैं फीड बैक सर्वे करा रहे हैं। इससे हमें एक एक मोहल्ला क्लीनिक के बारे में पता चलता रहेगा सरकार को कि कौन सी मोहल्ला क्लीनिक में कौन डाक्टर या कौन अटेंडेंट या कौन सी व्यवस्था गड़बड़ हो रही है तो हर तीन महीने में अब ये सर्वे हम कराते रहेगें, मोहल्ला

क्लीनिक का। हॉस्पिटल्स में भी हमने ये परंपरा शुरू की है। हमने इस सदन से बजट लिया था और हमने कमिट किया था दस हजार बिस्तरों की संख्या बढाएंगे बेड्स की दस हजार बैड से बढ़ा के 13844 (तेरह हजार आठ सौ चवालिस) बेड्स हो गए हैं दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में। इसमें भी हमने फीडबैक की परम्परा शुरू की है क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट की डे-टू-डे की फीडबैक लेनी बहुत जरूरी है तो हर एडमिशन महीने में अब से हेल्थ डिपार्टमेंट में और सरकारी अस्पतालों का भी इसी तरह से फीडबैक लिया जाएगा और पिछले तीन महीने में 2200 पेशंट्स का सर्वे किया गया, 77 परसेंट ओवरऑल सैटिस्फैकशन है। कोविड इंप्रफास्ट्रक्चर में क्योंकि कोविड का साल था पिछला साल भी और अभी भी कहीं न कहीं हवा में तो बात होती है। हो सकता है ईश्वर न करे लेकिन हम को तो तैयार रहना ही रहना है। पिछली बार जब हम आए थे तो 3,865 बेड्स थे आक्सीजन के, पिछले एक साल में हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट और पीडब्ल्यूडी और तमाम लोगों ने मिल कर, मेहनत करके सरकार ने 9,243 आक्सीजन बेड्स हो गए हैं। 3,865 बेड से बढ़ के आक्सीजन बेड से बढ़कर संख्या सरकारी अस्पतालों में परमानेंट आक्सीजन बेड्स हैं अब ये, कोविड और नॉन कोविड के लिए infrastructure बन गया है लेकिन आक्सीजन बेड्स 9,243 हो गए हैं। 534 आईसीयू बेड्स थे, इनकी संख्या बढ़कर अब 2,091 हो गयी है। अध्यक्षा महोदय, कोविड की एक बात होती है तो वैक्सीन की भी होती है और

जब वैक्सीन की बात होती है तो तुरंत वहां से नारा लगने लगता है। मैं बताता हूँ कि दिल्ली में 100 परसेंट वैक्सीन फर्स्ट डोज लग चुकी है, 90 परसेंट वैक्सीन सेकिंड डोज एडल्ट्स को लग चुकी है, 70 परसेंट टीन्स को दोनों डोजिज लगाई जा चुकी हैं और ये highest in India है। पूरे देश में सबसे ज्यादा है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उनसे भी और जहां किसी और पार्टी की सरकार है उनसे भी ज्यादा है। तो मैं इनको कहना चाहता हूँ ये बात ठीक है शुरू में मोदी जी विदेशों को वैक्सीन भेज रहे थे फिर जब शोर मचाया तो देश के लिए भी देना शुरू किया, मोदी जी वैक्सीन दे जरूर रहे हैं लेकिन लगवा नहीं पा रहे, लगवा तो केजरीवाल जी पा रहे हैं। तो मैं बीजेपी वालों को भी कहना चाहता हूँ कि देखो मोदी जी वैक्सीन दे देंगे लगवाएंगे नहीं, लगवाएंगे तो केजरीवाल जी। आपके बच्चों को भी वैक्सीन इसलिए लग पाई क्योंकि केजरीवाल जी हैं। खाली मोदी जी के भरोसे रहते तो बिना वैक्सीन के रह जाते। देख लो हरियाणा वालों को जाकर, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी नहीं लगी अभी तो। तो अध्यक्षा महोदय, ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए बहुत नई शुरूआत सरकार ने की है देश में पहली बार अगेन कि पहली बार किसी सरकारी काउंटर को जहां सरकार से कोई सुविधा लेने के लिए लोगों की लाइन लगती थी उस काउंटर को ऑनलाइन कराने की तो बड़ी बात होती थी लेकिन बाहर दलाल बैठे रहते थे क्योंकि वो खिड़की है तो बाहर दलाल है और दलाल है तो सारी ऑनलाइन बेकार है।

तो इसलिए अरविंद केजरीवाल जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जाकर पहली बार देश में लाइन लगने वाली किसी खिड़की को जाकर केजरीवाल जी ने ताला लगाया। सरकारी सिस्टम में जहां जहां गुंजाइश होती है भ्रष्टाचार की उसको ताला ही लगा दो, बंद कर दो। फेसलेस सर्विसिस कि ये खिड़की नहीं होगी तो खिड़की के बाहर दलाल भी नहीं बैठेगा। तो 5 लाख लोगों ने अगस्त में शुरू की थी ये, अगस्त से लेकर क्योंकि ये रिपोर्ट मैं 31 दिसम्बर तक की दे रहा हूँ, अगस्त से लेकर दिसम्बर तक इसका 5 लाख लोग फायदा उठा चुके हैं। महिलाओं के लिए फ्री यात्रा का बजट इस सदन से पास कराकर ले गए थे, तीन करोड़ पिंक टिकट यानि कि तीन करोड़ यात्रएं महिलाओं ने, हमारी बहनों ने की। इलेक्ट्रिक व्हीकल, ई-व्हीकल की पॉलिसी में हमने टारगेट रखा था कि हम 2024 तक हमने 2019 में ये टारगेट रखा था इस सदन के समक्ष कि हम 5 साल के अंदर अंदर दिल्ली में आने वाले नए वाहनों में 25 परसेंट ई-व्हीकल खरीदे जाएं इसका टारगेट लेकर चल रहे हैं। जब हमने ये कहा था तो जुमला पार्टी को ये लगा था जुम्ला दे रहे होंगे। जुम्ला पार्टी वालों को यही लगा था कि ये जैसे इनकी पार्टी के लोग जुम्ले मारते हैं और बाद में कह देते हैं जुम्ले हैं इनको लगा होगा ऐसे ही जुम्ले होंगे लेकिन 2 साल के अंदर अंदर आउटकम देखिए, हमारा आउटपुट जुम्ला नहीं होता, जुम्लों का महल नहीं बनाते, हमारा 2 साल के अंदर अंदर दिल्ली में हमने कहा था 5 साल में 25 परसेंट का टारगेट हासिल करेंगे। दो साल

के अंदर-अंदर 10 परसेंट का टारगेट हासिल किया जा चुका है। दिल्ली में खरीदे जाने वाले नए वाहन जितने भी नए व्हीकल्स खरीदे जा रहे हैं आज की तारीख में उनमें से 10 परसेंट ई-व्हीकल खरीदे जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। देश में नहीं ये दुनिया में बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप तो हाथ में पकड़कर चार्ज कर लोगे, आपको क्या टेंशन है। नाले से गैस बनती है नाले में पाइप डालो तो गैस बन जाती है आपके यहां पर, चाय गर्म हो जाती है आपकी। इसीलिए एमसीडी के नाले भरकर रखते हैं। अध्यक्षा महोदय, महिला विभाग के लिए मैं खुशी से बताना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार विमन इन डिस्ट्रेस के साथ हमेशा कदम से कदम मिलाकर खड़ी रहती है परिवार की तरह से। मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल जी हमेशा एक परिवार के बड़े भाई की तरह से खड़े रहते हैं। दिल्ली में ढ़ाई लाख महिलाओं को विमन इन डिस्ट्रेस की स्कीम का फायदा मिल रहा था उनकी संख्या बढ़कर अब 3 लाख 10 हजार हो गई है। उनको पेंशन जो मिलती है और जो सहायता मिलती है। पीडब्ल्यूडी में हमने कहा था 500 फ्लैग्स लगाएंगे आजादी के 75वें वर्ष पर, 15 अगस्त से इसको शुरू करेंगे और अगले 15 अगस्त तक लगा देंगे। ये पूरा प्रोग्राम बहुत ट्रेक पर चल रहा है कोविड और इन सबके लॉकडाउन के बीच भी कुछ स्लो हुआ बीच में लेकिन फिर से स्पीड पकड़ गया है और अभी तो 125 फ्लैग लगे हैं पूरी दिल्ली में as on today. 125 फ्लैग लगने से ही दिल्ली में ऐसा माहौल हो गया है

कि आप गाड़ी से 2-3-4 किलोमीटर कहीं जाओ विजयी विश्व जीत तिरंगा प्यारा हमारा 3-4 जगह तो लहराता हुआ दिख जाता है और मन में भाव ये ही आता है कि इस तिरंगे के लिए लोगों ने इतनी जान दी इतनी कुर्बानी दी बस उसको सैल्यूट करके निकल जाने का मन करता है। तो 125 जगह लगाया जा चुका है और 30 अप्रैल तक 200 का टारगेट है और 15 अगस्त यानि कि आजादी के 75वें साल पूरे होते-होते पूरे 500 फ्लैग्स पूरी दिल्ली में लहराने लगेंगे अभी तो 125 का ही कमाल दिख रहा है पूरी दिल्ली तिरंगामयी हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, डेढ़ लाख सीसीटीवी लगाने का टारगेट रखा था, दिसंबर तक 1 लाख 33 हजार सीसीटीवी।

...(व्यवधान)...

माननीय उप मुख्यमंत्रीः अब आप रूकवाओ, रोकने वाले हैं ये तो सीसीटीवी लगवाने वाले कहां है। 1 लाख 33 हजार सीसीटीवी लगवाए जा चुके हैं और टोटल 2 लाख 75 हजार सीसीटीवी लगवाए जा चुके हैं। पूरी दिल्ली में 2 लाख 75 हजार।

माननीया अध्यक्षः झूठ के पुलिंदे का।

माननीय उप मुख्यमंत्रीः अध्यक्षा महोदय, 2 लाख 75 हजार सीसीटीवी पूरी दिल्ली में लगवाए जा चुके हैं। ये इनके नेता भी ढूँढ रहे थे मैं बता देता हूँ इसका जवाब देता हूँ। इनके नेता इनके एक बहुत बड़े नेता है अध्यक्षा महोदय सुन लीजिए।

माननीया अध्यक्षः सुन लीजिए अगर आपके यहां नहीं लगा आप लिखकर दे दीजिए लगवा दिए जाएंगे। अभी बहुत बड़ा उदाहरण आ रहा है सुनिए।

माननीय उप मुख्यमंत्रीः इनके एक महामहिम नेता है अध्यक्षा महोदय, आप इधर ध्यान दीजिए आप उनको कहने दीजिए।

माननीया अध्यक्षः शांति बनाए रखें।

माननीय उप मुख्यमंत्रीः उनको छोड़ दीजिए वो अशांत है दिल से अशांत है बेचारे क्या करे रात को पोस्टर कम लगे, पोस्टर की लई कम पड़ गई थी बेचारों की। पोस्टर की लई कम पड़ गई थी, बेचारे क्या करे दुखी हैं। रात को सोने नहीं देते इनको फिल्मों वाले, बोले हमारे पोस्टर लगाओ, हमारे पोस्टर लगाओ दिहाड़ी नहीं मिलेगी खैर। अध्यक्षा महोदय, इनके एक बहुत बड़े नेता ने दिल्ली में देश के गृहमंत्री जी है वो। उन्होंने बयान दिया मैं दूरबीन लेकर सीसीटीवी कैमरे ढँढ रहा हूँ। मैंने कहा गृहमंत्री जी सीसीटीवी गलियों में लगे होते हैं आसमान में नहीं, दूरबीन की जगह नंगी आंखों से देख लेते तो उसी गली में दिख जाते जिसमें आप घूम रहे थे और मैंने ये 2 लाख 75 हजार जो सीसीटीवी लगाए हैं 2 लाख 75 हजार में से ही जिस गली से वो निकले एक मिनट-एक मिनट 2 लाख 75 हजार सीसीटीवी जो लगाए गए पूरी दिल्ली में उसी में से कुछ सीसीटीवीज में जहां से गृहमंत्री जी निकले वहीं उनकी फुटेज कैद हो गई। मैंने कहा आपके केजरीवाल

सरकार के लगाए सीसीटीवी में गृहमंत्री जी की फुटेज पूरी तरह से है ये रही वो सीसीटीवी है। वो दूरबीन लेकर आसमान में ढूँढते रहे जमीन पर सीसीटीवी लगे थे लाजपत नगर में। तो ये तो दूरबीन लेकर अपने नेता की तरह आसमान में सीसीटीवी ढूंढ रहे हैं, वहां तो मिलेंगे नहीं सड़कों पर मिलेंगे, गलियों में मिलेंगे।

...(व्यवधान)...

माननीय उप मुख्यमंत्री: ये अजेश भाई अच्छा बता रहे हैं। इनकी प्रोब्लम ये हैं कि ये शिक्षा से कोई लेना-देना है नहीं इनको पता नहीं सीसीटीवी क्या होता है और वाई-फाई क्या होता है। सीसीटीवी के बक्से के नीचे खड़े होकर कहते हैं वाई-फाई नहीं चल रहा है। वाई-फाई के नीचे खड़े होकर कहते हैं सीसीटीवी में फुटेज में फोटो नहीं आ रही। तो अध्यक्षा महोदय, 2 लाख 75 हजार सीसीटीवी पूरी दिल्ली में लगाए जा चुके हैं और पूरी दुनिया में सीसीटीवी का इतना डेंस नेटवर्क कहीं नहीं है जितना यहां है खुद पफोर्ड कीरिपोर्ट कहती है। वाई-फाई 10,500 स्पोट्स वाई-फाई के स्पोट्स पूरी दिल्ली में लग चुके हैं पिछले एक साल में 2 हजार स्पोट्स अध्यक्षा महोदय इस सरकार की ओर से लगाए गए हैं। तो मैं आपके समक्ष ये आउटकम सरकार का कुछ मोटी चीजें इसमें रखी और पूरा का पूरा पुलिंदा हमने इसमें रखा है जहां हमने किया वहां भी, जहां हम पीछे रहे गए, जहां हम बीच में है हर चीज हमने यहां पर रखी है और मुझे बहुत खुशी है फिर से कहता हूँ

कि केवल और केवल अरविन्द केजरीवाल जी नाम के मुख्यमंत्री में हिम्मत है पूरे देश में जो खुलकर कहता है ये किया था और ये नहीं किया था, ये कर पाए है और ये नहीं कर पाए हैं, इस पर मेहनत कर रहे हैं यह अटक गया है। केवल और केवल एक मुख्यमंत्री है पूरे देश में इनकी पार्टी का उनके पुरखों की पार्टी का, उनके पुरखों की पार्टी पता है न कौन थी। इनकी पार्टी और इनके पुरखों की पार्टी का एक भी मुख्यमंत्री ऐसा नहीं है जो खुलकर ये कह दे कि मैं आउटकम बजट दे रहा हूँ हम दे रहे हैं हम आउटकम बजट दे रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्षा जी।

माननीया अध्यक्षः बहुत-बहुत धन्यवाद और जहां तक सीसीटीवी की बात है तो अभी भाजपा के बड़े नेता का मोबाइल स्नैच हुआ था रेड लाइट से वो सीसीटीवी की फुटेज से ही मिला था। वो सीसीटीवी की फुटेज से ही मिला था और दूसरी बात मैं बोल रही हूँ न, अभी मैं बोल रही हूँ शर्मा जी अभी मैं बोल रही हूँ।

...(व्यवधान)...

माननीया अध्यक्षः मैं आप ही के फेवर में कोई बात कह रही हूँ मैं आपके लिए ही कोई बात कह रही हूँ जिस भी साथी को सदन में ऐसा लगता है कि कम कैमरे लगे हैं, बिल्कुल भी नहीं लगे वो लिखकर दे दीजिए। वहां पर जल्दी से जल्दी लगवाने का कार्य करेंगे। उप मुख्यमंत्री जी को लिखकर दे दीजिए।

...(व्यवधान)...

माननीया अध्यक्षः चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

...(व्यवधान)...

माननीया अध्यक्षः आप लिखकर दे दीजिए आपका जो भी विषय है, जो भी आपको लगता है आप लिखकर दे दीजिए। लिखकर दे दीजिए-लिखकर दे दीजिए। रोहित कुमार जी धन्यवाद प्रस्ताव पेश करेंगे।

श्री रोहित कुमारः धन्यवाद माननीय अध्यक्षा जी, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर या कहे लोगों की जिंदगी और सम्मान से जुड़े हुए मुद्दे पर मुझे धन्यवाद प्रस्ताव पेश करने का अवसर दिया। दिल्ली के ओजस्वी मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल जी ने 'जहां झुग्गी वहीं मकान' योजना को लेकर उच्चस्तरीय बैठक की है जिसमें सख्त हिदायत देकर अधिकारियों को इस योजना को अगले 3 साल में पूरा करने के सख्त आदेश जारी किए हैं जिसके लिए मैं तमाम अपनी विधान सभा के झुग्गी बस्ती में रहने वाले बहन-भाईयों की ओर से दिल्ली के सभी क्षेत्रें में विधान सभाओं में रहने वाले झुग्गी बस्तियों में रहने वाले बहन-भाईयों की ओर से हार्दिक धन्यवाद और शुक्रिया मैं अदा करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल जी के लिए कि जिन्होंने लोगों के जीवनस्तर को सुधारने के लिए और बेहतर जीवन उनको देने के लिए जहां झुग्गी वहीं मकान योजना को अंतिम रूप देने के लिए इतना साहसिक कदम उठाया है। माननीय अध्यक्षा जी, बाबा साहब

डाक्टर अम्बेडकर जी ने हमारे संविधान के अंदर सभी देशवासियों को सभी नागरिकों को अधिकार दिया है राइट टू लिव न केवल जीने का अधिकार बल्कि इस पूरे सम्मान के साथ में जीने का अधिकार और इसी के तहत अरविन्द केजरीवाल जी ने एक बार फिर इस बात को चरितार्थ किया है कि वे सचमुच में गरीबों के मसीहा है। इस योजना के तहत दिल्ली के लगभग 78 हजार परिवारों को पक्के मकान दिए जाएंगे बिजली, पानी और अन्य तमाम मूलभूत सुविधाओं के साथ में ये मकान उनको दिए जाएंगे, जहां पर झुग्गी बस्ती है उसके समीप ही मकान बनाए जाएंगे और अगले तीन साल में इस काम के लक्ष्य को पूरा भी कर लिया जाएगा।

माननीया अध्यक्षः चलिए धन्यवाद।

श्री रोहित कुमारः पहले चरण में मैं थोड़ी सी बात कहकर मैं।

माननीया अध्यक्षः धन्यवाद-धन्यवाद।

श्री रोहित कुमारः 5 मिनट और लूंगा क्योंकि कुछ।

माननीया अध्यक्षः धन्यवाद प्रस्ताव तो दो लाइनों का होता है बस।

श्री रोहित कुमारः दो लाइन का होता है लेकिन आपकी और मेरी जिंदगी और हमारे परिवारों से जुड़ा एक है विषय और इसमें पहले चरण में 16 हजार लोगों को मकान दिए जाएंगे। मैं बस इस

पर प्रकाश थोड़ा डालना चाहता हूँ कि आखिर ये योजना क्यों हैं, क्यों इसकी जरूरत है और यहीं नहीं हर जगह। माननीय अध्यक्षा जी, 1976 में त्रिलोकपुरी कालोनी बसाई गई थी जहां का मैं बाशिंदा हूँ मेरा जन्म 1976 में हुआ था जिस समय ये कालोनी बसाई गई थी। त्रिलोकपुरी एक पुर्नवास कालोनी है। दिल्ली के पंचकुइयां रोड से वहां पर झुग्गी बस्ती को वहां पर बसाया गया था। मैं कहूँगा कि बसे तो हम पहले से थे उस समय की त्तकालीक सरकार ने उजाड़ा था और तमाम इलाकों से और भी इलाकों से वहां पर झुग्गी बस्तियां पहुंची। मैं उस वक्त अपनी मां के गर्भ में था कि जिस वक्त ये कालोनी बसी थी ट्रकों में लादकर वो सामान बांस-बल्लियां अन्य सामान लेकर हम जब वहां पर हमारा परिवार पहुंचा। मेरी मां जब बताती है आज भी उसकी आंखें भर आती है कि कैसी मुश्किलातों का सामना करना पड़ा कि वहां पर वो कटे हुए खेत वहां पर एक खुला मैदान खुले आसमान के नीचे वहां पर छोड़ दिया गया था और वहां पर कोई सुविधाएं नहीं थी न वहां पर टॉयलेट्स थे, न वहां पर सड़क थी, न वहां पर बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल थे। तो इस तरह की जब योजनाएं बिना सोचे समझे बना दी जाती है तो लोगों को एक तरह से उजाड़ने का काम किया जाता है और बाद में धीरे-धीरे आज त्रिलोकपुरी जैसी अन्य कालोनियां भी है मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, दक्षिणपुरी जो उस समय 80 के दशक में बसाई गई थी। तमाम उन लोगों ने त्रिलोकपुरी वासियों ने इस तरह की परेशानियों को

सहा, न कोई यातायात का साधन था, न कोई अस्पताल था। अगर कोई बीमार उस समय हो जाता था तो उनको नई दिल्ली के किसी अस्पताल में इलाज के लिए जाना पड़ता था। बिजली आने में दशकों लग गए, पानी आने में सीवर आने में दशकों लग गए। तो ये धीरे-धीरे लोगों ने अपने आप अपने परिवार को फिर से बसाया और सबसे बड़ी बात आज हमारी सरकार शिक्षा पर काम कर रही है।

माननीया अध्यक्षः बहुत-बहुत धन्यवाद रोहित जी बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रोहित कुमारः एक सेकेंड आखिर में कहूँगा कि।

माननीया अध्यक्षः अल्ककालिक चर्चा नियम-55 के तहत दिल्ली के नगर निगम चुनावों में होने में जो विलंब हो रहा है संजीव झा जी चर्चा प्रारंभ करेंगे।

श्री संजीव झाः बहुत-बहुत धन्यवाद स्पीकर मैडम कि आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज चर्चा कराने और मुझे बोलने का मौका दिया क्योंकि आज जो विषय है ये विषय कोई सामान्य विषय नहीं है। आज का विषय इस देश में किस तरह से legislative process को विधायी प्रक्रिया को संविधान को किस तरह से दरकिनार किया जा रहा है उसका एक उदाहरण भी है। मैं उसको उसमें डिटेल में जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा

कि 15 साल से दिल्ली में दिल्ली के नगर निगम में बीजेपी की सत्ता है और नगर निगम में किस तरह की लूट है ये दिल्ली की एक-एक जनता आपको बता देगी। दिल्ली के नगर निगम से लोगों को फायदे क्या हैं कोई एक नहीं बता पायेगा लेकिन लूट क्या है ये सब बता देंगे। कई बार हमारे विपक्ष के साथी भी इस मुद्दे को उठा चुके हैं। ये लूट का नुकसान इनको भी झेलना पड़ता है ये भी कई बार कह चुके हैं तो जब 15 साल से निगम में अराजकता हो 15 साल से एक पार्टी की सरकार हो और सरकार लोगों का शोषण का काम करे, हर बार चुनाव में नये-नये वायदे किये जाते हैं एक भी वायदा पूरा नहीं होता। पांच साल पहले जब चुनाव हो रहा था तो उन्होंने कहा था 'नये चेहरे नई उड़ान' और वो जितने भी नये चेहरे हैं। आज सब भ्रष्टाचार में डूबे हुये हैं। दिल्ली की जनता बहुत गुस्से में थी, दिल्ली की जनता इस लूट के चिालाफ खड़ी थी। दिल्ली में हर पांच साल में चुनाव होगा ये संविधान की प्रक्रिया है भई Article 243U ये कहती है कि वर्तमान जो existing आपका municipality है उसके रहते हुये आप चुनावी प्रक्रिया पूरी करके नया आप निगम बनायेंगे लेकिन आनन-फानन में एक केन्द्र सरकार से चिट्ठी आती है Election Commission ये कहता है कि आज चुनावी अधिसूचना जारी होगी। पांच बजे का press conference तय होता है चार बजे चिट्ठी आती है और पांच बजे के press conference में ये election Commissioner कहते हैं कि केन्द्र सरकार से ये आदेश आता है कि अभी चुनाव नहीं

होगा। चुनाव क्यों नहीं होगा इसकी चर्चा नहीं थी, क्या कारण है इसकी चर्चा नहीं थी। तो हालांकि वो जो आदेश आया था वो आदेश भी असंवैधानिक था लेकिन आखिर ऐसी मजबूरी कौन सी थी। मैं एक क्षेत्र का विधायक हूँ, मैं बुराड़ी विधानसभा का विधायक हूँ। हमारे यहां 6 निगम पार्षद हैं अब समझिये लूट किस तरह की होती है मैं एक वाकया बताता हूँ आपको बड़ा interesting है सदन को भी जानना चाहिये और दिल्ली की जनता को भी जानना चाहिये। हमारे यहां unauthoirise colony है unauthorise colony कोई proper housing नहीं है तो जो वोट डाला जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि एक मकान का एक फ्लोर का वोट किसी और का किसी और बूथ पर और दूसरे फ्लोर का वोट किसी और बूथ पर। एक ही खसरा का एक मकान किसी और पोलिंग सैन्टर पर दूसरे का किसी और पोलिंग सैन्टर पर। तो एक बार एक जगह कोई मकान बन रहा था तो कई बार वहां जब कोई नया मकान बनता है तो ये संवैधानिक अधिकार पार्षद मानते हैं कि मैं पैसा लेना है कि नया मकान बनाया पैसे कैसे नहीं दोगे, पैसा तो देना पड़ेगा आपको, unauthorised colony है उनको डराते हैं। हालांकि कई बार मैं कहता भी हूँ कि मान लीजिये नया मकान बनाया है, किसी घर में शादी हो, बच्चा हो तो मांगने वाला कोई और आता था भगवान ने उनको बनाया था मांगने के लिए। दिल्ली में दिल्ली के पार्षद वो कैसे हो गये, मुझे आज तक समझ में नहीं आया, हैना, झूठ तो नहीं कह रहा ना। भई नया मकान बनाया तो

अधिकार है मेरा पैसे लेने का भगवान ने किसी और का अधिकार दिया था वो अधिकार पार्षद छिनकर ले गये खैर, खैर मैं अब देखिये बड़ा interesting वाकया है तो एक वार्ड के पार्षद खसरा नम्बर लेकर आये कि ये जो मकान बन रहा है इसका पैसा मुझे मिलना चाहिये, दूसरा पार्षद वोटर लिस्ट लेकर आ गया कि नहीं ये मेरा वोटर है मुझे मिलना चाहिये दोनों में लड़ाई हो गई और लड़ाई इतनी भयानक हुई कि उसकी पंचायत विधानसभा में नहीं हुआ फिर वो हमारे अपने सांसद जी के पास गये कि ऐसे-ऐसे मकान बन रहा था मेरे वोटर लिस्ट में पैसे वो ले रहे हैं दूसरे ने कहा नहीं-नहीं खसरा मेरा है पैसा मुझे मिलना चाहिये। सांसद ने कहा कि मैं तेरी पंचायत नहीं करूंगा तुम बेईमान निकले मेरा हिस्सा कहां है, मैं तेरी पंचायत नहीं करूंगा ये तो पोल आज खुला कि ये मकान बनने पर तुम लोग मुझे नहीं बताते हो। अगर ये लड़ाई नहीं होती तो जानकारी मुझे नहीं मिलती। तो सांसद जी नाराज, अब वो गये प्रभारी के पास जो दिल्ली के प्रभारी हैं उसने निर्णय लिया कि इस तरह का अगर कोई झगड़ा होगा तो दोनों मैं बराबर-बराबर बंटेगा ऐसा नहीं कि कोई एक खा जायेगा। अब समझिये कि लूट की शुरूआत कहां से होती है और ये पहुंचती कहां तक है तो ये हाँ बिल्कुल ऐसे चार वाकया हैं, ऐसे चार वाकया हैं हमारे विधानसभा में। एक जगह कोई कॉलोनी बन रहा था तो एक पार्षद पहुंच गया वो भी दो वो तो अलग पार्षद हैं वो दोनों पहुंच गया बोला कि ये मेरी बाउंडरी है, वहां मेरी

बाउंडरी है दोनों में भयानक लड़ाई हुई, कहा कि नहीं एक–एक थोड़ा ज्यादा था एक थोड़ा कम था बस 70 परसेंट तुम्हारा 30 परसेंट हमारा। ये लूट एम.सी.डी. में भाजपा के लोगों ने किया है स्पीकर मैडम। तो जब इस तरह का लूट हो तो दिल्ली की जनता ने ठान लिया था कि सबक सिखाऊंगा। एक और वाकया बताऊं बड़ा interesting है। मैं एक मैं एक जगह गया मैं किसी तेरहवीं में गया तो वहां एक पार्षद आये बोले देखो जी मैं ना कोई अगर 50 गज 100 गज मकान बनाये मैं किसी से पैसा नहीं लेता, हमने कहा हाँ–हाँ बोला मेरी ईमानदारी है हमने कहा हाँ–हाँ पार्षद जीकी ईमानदारी तो बहुत है ये बात तो है कि पार्षद जी बहुत ईमानदार हैं। बोला ये और बात है कि कोई कर्मिशियल बनाये उसको में नहीं छोड़ता हूँ। तो हमने कहा पार्षद जी फिर ये ईमानदारी कैसे हुई, हाँ ये कहिये कि आपकी बेईमानी का स्टेन्र्ड है बाकी नीच बेईमान हैं आप स्टेन्र्ड बेईमान हैं कि आप कर्मिशियल केवल लेते हैं बाकी सब ले लेते हैं। तो इस तरह की लूट एम.सी.डी. में भाजपा के पार्षदों ने किया है। अब ये नई चेहरे नई उड़ान के नाम पर इन लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं को नौकरी देने का काम करते हैं कि इस बार इसको लड़ाओ ये पैसे वाला बन जायेगा इसको सबको बतायेगा लूट हो रहा है और लूट का सब हिस्सेदार हैं सब जगह बंट रहा है तो जब इस तरह की अराजकता थी तो दिल्ली की जनता बहुत परेशान थी बहुत नाराज है उनको सबक सिखाना है इस बार, दिल्ली की जनता ने ठान लिया था। हमारे

सर्वे में भी कह रहे थे हम लोग सर्वे करा रहे थे कहते हैं कि 270 में से 270 सीट कहीं आम आदमी पार्टी को ना आ जाये, सर्वे इन्होंने भी कराया, इनको लगा मेरा सुपड़ा साफ होने वाला है, तो कहा कि इलैक्शन ही टाल दो। देखिये अध्यक्ष महोदय मैं बहुत गंभीर बात आपको कहना चाहता हूँ कि कभी भी जिस अधिकार की लड़ाई हम कर रहे हैं हमें ये तय करना चाहिये कि हमारे बच्चेउस अधिकार की लड़ाई न लड़ें। आज इस देश को आज़ादी मिली हमारे पुर्वजों ने बड़ी लड़ाई लड़ी, बहुत सारे बलिदान देने पड़े। शहीदे आजम भगत सिंह को फांसी पर चढ़ना पड़ा। एक से एक बलिदान से देश को आज़ादी मिली, हमें गणतंत्र मिला। हर पांच साल में चुनाव हो ऐसी प्रक्रिया बनी। एक बार इमरजेंसी में जनतंत्र की हत्या करने की कोशिश की गई, क्या अंजाम हुआ? देश के सामने आज उसी तरह का दुस्साहस फिर से किया जा रहा है। इस देश के जनतंत्र की हत्या करने की कोशिश की जा रही है और अगर जनतंत्र की हत्या की कोशिश की जा रही है तो ये हम सबका दायित्व बनता है, सदन के जरिये मैं पूरे देश को कहना चाहता हूँ कि हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर 75 साल पहले जिस बात को लेकर आज़ादी दिलाई गई आज वो खतरे में हो तो हम सबको उसके चिालाफ खड़े होना चाहिये। अध्यक्ष महोदय आज जब केन्द्रीय सरकार की चिट्ठी से ये आदेश हुआ कि इलैक्शन को stall कर दिया जाये इलैक्शन को रोक दिया जाये, इलैक्शन की प्रक्रिया यहां रूक गई जैसा मैंने आपको पहले

ही बताया और आज पर्लियामेंट में बिल आया है और मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये जो बिल आया है और जिस किसी ने बिल ड्राफट किया है उसको न तो संविधान की जानकारी है न उसको कानून की जानकारी है ये आनन-फानन में बनाया गया है किसी तरह से चुनाव को रोका जाये और जब मैं यह कह रहा हूँ तो मैं आपको संविधान के उस सारे वाकया मैं इस पटल पर रखना चाहता हूँ कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये असंवैधानिक है और एक बात और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ आपको कि दिल्ली इलैक्शन कमिश्नर ने Solicitor General से इसकी वैधता को लेकर legal opinion मांगा था, Solicitor General ने opinion देने से decline कर दिया। अब मैं पूरी जिम्मेदारी से इस सदन में कह रहा हूँ विपक्ष के साथी इसकी पुष्टि करा सकते हैं। तो अगर Solistor General लीगल वैधता को लेकर opinion देने से मना कर रहे हैं तो ये अपने आप में दर्शाता है कि इसका मतलब ये चिट्ठी और इलैक्शन रोकना ये असंवैधानिक है। पहली बात जैसा मैंने आपको पहले कहा कि संविधान में 243 (U) में ये mandate है कि आप existing जो आपका निगम है उसके कार्यकाल खत्म होने से पहले आप निगम का चुनाव करा लें तो निगम का कार्यकाल 16 मई को खत्म हो रहा है आपको किसी भी तरह से 14 अप्रैल से पहले नोटिफिकेशन करना है जो नहीं करने जा रहें हैं। ऐसे तो पहला, आप 243 U का जो mandate था उस mandate को आप खत्म कर रहे हैं, दूसरा, constitution के 7th Schedule में item V जो

है वो item V ये पॉवर देता है State Government को कि आप Municipal Corporation के निर्माण उसकी शक्ति और उसकी कार्ययोजना ये सब State Government तय करेगी। 73rd और 74th का जो amendment है वो land mark amendment है, ये landmark में इसलिए कह रहा हूँ कि 1993 में 73rd 74th amendment के जरिये लोकल पंचायत और निगम दोनों को संवैधानिक वैधता मिली। तो 73rd और 74th amendment में जो incorporate हुआ part 9 और part 9 (a) उसमें state legislature को empowerd किया गया to structure the bodies in terms of election, in terms of finance, in terms of taxation तो इसका मतलब ये हुआ कि responsibility जो है in all respect ये state legislature को है तो इसका मतलब है कि जिस किसी ने ये बिल ड्राफट किया है उन्होंने 73rd 74th के amendment के जो incertion को Part 9, Part 9 (a)को नहीं देखा उसने जो अभी मैंने स्पीकर मैडम जो आपको मैंने बताया कि Item-5, 7th Schedule के जो Item 5 थे न उसको देखा। ये बिल अफरा-तफरी में इलैक्शन रोकने का जैसा मैंने पहला कहा, इलैक्शन रोकने की साजिश के तहत ये लाया गया है। अब देखिये एक मजे की बात है इसमें कहा गया है गर्वमेंट मतलब सैन्ट्रल गर्वमेंट कैसे होगा ये? अगर सैन्ट्रल गर्वमेंट है पैसे कौन देगा, बताईये ज़रा।

इस बिल में आपने कोई ऐसी बातें नहीं बताई हैं कि फंड कौन देगा। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे देगी फिर। आपने 2017 में

चुनाव लड़े था,आपने कहा था, आपके मैनिफैस्टो में है कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसे लायेंगे, तो क्यों नहीं पैसे लाए सेंट्रल गवर्नमेंट से और अगर गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है तो ये सरकार पैसे क्यों देगी निगम को, निगम चलेगा कैसे? तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ स्पीकर मैडम कि फिर से एक बहुत बड़ी साजिश जो इमरजेंसी के टाईम में हुआ था, उसी तरह की साजिश फिर से केन्द्र सरकार दिल्ली में इलेक्शन रोकने की प्रक्रिया के तहत करने की कोशिश कर रही है। मैंने मजाक मजाक में कहीं कहा भी कि अभी तो पंजाब जीते हैं तो इतनी घबराहट, अभी चार और स्टेट का चुनाव है। तीन स्टेट का तो अभी है। दो साल में तो सात स्टेट का चुनाव, कहीं हम जीत गए, कहीं आम आदमी पार्टी जीत गयी तो ऐसा नहीं होगा। आप कहते हैं कि पार्लियामेंट का भी चुनाव न कराएं, जिसकी बात कल इस हाउस में ऑनरेबल सीएम साहब कह भी रहे थे कि मैं बस विपक्ष के साथियों से भी कहना चाहता हूँ। देखिये, आज कोई भी ऐसी सत्ता किसी के लिए भी, सरकार किसी का भी हो, कोई पक्ष में रहेगा तो कोई विपक्ष में रहेगा, लेकिन अगर लेजिस्लेटिव प्रोसेस का, अगर संविधान की हत्या हो रहा हो, उस समय में अगर आप चुप हैं तो इतिहास तो सब की लिखी जाएगी। तय किया जाएगा कि कौन सच्चाई के साथ खड़ा था और कौन सच्चाई के चिालाफ खड़ा था। अगर द्रोपदी का चीरहरण हुआ और उस समय में जो चुप थे, आज दोषी तो हम उनको मान रहे हैं। अगर संविधान का चीरहरण हो

रहा है और अगर आप चुप हैं तो आप भी उतने ही इतिहास में दोषी होंगे, जो बाकी वो जिन्होंने संविधान की हत्या करने की कोशिश की थी। तो ज्यादा न कहते हुए बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ स्पीकर मैडम कि आज जिस विषय पर चर्चा हो रहा है, वो बहुत गंभीर है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये सदन पक्ष और विपक्ष दोनों एक मत से ये तय करेगा कि अगर दिल्ली में संविधान की हत्या होगी तो हम उसके विरोध में खड़े होंगे। थैंक्यूँ

माननीया अध्यक्षः पवन शर्मा जी, पवन शर्मा जी।

श्री पवन शर्माः धन्यवाद अध्यक्षा महोदया, आपने मुझे एमसीडी चुनाव परिचर्चा पर बोलने का अवसर दिया। अध्यक्ष महोदया, संजीव भाई ने बहुत कुछ डिटेल में बताया जैसा एमसीडी चुनाव और भारतीय जनता पार्टी, इसके जी का जंजाल बन गया है। बहुत बुरा हाल है। हार का इतना डर, इतना डर की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अंतिम क्षणों में मैदान छोड़कर भागने को मजबूर हो गयी है। 7 मार्च को 5 राज्यों में चुनाव का अंतिम दौर समाप्त होता है और शाम को ही एक्जीट पोल के नतीजे आने शुरू हो जाते हैं और 8 मार्च तक यह आईने की तरह साफ हो जाता है कि आम आदमी पार्टी पंजाब में न केवल पूर्ण बहुमत से आ रही है बल्कि 90 से 100 सीट लेकर फुल बहुमत से सरकार बना रही है, तो एमसीडी में 15 साल से काबिज भारतीय जनता पार्टी के तोते उड़ जाते हैं।

अध्यक्ष महोदया, भाजपा को पहले से ही अंदाजा तो था कि पंजाब में माननीय अरविंद केजरीवाल जी का जादू पंजाब वासियों के सर चढ़ कर बोल रहा है और इसके लिए भाजपा अवसाद में पहुंच चुकी थी। अध्यक्ष महोदया, मेरी जानकारी के अनुसार डूबती हुई भाजपा ने आत्मघाती प्लान बी पहले से ही तैयार कर रखा था जो अवसाद की स्थिति से उबरने के लिए बनाया गया था और उसपर अमल भी शुरू कर दिया था।

महोदया, चुनाव आयोग दिल्ली म्युनिसपल कॉरपोरेशन की चुनाव की घोषणा के लिए प्रेस कांफ्रेस बुलाते हैं, लेकिन धूर्तता की हदों को पार करते हुए भाजपा की केन्द्र सरकार का चुनाव घोषित न करने का फरमान पत्रकार वार्ता से ठीक एक घंटा पहले चुनाव आयोग के पास आता है और बड़ी बेशर्मी से दिल्ली नगर निगम के चुनाव इस बहाने के साथ टाल दिये जाते हैं कि दिल्ली की तीनों निगमों के एकीकरण का फैसला ले लिया गया है।

अध्यक्ष महोदया, इस सदन के माध्यम से मैं केन्द्र सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या यह फैसला कब और किसने लिया क्योंकि कैबीनेट की मीटिंग में तो अभी 21, 22 मार्च को यह पारित किया है। इसका सीधा-सीधा मतलब है कि 9 मार्च का फरमान किसी केन्द्र सरकार द्वारा लिया गया फैसला नहीं था बल्कि किसी तानाशाह द्वारा जारी किया गया तुगलकी फरमान था और जिसके आगे चुनाव आयोग नतमस्तख्क था।

महोदया, ये लोकतंत्र पर सबसे बड़ा कुठाराघाट है। ये जनता का अपमान है। ये लोकतंत्र का अपमान है।

अध्यक्ष महोदया, मैं अपने काबिल विपक्षी साथियों को आगाह करना चाहता हूँ कि बिल्ली को देखकर कबूतर अगर आंखे बंद कर लेता है तो इसका मतलब ये नहीं की कि बिल्ली भाग गयी है। बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। चार दिन बाद, चार माह बाद चुनाव तो कराने ही होंगे, परिणाम भी बदलने वाले नहीं है बल्कि और भयंकर होंगे। चुनाव से जितना दूर भागोगे उतना अधिक नुकसान उठाओगे। केन्द्र में 8 साल से बैठे हुए हैं आप। एकीकरण के विषय पर अचानक नींद कैसे टूट गयी, वो वी चुनाव घोषणा से ठीक एक घंटे पहले। ये नींद हार के डर से टूटी है। अवसाद की स्थिति में नींदटूटी है। अभी तो और भी बुरे सपने इन्हें तंग करने वाले हैं।

अध्यक्ष महोदया, हिमाचल, गुजरात और हरियाणा ने अंगड़ाई लेनी शुरू कर दी है। कहां कहां से चुनाव रोकेंगे।

अध्यक्ष महोदया, अभी रसिया और यूक्रेन के बीच जो टेंशन है जो पीछे हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट भारत के स्टूडेंट वहां पढ़ने गये हुए थे। जो दुर्दशा हुई, जो परेशानी हुई, उसके बाद देश में, दिल्ली में लोगों में ये चर्चा जोरों पर थी कि जिस प्रकार से पिछले 70 सालों में जितनी भी सरकारें रहीं केन्द्र में और अब आठ साल से भाजपा की केन्द्र में सरकार है। अगर देश में

अरविंद केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री होते तो ये दुर्दशा हमारे बच्चों की नहीं होती, जिस प्रकार से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने हमारे माननीय उप-मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी ने।

माननीया अध्यक्षः जल्दी कीजिए। कंप्लीट कीजिए।

श्री पवन शर्माः शिक्षा के क्षेत्र में काम किये उसी प्रकार से देश में अगर शिक्षा पर काम हुआ होता तो ये दशा हमारी नहीं होती।

अध्यक्ष महोदया, मैं ईश्वर से इस प्रार्थना के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। मैं भगवान की, हमारे साथी जो बैठे हैं, इन्हें भगवान श्री राम सद्बुद्धि दे कि दिल्ली के नगर निगम के चुनाव अपने समय पर करवायें। जनता अपना मन बनाए बैठी है। हार तो इनकी तय है। जितना जल्दी चुनाव करवा लेंगे, उतना फायदे में रहेंगे। हो सकता है कि समय पर चुनाव कराने की स्थिति में दिल्ली के लोग तरस खाकर शायद दो, चार सीट इनको दे दें।

माननीया अध्यक्षः धन्यवाद।

श्री पवन शर्माः मुझे महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीया अध्यक्षः भावना गौड़ जी।

सुश्री भावना गौड़ः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है सदन में। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। देश की आजादी के लिए लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी। न जाने कितनी सारी महिलाओं के सुहाग उजड़े, न जाने कितने सारे बच्चे अनाथ हुए। कितने संघ्र्षों के बाद ये आजादी मिली, उनके लिए शायद शब्दों का उपयोग नहीं बन पाता।

अध्यक्ष महोदय, संविधान की रचना के लिए भी कितने संघ्र्ष हुए। आज हम सब गंभीर है क्योंकि आज देश का संविधान खतरे में है। आज देश का लोकतंत्र खतरे में है। अध्यक्ष महोदय, भारत देश की राजधानी दिल्ली, जिसमें हम सभी निवास करते हैं। दिल्ली का प्रतिनिध्त्वि करते, ये विधान सभा में बैठे हम सभी विधायक हमारी देख रेख में, दिल्ली के लोगों को छला जा रहा है। देश पर, पूरी दिल्ली पर, लोकतंत्र के ऊपर इस समय खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। हार के डर से चुनाव टालने के लिए चुनाव आयोग पर दवाब बनाया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, एमसीडी चुनाव टालना लोकतंत्र के अंत की शुरूआत है। अध्यक्ष महोदय, 9 मार्च को शाम पांच बजे दिल्ली चुनाव आयोग ने एक पत्रकार वार्ता बुलाई जिसमें ये ऐलान होने वाला था कि किन तारिखों में दिल्ली के अंदर एमसीडी के चुनाव होंगे, पर ऐसा नहीं हुआ।

अध्यक्ष महोदय, चीफ इलेक्शन आफिसर ने कहा कि उन्हें थोड़ी देर पहले केन्द्र सरकार से एक चिट्ठी मिली है और उसमें नगर निगम के तीनो नगर निगमों को एक करने की बात कही गयी है इसलिए फिलहाल चुनाव की डेट को घोषित करना अपने आप में ठीक नहीं है। चुनाव टाल दिये गये।

अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो चुनाव आयोग ये कहता है कि यूनिफिकेशन से इलेक्शन का कोई लेना देना नहीं। वो चुनाव करा सकते हैं पर अभी उन्हें इसकी अनुमति नहीं है। ये क्या कर रहे हैं चीफ इलेक्शन आफिसर? श्री वास्तव जी ने जब अपना पद ग्रहण किया तो कहीं न कहीं तो उनकी भी आत्मा जागी होगी। निष्पक्ष तरीके से काम करेंगे, फ्री सेवा देंगे, निष्पक्ष चुनाव कराएंगे, कोई भेदभाव नहीं होगा इस तरह का विचार जो पद ग्रहण करते समय उनके मन में आया वो विचार आज न जाने कहां गुम हो गया है। किसके दबाव में चुनाव आयोग काम कर रहा है ये बताने की आवश्यकता इस सदन को नहीं है। दिल्ली की जनता त्रस्त है लेकिन जनता ने कहीं न कहीं मन बनाया हुआ है कि दिल्ली निगम में बैठी बीजेपी की सरकार को बदलना है। निगम के अंदर बीजेपी की सरकार का हारना तय है। अध्यक्ष महोदय एमसीडी में 272 सीटें हैं। बीजेपी ने सर्वे करवाया, मीडिया ने सर्वे करवाया, पार्टी ने सर्वे करवाया और ये सर्वे ये कहता है कि 272 में से 250, 260 सीटें आम आदमी पार्टी जीत सकती है और 5 या 10

सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। तो दिल्ली की जनता को सीधा-सीधा बताने की आवश्यकता नहीं, कहने की आवश्यकता नहीं। यहां तक कि जब आम आदमी पार्टी के लोग अपने कामों का प्रचार-प्रसार करने या एमसीडी का व्याख्यान करने लोगों के दरवाजे जाते हैं तो लोगों ने आलरेडी मन बनाया हुआ है, लोग हमें कहते हैं निगम का चुनाव है आपको हमारे दरवाजे आने की आवश्यकता नहीं है। आम आदमी पार्टी के कामों को, आम आदमी पार्टी के विचारों को हमने देखा है, हमने परखा है और हम उनके कामों का लाभ उठा रहे हैं। तो इस बार एमसीडीज में केवल और केवल झाड़ू चलेगी। अध्यक्ष महोदय, देश में अगर चुनाव टल गया तो जनतंत्र को अपने आप में बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। लोकतांत्रिक, संवैधानिक सरकार के अंतर्गत जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन होता है। अध्यक्ष महोदय, लोकतांत्रिक देश में चाहे वो अमीर आदमी हो, चाहे गरीब आदमी हो, चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे किसी धर्म का हो, चाहे किसी बिरादरी का हो, वो 5 साल में एक बार वोट करता है और वो अपने एक वोट से किसी भी नेता को बना सकता है, किसी भी सरकार को बदल सकता है,किसी भी मंत्री को बनाता है, किसी भी मुख्यमंत्री को बनाता है और किसी भी पार्टी को सत्ता में बिठा सकता है। लेकिन अगर वो बिठाना जानता है तो उसको उतारना भी जानता है। ये जनता अपने आप में जनार्दन है, उसके मनोभावों को सत्ता में रहने वाली प्रत्येक सरकार को समझना चाहिए और

अध्यक्ष महोदय मैं आपको बताना चाहूँगी हमारे यहां पीएमओ का एक अलग ही स्टाईल है। सबसे पहले वो देश के भ्रष्ट अधिकारियों की लिस्ट बनाता है, उसके बाद में ये लिस्ट बनाता है कि किस अधिकारी ने कितना भ्रष्टाचार किया और फिर उन अधिकारियों को बड़े ही अहम पदों के ऊपर नियुक्त किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, जब वो अपनी मनमानी से नियुक्त करते हैं तो अपनी मनमर्जी से वो काम भी उन लोगों से करवाते हैं और ये अपने आप में आज के इस युग के अंदर भारत को चलाने के लिए हमारी सरकार का एक विशेष स्टाईल बन गया, केन्द्र सरकार का ये एक विशेष स्टाईल है। राज्य चुनाव आयोग एस के श्रीवास्तव जी ने कहा केन्द्र सरकार ने कुछ ऐसे मुद्दे उठाये हैं जिनकी कानूनी रूप से जांच होना बाकी है इसलिए अभी हम एमसीडी चुनाव नहीं करवा सकते। इसके विपरीत इस सदन को मैं बताना चाहूँगी कि टी.एन. शेषन जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे, वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने चुनाव आयोग को एक अलग ही प्रकार की ऊंचाईयां प्रदान की। बीजेपी दिल्ली में इस समय एमसीडी चुनाव से भाग रही है। पन्द्रह सालों से दिल्ली नगर निगम के अंदर बीजेपी का जो शासन रहा है और उसने जनता पर जो कहर ढ़ाया है, चाहे वो बिल्डिंग डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो हाउस टैक्स डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो सफाई के मामले में हो, इक्रीचमेंट को लेकर के हो, दिल्ली इस समय गंदगी के, कूड़े के ढ़ेर के ऊपर बैठी हुई है। अब अध्यक्ष महोदय, क्या एमसीडी चुनाव करवाने से पहले इस

तरह का इमरजेंसी ब्रेक लगाना आवश्यक था, ये अपने आप में एक प्रश्न है। अब दूसरा प्रश्न यह है कि क्या केन्द्र सरकार किसी चुनाव को करवाने या रद्द करवाने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश दे सकती है। प्रश्न यह भी है अध्यक्ष महोदय कि किस प्रावधान के तहत ऐसा होता है। प्रश्न यह भी है कि क्या यह दिशा–निर्देश चुनाव आयोग के लिए बाध्यकारी है। प्रश्न यह भी है अध्यक्ष महोदय क्या चुनाव आयोग झुक गया है। क्या देश के प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश में चुनाव नहीं करवाना चाहते। माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में उदासी है ऐसा लगता है पानी में रहकर के भी मछली प्यासी है। आप प्रधानमंत्री हैं, आप देश चलाईये आप चुनाव आयोग को बाध्य न कीजिए। निश्चित समय के ऊपर हिन्दुस्तान के अंदर चुनाव होते आए हैं और होंगे। ये देश की जनता है ये आपको गद्दी पर बिठा भी सकती है आपको वहां से उताकर के फेंकने की भी क्षमता अगर किसी में है तो वो देश की पब्लिक में है। दिल्ली की जनता एमसीडी में बदलाव चाहती है। चुनाव करवाना चुनाव आयोगी की जिम्मेवारी है आपकी नहीं। माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने भी स्वयं प्रधानमंत्री जी से अपील की है सरकारें आती हैं, जाती हैं, कल आप नहीं रहेंगे शायद हम भी नहीं होंगे पर देश महत्वपूर्ण है देश के लिए जीना देश के लिए मरना हमारा संस्कार है। चुनाव आयोग पर दबाव डालकर के चुनाव कैंसिल करवाना चुनाव आयोग को अपने आप में कमजोर बनाता है और यह जनतंत्रके लिए अपने

आप में एक बहुत बड़ा खतरा है। अध्यक्ष महोदय मैं आपको बताना चाहूँगी देश में बीजेपी के 1435 विधायक हैं, 1435 विधायक इस समय वर्तमान में हैं। 97 राज्यसभा सांसद हैं बीजेपी के। 301 लोकसभा सदस्य हैं और वहीं लगभग 40 निगमों के अंदर बीजेपी का कब्जा है।

माननीया अध्यक्षः बहुत-बहुत धन्यवाद जी।

सुश्री भावना गौडः देश की इतनी, मैं अभी खत्म कर रही हूँ बस। देश की इतनी बड़ी पार्टी अगर आम आदमी पार्टी जैसी छोटी पार्टियों से डर जाएगी तो सोचिए इससे बड़ी जीत हमारे लिए कुछ और नहीं हो सकती। अध्यक्ष महोदय इस सदन के माध्यम से मेरी यही मांग है कि दिल्ली में एमसीडी के चुनाव करवाए जाएं और इसका फैसला दिल्ली की जनता पर छोड़ दिया जाए, धन्यवाद आपने मुझे बोलने का मौका दिया, शुक्रिया।

माननीया अध्यक्षः बहुत-बहुत धन्यवाद श्री सौरभ भारद्वाज जी।

श्री सौरभ भारद्वाजः बहुत-बहुत धन्यवाद राखी जी और आपको बधाई की आज हमारे जो हाउस का संचालन है वो आप कर रहे हैं और जैसा कि मेरे से पहले संजीव भाई ने बोला और भावना बहन ने बोला ये जो केन्द्र सरकार आज कानून लेकर आई है लोकसभा के अंदर और केन्द्रीय गृह मंत्री ने यह बिल जो लोकसभा में रखा है यह मुझे लगता है कि काफी पीछे ले जाने

वाला कानून है और हमसे ज्यादा ये हमारे भाजपा के मित्रों के लिए दुख की बात है क्योंकि रामवीर सिंह बिधूड़ी जी जिस तरह से हाउस के अंदर काम कर रहे हैं, विजेन्द्र गुप्ता जी कर रहे हैं बाकी छह और भाजपा के साथी कर रहे हैं ये मन में कहीं न कहीं यह उम्मीद लगाकर काम कर रहे होंगे कि 2025 में जब दिल्ली के अंदर चुनाव होगा इनके कामों से प्रभावित होकर, मोदी जी के कामों से प्रभावित होकर दिल्ली की जनता इन्हें मौका देगी। ये सोचते हुए और इनके मन में यह होगा कि पांच साल बाद जनता इन्हें यहां बैठने का मौका देगी मगर मोदी जी ने इस कानून को लाकर देश की संसद में इस बात को स्थापित कर दिया कि मोदी जी को, अमित शाह जी को पूर्ण विश्वास है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली से कहीं नहीं जाने वाली ये लोग वहीं बैठेंगे। थोड़ा सा भी इनके ऊपर भरोसा होता इनकी कैपेसिटी पर इनकी कैपेबिलिटी पर इनकी क्षमता पर भरोसा होता, तो वो कहते 2025 तक रुक जाओ रामवीर बिधूड़ी जी मेहनत कर रहे हैं, विजेन्द्र जी लगे हुए हैं, अगली बार वो मुख्यमंत्री बनेंगे क्या दिक्कत है, एमसीडी बढ़िया चलाएंगे। मगर जब केन्द्र सरकार ऐसा कानून ले आई जिसके अंदर सारी की सारी एमसीडी को समेटकर केन्द्र के अंदर ले गये, इसका मतलब यह है मोदी जी को क्योंकि देखो मोदी जी साधारण आदमी नहीं हैं, सही बता रहा हूँ। मैं गुजरात गया एक भाजपाई से बात हो रही थी, मैं थोड़ी ही देर में समझ गया भाजपाई है, फिर मैंने बोला यहां पर

लोग कोस बहुत रहे हैं नरेन्द्र मोदी जी को काफी उल्टी-सीधा बोल रहे हैं, मैं तो सोच रहा था गुजरात में इनकी बड़ी चलती होगी। तो देखो आप, आप भाजपाई को सोचों भाजपाई आदमी सोचता कैसे है, कहता है भाई साहब आपके घर में बुरा हो जाता है तो आप किसको कोसते हो भगवान को, मोदी जी भगवान हैं इसलिए कोस रहे हैं ये, मैंने कहा जय हो भाई तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तो आप सोचिये कि उनके दिमाग का ऐसा ऑपरेशन कर रखा है कि अगर वो बुरा भी करेगा तो ये कहेंगे कि ये तो आपके साथ बुरा होगा आप भगवान को कोसोगे ओहो भगवान ये हमारे साथ क्या किया। सही में, सही में आपको क्या लग रहा है सही में बता रहा हूँ। तो अब मोदी जैसे विश्व विजेता और जो हर चीज के ऊपर मुझे लगता है बड़े-बड़े मसले सुलझाते हैं, अभी रशिया का और युक्रेन का मसला सुलझा रहे थे, मतलब मुझे दिल पर इतना दुख हुआ कि अगर अब मेरे पड़ोस में झाडू नहीं लगेगी मोदी जी वहां रशिया और युक्रेन की बातचीत करा रहे होंगे। कोई फोन करके कहेगा भाई साहब हमारे मोहल्ले में झाडू नहीं लगी क्योंकि सीधा उन्होंने अपने अंडर ले लिया। भाई साहब सोचो, मतलब हम तो यहां पर पुतिन को और पता नहीं चीन को आंखें दिखा रहे हैं यह कहकर जी हमारे मोदी जी हैं सारे मसले वो सुलझाएंगे और अब कूड़ा नहीं डलेगा, काउंसिलर जो है छज्जे नापेगा, एमसीडी भेजेगा उसके यहां।

सुश्री आतिशीः काउंसिलर तो बचा नहीं।

श्री सौरभ भारद्वाजः अच्छा काउंसिलरों का काम भी मतलब एक ले देकर बेचारे वो काम करते थे छज्जे-वज्जे नापते हुए घूमते थे कहीं पर जेसीबी भेजते थे कुछ करते थे वो काम भी मोदी जी ने उनसे ले लिया। अब ये देश कैसे चलेगा और देश नहीं ये संसार कैसे चलेगा। आप ये सोचिये ब्रह्मांड कैसे चलेगा प्रभु अगर एमसीडी में बिजी हो जाएंगे तो ये काफी दुख की बात है और जिस रिफार्म की बात हम लोग कर रहे थे कि रिफार्म आने वाले हैं, रिफार्म आने वाले, रिफार्म तो कोई है ही नहीं इसके अंदर। एक समस्या एमसीडी की हमेशा से रही है कि इनके पास पैसे नहीं है। इनके पास पैसे नहीं है ये हमेशा कोसते रहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। अब इन्होंने तीन जगह पैसा नहीं था इन्होंने अब एक कर दिया तो अब पैसा कहां से आएगा ये नहीं बताया और सोमनाथ जी ये सबसे ज्यादा अन्याय हमारे साथ किया है इन्होंने।

थोडा बहुत पैसा मेरे मदन लाल, सोमनाथ भाई जो दक्षिण दिल्ली के विधायक है आतिशी जी बैठी है ये हमारे साथ ज्यादा अन्याय किया है इन्होंने। प्रवीण भाई भी बैठे हैं। जितना थोड़ा बहुत रेवेन्यू आता था वो दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अंदर आता था। क्योंकि वहां पर साउथ में सहीराम जी है, हम लोग रखवाली भी करते थे और हमारे यहां बड़ी-बड़ी कालोनियां हैं वहां से प्रोपर्टी

टैक्स वगैरह आता था। अब ये कह रहे है कि जो साउथ की एमसीडी का पैसा है वो बांट देंगे ईस्ट और नार्थ के अंदर तो पैसे की वो जो कमी है वो हल हो जाएगी, ये कैसे हल हो जाएगी। मतलब बचाकुचा जो साउथ में थोडा बहुत अच्छा काम होता था आप उसको भी नहीं करोगे। आपको तो ये कहना चाहिए था कि भई साउथ की हालत ठीक है तुम अपना चलाते रहो। ईस्ट में हालात खराब हैं, ईस्ट में मोदी जी दे देंगे पैसा। नार्थ में हालात खराब हैं नार्थ में मोदी जी पैसा दिया करेंगे तो हालत अच्छी हो जाएगी। पैसे के बारे में तो जिक्र ही नहीं है उस पूरे के पूरे बिल में। फाईनांस कमिशन क्या करेगा, आगे कैसे बदलेगा उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। मतलब जो फाईनांस कमिशन पहले करता था वो अभी भी करेगा। दिल्ली सरकार से जो ग्रांट जाते थे वो अभी भी जाएगें। मतलब कटोरा लेकर तो हमारे आगे ही बैठेंगे फिर से तो बदलेगा क्या, हां जो कन्ट्रोल है वो सारा का सारा केन्द्र सरकार को मिल रहा है, तो इसके अंदर रिफार्मस कोई नहीं है। तीन चीजों को मिलाकर एक कर रहे हैं और उसके बाद चुनाव कब कराएगें मुझे तो पता नहीं। किसी को इन्होंने हायर किया है कन्सलटेंट को। उसको बोला कि भई हर महीने सर्वे होगा दिल्ली में। जब तक हम जीत्ते नहीं तब तक हम चुनाव नहीं होने देंगे। अच्छा अब वो सर्वेयर भी जा–जाकर परेशान करेंगे दिल्ली वालों को कि भाई साहब इनका कुछ बढ़ा ऊपर, कह रहे है अभी नहीं बढ़ा। उसके पैसे बनते रहेंगे। वो बार–बार जाकर कह रहे हैं जी कुछ हुआ इनका।

कह रहे है नहीं हुआ। कह रहे है आगे टालो, और टालो-टालो। ये तो चुनाव कभी होंगे ही नहीं या फिर हम सर्वेयर का पैसा वैसा देकर कहें कि इनको कह दो की बढ़ गया है इनका चुनाव तो करा लो। ये ही एक तरीका है कि इनको सर्वेयर को भई अपने लोगों को दिल्ली में कहो की भई एक डेढ महीना इनकी वाह-वाह करनी शुरू कर दो कि बहुत बढ़िया चल रहा है। मोदी जी का चल रहा है और इस बार ये आने वाले हैं। इनका सर्वेयर जैसे रिपोर्ट देगा ऊपर की भाई साहब सब सैट मामला है कि कराओ चुनाव, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पहले वो सिरसा जी, विरसा जी वो गडबड़ थे वो कपिल वपिल। अब आप लोग ठीक आदमी हो। more or less मैं सच बता रहा हूँ दिल से बता रहा हूँ। इससे भाई साहब आपका नुकसान ज्यादा होगा। मैने कहा वो क्यों होगा। एमसीडी के पाप का घड़ा भरा हुआ है। लोग पूरी खुंदक में है उनसे। अच्छा आप जितने देर तक उन्हें वोट देने का मौका नहीं दोगे उनकी खुंदक और बढ़ती जाएगी। 2014 में भी ये ही हुआ था। 2014 में 14 फरवरी को हमारी सरकार गिर गई। आपका सर्वे खराब था। आपने बोला बाद में चुनाव कराऐंगे। एक महीना, दो महीना, छः महीना, आठ महीना फिर दिनेश मोहनिया जी से भी मुलाकात हुई थी शेर सिंह डागर जी, कहां गई दिनेश भाई। वो टीवी पर चला था। शेर सिहं डागर है हमारे यहां शाहपुर जट से ही है वो दिनेश मोहनिया जी से मिले। पांच करोड की बात हुई। इनके पास भी गए। रंजू मिनाज गई उनके पास। उनसे बात की। ये

चलता रहा और सर्वे इनका खराब ही रहा। फिर जाकर हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र को और चुनाव आयोग को आदेश दिया कि भई आप चुनाव कराओ और 2015 में चुनाव हुए। हमारा ग्रफ जो 28 सीट पर था वो बढ़ कर भाई साहब एक साल में 67 पर हो गया। आप इस उम्मीद में मत रहो कि लोग अपना मन बदलते हैं। लोग ना और ज्यादा ना भर जाते है। लोग कहते है अच्छा इनको बताएगें। अब आपका नुकसान कैसे होगा भाई साहब। अभी आप चुनाव नहीं होने दोगे। सर्वे आगे आएगा नहीं ठीक और ये चुनाव आपके चुनाव के साथ होगा। 2025 में और आप सब भले मानस हो बढिया आदमी हो उनके चक्कर में आप भी लपेटो जाओगे। ये ही होना है। आप भाई हो। आप सब बड़े भाई हो और भले आदमी हो पक्की बात है। मगर इनके चक्कर में आप लोगों का नुकसान होगा ये गड़बड़ है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीया अध्यक्षः विजेन्द्र गुप्ता जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः आदरणीय अध्यक्षा जी, अभी हमारी छोटी बहन भावना जी ने कहा कि आम आदमी पार्टी छोटी सी पार्टी है मैं उनकी इस बात से सहमत हूँ। जो अभी हमारे भाई साहब बोल रहे थे उसमें आगे जोडते हुए इतना ही कहूँगा कि थोथा चना बाजे घना। छोटी से पार्टी है बोलती ज्यादा है। लेकिन लोकतंत्र की महिमा है जुबान पर तो किसी के कोई कन्ट्रोल होता नहीं है। अब मुद्दा ये हैकि इतने गम्भीर विषय पर एक ऐतिहासिक भूल को

ठीक करने का काम शुरू हुआ है। उस पर सहमति आम आदमी पार्टी की भी है। कांग्रेस पार्टी की भी है। यूनिफिकेशन पर कोई contradiction नहीं है। नगर निगमों का एकीकरण मूलरूप से सभी राजनैतिक दल इसके लिए एक मत है। लेकिन बड़ी विचित्र स्थिति है कि यूनिफिकेशन के तो फेवर में है पर इलैक्शन जो है वो trifurcated होना चाहिए। एक दिन केजरीवाल जी बोल रहे थे कि भई बाद में कर लेना। भई जब युनिफाईड बॉडी की बात हो रही है तो ईडीएमसी का इलैक्शन का क्या मैटर रह गया। ईडीएमसी में क्या कहकर इलैक्शन लड़ोगे। एनडीएमसी में क्या कहोगे, साउथ में क्या कहोगे। यानि कि कुल मिलाकर बॉडी युनिफाईड होनी चाहिए। इलैक्शन trifurcated होना चाहिए। तो ये इतना बड़ा contradiction आम आदमी पार्टी का दिल्ली की जनता देख रही है और समझ रही है। ये यूनिफिकेशन जो है ये एक रिफॉर्म प्रोग्राम है। आप सब जानते हैं कि जब शीला दीक्षित सरकार ने इसका trifurcation किया तो scientific basis नहीं था। financial viability का भी ध्यान नहीं रखा गया। एक नैचूरल बाउंड्रीज नार्थ और साउथ में कोई है नहीं। ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कार्पोरेशन में जितनी आमदनी का जरिया है खर्चा उससे कई गुणा ज्यादा है। जब trifurcate किया गया तो इसकी कोई जांच नहीं की गई। उनके स्त्रेतों को नहीं देखा गया उनके obligation का ध्यान नहीं किया गया और कुल मिलाकर स्थिति ये हुई कि देश के किसी metropolitan city सिटी में इस प्रकार से divided corporation नहीं है दिल्ली को छोडकर।

अध्यक्षा जी अब मैं बात करता हूँ कि दिल्ली की सरकार ने किस तरह से नगर निगमों के मामले में एक खलनायक की भूमिका निभाई। trifurcated body थी। चौथा वित्त आयोग जो निगमों के trifurcation के बाद उस रिपोर्ट में सारी बातें लिखी गई कि trifurcation के बाद इनकी फंडिंग्स का क्या स्टेटस है। बड़ी हैरानी की बात है कि दिल्ली की सरकार ने चौथे वित्त आयोग को लागू ही नहीं किया। एक तरफ निगम तीन हिस्सों में बंट गया। क्योंकि संविधान कहता है कि फाईनांस कमिशन की रिपोर्ट असेम्बली के पटल पर टेबल होगी और असेम्बली थी नहीं। असेम्बली का गठन हुआ 2015 में। असेम्बली बैठी 2015 में और जब असेम्बली 2015 में बैठी तो दिल्ली की सरकार ने उसके बावजूद उस रिपोर्ट को टेबल नहीं किया और जिसके कारण दिक्कतें आई संविधान का उल्लघंन हुआ। constitution crisis हो गया कि फाईनांस कमिशन की रिपोर्ट टेबल नहीं हो रही है। 2018-19 में अर्बन डवलमेंट सैक्टर में योजना मद के अन्तर्गत निगम को जो पैसा मिलता था सारा रूक गया। यानि कि पहले फाईनांस कमिशन को टेबल नहीं किया उसके बाद उसकी recommendation को लागू नहीं किया और सैन्ट्रल गवर्नमेंट का जिसमें कोई रोल नहीं है। State Finance Commission का मतलब है लोकल बॉडी और स्टेट गर्वनमेंट उसमें जबरदस्ती सैन्ट्रल का नाम लेकर उसको set-aside कर दिया गया। मेरा कहना कुल मिलाकर कुल मिलाकर ये है कि जब भी दिल्ली नगर निगमों के फंडस को रिलीज करने की बात आई, जानबूझ

कर नगर निगमों को पंगू बनाने के लिए कि वो अपना काम ना कर सकें इस लिए यहां तक कि 05 अप्रैल 2021 को दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश से और क्या टिप्पणी की दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा 'question Arvind Kejriwal Government for raising the issue of shortage of funds.' जब इन्होंने कहा कि जी हमारे पास पैसा नहीं है कोर्ट के सामने तो कोर्ट ने कहा while there are full page advertisements in newspapers आपके पास निगमों देने के लिए पैसा नहीं है लेकिन फुल पेज ऐड देने के लिए आपके पास पैसा है। आप 500 हजार करोड रूपया ऐड पर खर्च कर रहे हैं और नगर निगम के एम्पलाईज को सैलरी ना मिले इसके लिए एक प्रकार से आप शडयंत्र कर रहे हैं। ये बात एक आम धारणा में आई और जिसके कारण निगमों को पंगू बनाओ, निगमों का काम रोको, निगम काम ना कर सके, एम्पलाईज को सैलेरी ना मिले और पांच साल पहले पांच साल और अब ये दो साल लगातार एक ही काम दिल्ली की सरकार ने किया कि निगमों को बिल्कुल वित्तिय रूप से पंगू बनाने का काम किया है। इसके कारण आज ये स्थिति उत्पन्न हुई है कि यूनिफिकेशन होना सिर्फ होना ही नहीं बल्कि आवश्यकता है समय की दिल्ली के विकास के लिए और पैसा जो दिल्ली की सरकार रोक रही है मैं अध्यक्षा जी आपके माध्यम से कहना चाहूँगा इस बात की जांच बिठानी चाहिए कि पिछले सात सालों में किस प्रकार निगम के पैसे को रोका गया है और जांच

के बाद अगर आवश्यकता पड़े तो ऐसी सरकार को भंग कर देना चाहिए।

माननीया अध्यक्षः बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः क्योंकि ये जो स्थिति उत्पन्न हुई है इसकी पूरी जिम्मेदारी दिल्ली की सरकार की है। केजरीवाल सरकार की है। खलनायक की भूमिका में आकर निगमों को पंगू बनाया और दिल्ली की जनता को परेशान करने की कोशिश की। धन्यवाद।

माननीया अध्यक्षः धन्यवाद। अब सवा दो बजे लंच के बाद सवा दो बजे मुलाकात करेंगे।

(सदन की कार्यवाही अपराह्न 2.15 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

सदन पुनः अपराह्न 2.20 बजे समवेत हुआ।

माननीया अध्यक्ष (श्रीमती राखी बिरला) पीठासीन हुई।

माननीया अध्यक्षः एमसीडी पर चर्चा जरनैल सिंह जी।

श्री जरनैल सिंहः शुक्रिया अध्यक्ष महोदया, दिल्ली नगर निगम चुनाव में विलंब से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण चर्चा पर बोलने का समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदया देश में इस वक्त दो किस्म की राजनीति हो रही है। पहले किस्म की राजनीति वह है जिसकी शुरुआत कुछ सालों पहले हुई है

जिसको लेकर भाजपा में बहुत घबराहट भी है, वो है काम करने वाली राजनीति। आप सबको ध्यान होगा पूरी दिल्ली इस चीज की गवाह है कि साल 2020 के अंदर आम आदमी पार्टी ने एक नई किस्म की राजनीति पूरी दुनिया के आगे रखी वो राजनीति थी काम के दम पर वोट मांगने वाली राजनीति। साल 2015 के अंदर हमने जो वायदे किये थे मेरे को इस चीज का फर्क है कि जब 2020 के चुनाव हुए तो हमारे एक हाथ में 2015 वाला मेनिफेस्टो था और दूसरे हाथ में 2020 का रिपोर्ट कार्ड था और यह कहने की हिम्मत करी कि अगर काम किया है तो वोट देना नहीं तो वोट मत देना, यह तो पहले किस्म की राजनीति है और दिल्ली वालों ने फिर से 70 में से 62 सीटें दी। दूसरे किस्म की राजनीति है झूठ की सियासत, संविधान का गला घोटने वाली सियासत, तानाशाही की सियासत और यह कोई पहली बार नहीं हो रहा है इस सरकार में, केन्द्र सरकार द्वारा इससे पहले भी कभी नोटबंदी कानून लाकर, कभी तीन काले कानून लाकर बार-बार लोगों पर अपनी तानाशाही फैसले थोपे हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जब पूछ रहे थे कि आप बाबा साहब से इतनी नफरत क्यों करते हो तो ये मना कर रहे थे पर आज लोकसभा के अंदर अमित शाह जी ने एक ऐसा बिल पेश करके फिर से यह साबित कर दिया है कि जो कांस्टिट्यूशन में लिखा था 'to the people, by the people for the people' उसको उन्होंने आज कर दिया जव to the BJP by the BJP for the BJP अब डर लग रहा है

चुनावों से। जिसने काम किया हो उसको कोई डर नहीं होता अध्यक्ष महोदया पर काम नहीं किया क्योंकि बीजेपी पिछले लगभग तीन बार से एमसीडी के अंदर काबिज है और बदनामी इतनी है कि इनको खुद भी मालूम है। 07 तारीख को जब एग्जिट पोल के नतीजे आए सबको यह क्लियर हो गया कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी अपने इस काम के दम पर वोट मांगकर सरकार बनाने जा रही है तो इनको घबराहट शुरु हो गई। दो दिन के अंदर-अंदर 09 तारीख को ही जब इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की तारीखों का ऐलान करना था तो केन्द्र सरकार द्वारा एक चिट्ठी स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास चली जाती है और बहुत ही हैरानी इस चीज के ऊपर हुई कि जो एजेंसीज इंडिपेंडेंट मानी जाती थी वो पूरी तरह से इनके प्रभाव के अंदर दिखी और इलेक्शन कमीशन द्वारा यह कहा गया कि हमारे को रिप्रजेंटेशन प्राप्त हुई है केन्द्र सरकार की तरफ से और उन्होंने कहा है कि हमें तीनों नगर निगमों का एकीकरण करना है इसलिए चुनावों को फिलहाल टाला जाए हम इस पर लीगल ओपीनियन ले रहे हैं। अध्यक्ष जी बहुत ही कमाल की बात थी न उस लीगल ओपीनियन का कुछ पता लगा और संविधान को बार-बार तार-तार किया जा रहा है संविधान का आर्टीकल-243(यू) स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि कोई सरकार हो या कोई नगर निगम हो उसकी वैद्यता खत्म होने से पहले उसके चुनाव हर हाल में करवा दिये जाने चाहिए। 16 मई को इस नगर निगम का कार्यकाल खत्म हो रहा है उसके पहले संविधान के

मुताबिक चुनाव होने चाहिए थे पर आज क्या हुआ आज देश की संसद में एक बिल पेश कर दिया गया और हवाले दिये जा रहे हैं कि ये तो बहुत समय से पेंडिंग एक सुधार था जो होना था। अभी हमारे नेता विपक्ष जी ने भी बोला की जी बहुत पेंडिंग और बहुत बड़ा सुधार आज देश की संसद में होने जा रहा है। पूछो जी क्या सुधार होने जा रहा है तो उस चीज का कोई नहीं मालूम। सुधार के नाम पर क्या चीज है जो बिल में हमने पढ़ा इस बिल के अंदर मोटे तौर पर तीन-चार चीजें समझ आई कि वार्डो की संख्या 250 से अधिक नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या समझ आती है इसमें कोई वित्तीय बातों का जिक्र कर रहे थे जी दिल्ली सरकार ने पैसा नहीं दिया ये नहीं किया वो नहीं किया तो अब वित्तीय अरेंजमेंट क्या रहेगा उसका कोई जिक्र नहीं है। प्रशासनिक सुधार क्या होगा उस पर बिल्कुल खामोश है यह बिल तो बार-बार चीजों और इलेक्शन से भागने के लिए चीजों को दूसरे नाम देकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है और दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं अपनी सूझबूझ का प्रमाण इसके पहले भी तीन बारी दे चुके हैं। असल में इनको घबराहट इनको जब भी चुनावों की घोषणा आती है या चुनाव नजदीक आता है तो इनको बार-बार कभी 10 फरवरी, 2015 याद आ जाता है कभी 11 फरवरी, 2020 याद आ जाता है। एक बार 70 में से 03 सीटें आई, एक बार 70 में से 08 सीटें आई इनको अपनी वो जमानतें जब्त होना याद आ जाता है। इनको अब जो रिसेंट 10 मार्च को नतीजे आए

जिसमें 117 में से 95 सीटों पर जमानत जब्त हुई वो ध्यान आ जाता है तो लोकतंत्र में चुनावों से नहीं भागा जा सकता। ये जितनी मर्जी कोशिश कर लें जितना मर्जी गुमराह कर ले हर चीज का एक अंत होता है बीजेपी की तानाशाही का भी अंत अब नजदीक है और मैं सलाम करता हूँ अपने नेता को जो इतने विपरीत माहौल के अंदर भी डटे हुए हैं और अपने काम के दम पर इनको सबक सिखाने पर जुटे हुए हैं और मैं शुक्रगुजार हूँ उस परमात्मा का जो जनता का साथ हमको मिल रहा है उन कामों के दम पर वो इनकी मेन वजह है घबराहट की, वही वजह है। अब ये जब तक मर्जी अध्यक्ष जी इस चीज से भाग लें आज नही तो कल जब भी चुनाव होगा आम आदमी पार्टी पूरे बहुमत के साथ नगर निगम में आएगी और दिल्ली की जनता इनको इन नाकामियों का, इन नालायकियों का सिला देगी। मैं खुद अध्यक्ष महोदया दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली नगर निगम का सदस्य रहा हूँ। इतनी ज्यादा अगर भ्रष्टाचार की फैक्ट्री का मेरे को लगता है कोई नाम होना चाहिए तो वह नाम एमसीडी होना चाहिए। अध्यक्ष महोदया, दिल्ली नगर निगम के सदस्य जब दिल्ली नगर निगम को पूछते हैं मैं खुद इस चीज का प्रमाण हूँ कि कितनी बिल्डिंगें पिछले तीन साल में दिल्ली नगर निगम ने बुक की तो नगर निगम बता देता है जी इतनी संख्या में बुक की। उसके बाद पूछिये जी आज की डेट में इन बिल्डिंगों का क्या स्टेटस है तो उसका जवाब ही नहीं देता नगर निगम। इस चीज को लेकर पूरे नगर

निगम में कई बार हंगामे हुए पर नीचे से ऊपर तक सारे मिले होने की वजह से दिल्ली की जनता उस चीज का नतीजा भुगत रही है। जैसे मेरे से पहले मेरे साथी संजीव झा जी ने बताया कि बिल्डिंग डिपार्टमेंट हो उसके करप्शन से पूरी दिल्ली त्रस्त है। हेल्थ डिपार्टमेंट हो, सेनीटेशन डिपार्टमेंट हो एक भी डिपार्टमेंट एमसीडी का अगर सुचारु तरीके से काम करता तो ये भी दम रखते इस चीज के कहने का कि अगर एमसीडी के काम से खुश हो तो भाजपा को वोट दे देना नहीं तो वोट मत देना। मैं जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूँ कि जितनी सीटें थी सब पर इनकी जमानत जब्त होनी थी और इनके सर्वे में यह चीज आ चुकी थी इसलिए चुनाव से ये भाग रहे हैं और हर चीज का एक अंत होता है इस चीज का भी अंत जरूर होगा। भाजपा की तानाशाही से देश को जल्दी निजात मिले मैं इस चीज की भगवान से प्रार्थना करता हूँ और इस चीज की घोर निंदा करता हूँ जिस तानाशाही रवैये से भाजपा चुनाव से भाग रही है परमेश्वर इनको सद्बुद्धि दे। आज नहीं तो कल जब भी चुनाव होंगे दिल्ली की जनता सारी की सारी सीटों पर इनकी जमानत जब्त करवाकर इनको सबक सिखाएगी, बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।

माननीया अध्यक्षः बहुत-बहुत धन्यवाद जी, अब्दुल रहमान जी।

श्री अब्दुल रहमानः धन्यवाद अध्यक्ष महोदया, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं

सन् 2012 से और 2020 तक एमसीडी में रहा हूँ। 2017 में मैं लीडर अपोजीशन बना ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का। उसके बाद मैंने जो वहां के हालात देखे तो बड़ा अजीब सा माहौल एमसीडी के अंदर और सच्चाई यह कि उस वक्त में एक यह जो स्ट्रीट लाईट जगह–जगह लगी होती थी जो एमसीडी देखती है जिसे और उस स्ट्रीट लाईट को इन्होंने एक ई–कंपनी को दे दिया प्राइवेट कंपनी को। उस वक्त मैंने अपने बजट भाषण में भी कहा और बहुत उस पर शोर मचाया चूँकि हम संख्या में बहुत कम थे तो हमारी एक न चल पाई। लगभग 300 करोड़ रुपये का घोटाला अकेले ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर था और मैडम इनका लाईट लगाने का तरीका क्या था मैं आपके समक्ष वो रखना चाहता हूँ कि जितनी लाईटें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने लगाई थीं वो लाईट जिसकी कीमत लगभग 6 हजार, 7 हजार रुपये थी वो सारी लाईटें जो ई–कंपनी थी वो उतारकर अपने घर ले जाएगी और एक 800 से 900 रुपये की एलईडी लाईट वहां लगाएगी। सूर्या कंपनी की उन्होंने लाईट लगाई। जब हमने उसकी कीमत पता की तो 1800 रुपये उसकी कीमत दर्शा रही थी लेकिन वो कंपनी खुद बनाकर के लगा रही थी तो वह 800 रुपये में बनकर तैयार हो रही थी लाईट। इस तरह के घोटाले ये जनता पर भी उजागर हुए और एक भय अजीब से भाजपा के निगम पार्षदों के ही नहीं भाजपा के जो बड़े नेता हैं उनके अंदर इस तरह का बैठ गया कि अगर आम आदमी पार्टी जिसने देश की राजनीति को बदल डाला,

दिल्ली की राजनीति को बदल डाला अगर वो निगम में एक बार आ गई तो निगम में वो सारी परतें खोल कर रख देगीऔर फिर इनको कोई पानी पिलाने वाला मुय्यसर नहीं होगा यह अच्छी तरह जान चुके थे इस बात को। इसी को लेकर के ये चुनाव से भागे वर्ना अभी जैसे मेरे भाई ने कहा कि बिल्डिंग डिपार्टमेंट। कमेटी के अंदर तीनों कमिश्नरों को बुलाया गया विधान सभा कमेटी में और उनसे एक सवाल किया गया कि आज तक 2015 से और 2021 तक आपने किन-किन बिल्डिंगें बुक की और कितनी बिल्डिंगें सील की। सील बिल्डिगों का ब्यौरा दे दो। वो साहब कई महीनों तक चला और कई महीनों के बाद में फिर वो ब्यौरा कभी 15 दिन कभी 21 दिन फिर एक महीना 15 दिन ऐसे करते-करते लगभग सात महीने के बाद वो ब्यौरा आया कि ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कार्पोरेशन में दस हजार सात सौ बिल्डिंगें सील है। मैने पूछा मौके पर कितनी सील है। तो उन्होंने बताया जी इसका ब्यौरा तो जांच के बताऐंगे जी। कितने दिन में, कि जी पन्द्रह दिन में। चलिए बता दीजिएगा। फिर पन्द्रह दिन, पन्द्रह दिन, बीस दिन, पन्द्रह दिन चलते रहे फिर साढ़े चार महीने के बाद में उनका जवाब आया कि साहब 516 बिल्डिंगें सील हैं। दस हजार पांच सौ कुछ बिल्डिंगें थी उसमें बाकी सील है। तो वो सील किसने तोड़ी। एक आम आदमी तो ड़रता है सील तोड़ने से। होता क्या है वहां खेल। वहां मैने नजदीक से रहकर देखा, वहां खेल ये होता है कि इन्होंने अपने आदमी सेट किये हुए हैं। पार्षद बचते हैं और ये कराते क्या

हैं मैडम सुनने की बात है कि इन्होंने अपने कुछ आरटीआई कार्यकर्ता सेट किये हुए है मैम। उनके द्वारा कम्पलेंट कराते हैं और फिर जिस बिल्डिंग की कम्पलेंट हो गई उस पर जस्ट अगर इन्होंने रेट एक लाख लेंटर रखा हुआ है तो दो लाख हो जाता है। अब तेरी बिल्डिंग सील होने वाली है ये दे और अगर उससे पहले सेटिंग नहीं हुई तो सील कर देते हैं और सील करने के बाद में फिर उससे डबल पैसा वसूल कर वो जेई कह देता है तोड ले तँ हम बैठे हैं कुछ नहीं होगा। वो तोड लेते हैं इस तरह दस हजार बिल्डिंगों की सील पैसे ले लेकर तुडवाई गई। ये सारी चीजें जनता बारिकी से जान गई थी। इसी तरह जितने हमारे सफाई कर्मी भाई है वो एमसीडी में काम करना चाहते हैं। बड़ी लगन से काम करते हैं। लेकिन इनके पार्षद जानबूझकर उनसे कहते है कि तुम लाहौरी बनो। घर पर बैठो। हाँ लाहौरी एक शब्द है इनमें कि आप घर पर बैठो और हमें जो है तुम सिर्फ पांच हजार रूपया महीना दो बाकी पूरी तनख्वाह तुम ले जाओ तुम अपना दूसरा काम करो। इस तरह एक-एक वार्ड में अगर तीन सौ कर्मचारी हैं तो सौ कर्मचारी काम पर नहीं लेते ये। वो करना चाहते है ये करने नहीं देते। ये कहते फिर हमें पैसा कैसे मिलेगा। तो इतना भ्रष्टाचार जितना एमसीडी में हुआ है मै नहीं समझता कि भारत की राजनीति में या भारत के 29 स्टेटों में कहीं इतना भ्रष्टाचार होगा जितना अकेले दिल्ली के एमसीडी में हुआ है इन पन्द्रह सालों में। मैडम इन पन्द्रह सालों के भ्रष्टाचार का जब इन्होंने एक सर्वे करा कर देखा तो इनको पता

चल गया कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी 250 से 260 सीटें जीतने जा रही है और भाजपा मात्र 10 से 12 सीटों पर सीमटने वाली है और कांग्रेस जीरो से तीन सीट तक ला सकती है। तो ये खेल गए। खेल गए इन्होंने कहा फिर चुनाव ही क्यों कराएं। अगर हम हार रहे हैं तो, तो इन्होंने ये सारा शडयंत्र जो एक घंटा पहले नौ तारीख को चार बजे टेलीफोन करके पत्र लिखकर के चुनाव को टाला गया और इस प्रक्रिया को बदलने की कोशिश की जा रही है। ये सिर्फ इनका करा-धरा है जो इन्होंने किया है। जनता के सामने इनकी सच्चाई आने वाली थी इस डर की वजह से इन्होंने ये सब कुछ किया है। मैं समझता हूँ कि इस तरह अगर होता रहा कि भारत की राजनीति में संविधान के साथ खिलवाड़ा किया जाता रहा, चुनाव से भागा जाता रहा तो आज इन्होंने एमसीडी में किया है, कल किसी प्रदेश में करेंगे तो इस तरह इनकी मनमानी चलती रहेगी। लेकिन जो चीज पैदा है वो नपैदहै। चाहे फल हो फूल हो, पेड़ हो इन्सान हो, जानवर हो। जो आया है वो गया है। इनको इस चीज को नहीं भूलना चाहिए कि आज यूरूज पर हो, कल जमाल पर भी आओगे। तो मैं कहना चाहता हूँ आप से अध्यक्ष महोदया इन चीजों को संज्ञान में लेकर और इन पर कार्यवाही की जरूरत है कि इस तरह अगर देश में होता रहा तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। मैं अपने साथी जो विपक्ष के साथी हैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि अगर आप ये चाहते हो कि दिल्ली के अंदर सच्चाई से ईमानदारी से चुनाव हो

तो आपको भी इसमें हमारा साथ देकर दिल्ली के अंदर चुनाव कराना चाहिए। चुनाव सच सामने ले आएगा। कौन सही है कौन गलत है। अगर आप खुद भी ये चाहते हो कि दिल्ली में चुनाव हो और आपने अच्छा काम किया तो इसे परखने की इससे बड़ी कसौटी कोई नहीं हो सकती कि चुनाव में आओं और सामना करो और अपने आप को देख लो। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीया अध्यक्षः प्रहलाद सिंह साहनी जी।

श्री प्रलाद सिंह साहनीः आदरणीय अध्यक्ष महोदया मैं आपका ध न्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस मौके पर बोलने दिया। एक बहुत बड़ा मसला है ये। किन से उम्मीद कर रहे हो। आप लोग बड़े-बड़े भाषण दे रहे हो कि कार्पोरेशन में ये करप्शन हो गई यहां करप्शन हो गई। इनके राज में करप्शन है कहां नहीं, वो बता दो। जब इस देश को चलाने वाले वो ही तडीपार होंगे, देश को चलाने वाले जो होम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने इन कार्पोरेशन के इलेक्शन रोकने की कार्यवाही की है। तमाम हिन्दुस्तान के अंदर जो करप्शन का ढेर है वो सिर्फ कार्पोरेशन ही नहीं है। आज गुप्ता जी बड़े मजे से बोल रहे थे कि कार्पोरेशन के पास फंड्स नहीं है। फडिंग की कमी होने की वजह से भी एक ये फंडिंग क्यू रूक रही है। ये फंडिंग कहां से रूक रही है। कार्पोरेशन के अंदर एक जो बड़े प्लाट होते है उनको जब सब-डिविजन किया जाता है, पास किया जाता है उससे करोड़ो रूपये स्टैंडिंग कमेटी को मिलते हैं। आज

इनके राज़ के अंदर आप पूछो कितने सब-डिविजन हुई। हर नक्शे के ऊपर सौ-सौ गज का नक्शा सरल नक्शे के नाम से पास कर दिये जाते हैं। उनसे लाखों रूपये लिये जाते हैं और दो हजार गज का प्लाट अभी थोडे दिन पहले ही कश्मीरी गेट की न्यूज आपने सुनी होगी। एक बिल्डिंग गिरी तो मैं वहां मौके पर था, मैने मौके पर ही डीसी से पूछा, कहने लगा ये नक्शा पास है। मैने कहा किस तरह का नक्शा पास है। कहने लगा सरल के अंदर। यह प्लाट तो यहां स्कूल था। यहां अग्रवाल स्कूल चलता था। दो हजार गज का प्लाट है। उसके सौ-सौ गज के टुकडे करके इन्होंने इसके ऊपर दुकानें मार्केटे बनानी शुरू कर दी। सौ-सौ गज के ऊपर छः छः मंजिल मार्केट बनी है। आज भी रिकार्ड पर हम लोगों ने कई दफा कम्पलेंट की उसका कोई असर नहीं हुआ। दुर्गेश भाई ने मिटिंग की बताया गया कि इन जगह पर अन-ओथोराईज्ड कन्सट्रक्शन जितनी भी कार्पोरेशन के अंदर जाएं आप, आप अपने घर के लिए या किसी दुकान के लिए। मैडम एक गधे पर एक कट्टा सीमेंट का थोड़ा सा बदरपुर और थोडी सी ईंटी वगैरह लादकर जा रहे हो तो उसके पीछे हांकने वाला होना चाहिए। जो गधे को चला रहा हो। मगर वार्ड सिटी के अंदर उसके पीछे कार्पोरेशन का इन्सपैक्टर होता है। ये गधा किस के घर पर जा रहा है, क्या रिपेयर करेगा, क्या वहां काम करेगा, कितने पैसे मेरे को इसको लाने है वो वहां से पैसे ले आएगा। दूसरा पुलिस वाला जाएगा। तो कार्पोरेशन का जो फंड आना है जो स्टेंडिंग कमेटी की ये जो मामला था डिविजन

ऑफ प्लाट का करोड़ो अरबों रूपये की जितनी भी प्रोपर्टियां इन्होंने डिविजन किया है अगर उसको ये डिविजन करके पर्याप्त मात्र में उसका पैसा दिल्ली म्यूनिसिपल कार्पोरेशन को जमा होता तो कार्पोरेशन को पैसे की जरूरत ना होती। कार्पोरेशन को दिल्ली सरकार ये सैन्टर गवर्नमेंट की तरफ देखने की जरूरत नहीं होती। मगर कार्पोरेशन का वो पैसा जो सौ-सौ गज में सरल जोन में आता है वो इन लोगों की जेब में जाता है। बड़े-बड़े लीडरों की जेब में जाता है। बड़े-बड़े आफिसर्स की जेब में जाता है। उस पर वॉच रखने वाला कोई नहीं है। लगाया क्यूँ, कौन वॉच करेगा। आज हमारे मंत्री जो काम करते हैं। जितना काम उन्होंने किया है, यहां इलाके में जितने काम उन्होंने कर दिये, उन कामों से ये डरे हुए हैं। मैं यहां तक कहने के लिए तैयार हूँ। एक सीट भी दिल्ली के अंदर आप तो कहते हो पांच सात सीट मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह हमारे मंत्रियों ने यहां काम किया है, मैं अपनी बात कह रहा हूँ हमारे इलाके में जहां कमी भी, हमें पानी की दिक्कत होती थी। मैने एक बार मंत्री महोदय को कहा, मंत्री महोदय मेरे साथ थे। एक एक मकान पर खड़े होकर उन्होने मेरा काम करवाया। आज मेरे को उम्मीद है कि आने वाले चुनाव के अंदर देखेंगे हम कौन पार्टी दूसरी आती है। आज ये बड़ी छोटी पार्टी की बात कर रहे है। छोटी पार्टी, ठीक है हमारी मगर एक चींटी बहुत छोटी होती है। हाथी बहुत बड़ा होता है। चींटी अगर हाथी के सूँड में चली जाए तो उसको मार देती है। हमारी पार्टी चींटी की तरह

इनके ऊपर रहेगी। मेरे को ये नजर आता है इतना भी नहीं ये जो बैठे हुए है ना चुपचाप, इनको जंच नहीं रही है बात, चाचा जी जो है ना होम मिनिस्टर साहब जो वो कहेंगे इनको करना पड़ेगा। एक हमारे ओपोजिशन लीडर साहब की मजबूरी है। अब इनको रात को तो कुछ कहते है, सवेरे कुछ कहते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है ये दिल्ली म्यूनिसिपल कार्पोरेशन भ्रष्टाचार का जो है उसमें ये कुछ लाग नहीं लगाऐंगे। आज 204 की, 250 की जितने प्रोमिज कर रहे हैं, ना इनके बसका कुछ है, जो कुछ भी करेगा वो होम मिनिस्टर करेगा। कहां से पैसा आएगा, कहां से नहीं आएगा, होम मिनिस्टर करेगा। मगर इनको तो रात को अगर नींद खुल जाती है ना, घर के अंदर बिल्ली आ जाए और बिल्ली अगर बर्तन गिरा जाए तो इनको पता है नजर क्या आता है कि केजरीवाल आ गया, केजरीवाल आ गया। या कोई और मंत्री आपका आ गया, इनको डर सता रहा है। चुनाव ये, आज तो ये 2 साल तक भी चुनाव नहीं कराएंगे, मगर मैं इनको बताना चाहता हूँ आप 2 साल बाद कराओ, 4 साल बाद कराओ, जोये केजरीवाल बैठा है और जो ये हमारे मंत्री बैठे है ये आपका भोग डालकर ही जाएंगे। ये आपको कहीं टिकने देने वाले नहीं है, जिस तरह ये काम कर रहे है आज आम पार्टी का काम।

...(व्यवधान)...

माननीया अध्यक्षः कम्पलीट कीजिए साहनी साहब, साहनी साहब आप कम्पलीट करिए।

श्री प्रलाद सिंह साहनीः बेटा तू किसमें था, तू भी तो काँग्रेस में था, तू किसमें था, तू भी तो काँग्रेस से आया है, तू भी हमारी औलाद है, तू भी हमारी औलाद है। तू भी, बात सुन ले, तू भी हमारी औलाद है कांग्रेस से आया है और जो ये तेरे लीडर साहब है ना। leader sahab हमारा बड़ा भाई है, मगर ये भी कांग्रेस से आया है, ये तेरे को नहीं पता शायद पहले तेरे को ये नहीं पता होगा, पहले सोच के देख।

माननीया अध्यक्षः आप विषय पर वापस लोटें।

श्री प्रलाद सिंह साहनीः कांग्रेस में हम यहां आए है ना और कांग्रेस का वहां भोग पड़ गया, अब यहां तुम्हारा डाल देंगे।

माननीया अध्यक्षः प्रहलाद सिंह साहनी जी, विषय पर वापस लौटें।

श्री प्रलाद सिंह साहनीः अध्यक्ष महोदय, एक लाजपतराय मार्केट है जो लाल किला के ठीक सामने है। हाईकोर्ट के ओर्डर आए की यहां कोई अनोथराइज्ड कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। उसके अंदर दो-दो, तीन-तीन मंजिल गहरी खुदाई कर-कर उसके अंदर मार्केटें बना दी गई। ऊपर भी मार्केट बना दी गई, तीन मंजिल नीचे भी बना दी गई। उसके नोटिस इशू हो गए, नोटिस इशू हुए कम्पाउंड करने के

लिए, जब एक्ट में वो कम्पाउंड नहीं हो सकती, वो पैसा जो कम्पाउंड होने का पैसा है वो दिल्ली नगर निगम को जो जाना था वो इनके बड़े-बड़े नेता, उनमें सौदागिरी कर रहे हैं। हमारी पार्टी के लोगों का, हमारे मंत्रियों के लोगों का काम एक है, वो है काम करना। दिल्ली को किस तरफ ले जाना है, किस तरफ लोगों को जनता को, राहत मिल सकती है उसका काम करते हैं हमारे मंत्री, उसका काम करते हैं हमारे केजरीवाल साहब।

माननीया अध्यक्षः चलिए जी धन्यवाद।

श्री प्रलाद सिंह साहनीः आप लोग जो करते हो वो आपको मालूम है और आज मैं दावे से कहता हूँ एक लाजपतराय मार्केट नहीं, कई लोग हैं। ये भ्रष्टाचार का मामला आप लोगों के बीच में है। आज अगर मैडम एक बात मैं आपको और कहना चाहता हूँ, मंत्री जी जरा मेरी तरफ 2 मिनट के लिए ध्यान दें। दिल्ली म्यूनिसिपिल कार्पोरेशन के अंदर से, बिल्डिंग डिपार्टमेंट हटवा दो, बिल्डिंग डिपार्टमेंट दिल्ली म्यूनिसिपल कार्पोरेशन से हटा दो, ना कोई कमिश्नर वहां आएगा, ना कोई कार्पोरेशन का मैंबर वहां आएगा, इनकी सबकी निक्करें उतर जाएंगी। इन सबकी निक्कर, सबकी उतर जाएंगी।

माननीया अध्यक्षः चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री प्रलाद सिंह साहनी: और ये बैठे हुए है, तो सीटी बजा देते हैं, वो सीटियाँ बंद हो जाएंगी। तो मैडम यहां सिर्फ दिल्ली की क्यों बात कर रहे हो चुनाव, किस स्टेट में ये नहीं हो रहा। मैं अभी मंत्री जी ये कह रहा था कि जब हमारे आका, वो तड़ीपार हो, हमारे तड़ीपार क्या होता मैडम बोल रही थी, तड़ीपार वो होता है सबसे खतरनाक मुलजिम इलाके के अंदर हो, जिससे इलाके को डर हो। तो ये आदमी।

...(व्यवधान)...

श्री प्रलाद सिंह साहनी: बेटा तुम्हारे लिए तो केजरीवाल ही बहुत है, तुम्हारे सपने में तो वही बहुत है।

माननीया अध्यक्ष: अच्छा साहनी साहब खत्म कीजिए। बाकी सबको भी बोलना है।

श्री प्रलाद सिंह साहनी: तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, वो आदमी जिसके दिमाग में कूटकूट के भ्रष्टाचार भरा हो, वो इनका बॉस है। वो देखता है सारे दिन-रात में। रात को भी सो कर देखता है के किस कदर कहां बेईमानी हो सकती है। किस कद्र हम किसी को कोई नुकसान पहुंचा सकते है। अब वो नुकसान तो हो रहा है दूसरा, मगर एक छोटी सी पार्टी, जो केजरीवाल साहब की है। सबसे ज्यादा डर अगर किसी से है तो केजरीवाल से है। आज अगर जे इनको मैंने अभी बताया था, मैं इनको कह रहा था, इनके किसी घर के अंदर चाहे वो अपना इनके मुख्यमंत्री किसी

स्टेट के हों, इनके प्राइमिनिस्टर हो, इनके होम मिनिस्टर हों, घर के अंदर बिल्ली आकर बर्तन गिरा दे ना तो ये भी उठकर भागने लगते है, एक तरफ चारपाई के नीचे घुसते है केजरीवाल तो नहीं आ गया। इस कद्र खौफ इन लोगों के दिमागों में बैठा हुआ है।

माननीया अध्यक्षः चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री प्रलाद सिंह साहनीः धन्यवाद।

माननीया अध्यक्षः बहुत-बहुत धन्यवाद। कुलदीप जी।

श्री कुलदीप कुमारः धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। आज इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका देने के लिए, अभी बहुत सारे साथियों ने विस्तश्त में अपनी बात रखी और बताया कि किस प्रकार दिल्ली नगर निगम का जो भ्रष्टाचार का 15 साल का आयाम है वो किस प्रकार से दिल्ली में अपनी जगह बना चुका है और आज हमारे भाजपा के साथियों की इस एमसीडी को लेकर हालत ऐसी हो गई है कि उगलो तो शान गई और निगलो तो जान गई। ये बेचारे बीच में फंसे हुए है, ये करें क्या। चुनाव कराएं तो भी जाएंगे, नहीं कराएंगे तो भी जाएंगे। तो आज जो पिछले 8-10 दिन दिल्ली में ड्रामा चल रहा था केंद्र सरकार का के यूनिफाई करेंगे, एक करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हमें भी लग रहा था पता नहीं क्या करने वाले है। कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चुहिया। हमें लगा पता नहीं क्या करने वाले हैं, क्या बदलाव करने वाले हैं।

इन्होंने बदलाव क्या किया, तीनों को उठाकर एक कर दिया। लेकिन जब भी हम दिल्ली नगर निगम की बात करते हैं, तो दिल्ली नगर निगम जब-जब बात होती है तो जब-जब बात होती है, दिल्ली नगर निगम की पहचान अगर है तो वहां की साफ-सफाई और सफाई व्यवस्था से है और सफाई व्यवस्था को आयाम तक पहुंचाने वाले, उसको इस मुकाम तक लेकर जाने वाले दिल्ली के लाखों सफाई कर्मचारी, जो इस बात की मुझे कहते हुए दुख भी हो रहा है कि जब वो हमारे पास कार्यालय में आते थे। क्योंकि हम उस समाज से आते हैं, उस परिवार से आते हैं, वो लोग हमारे पास आते थे और वो लोग आकर हमसे कहते थे कि भईया आपकी दिल्ली में सरकार है लेकिन हमें पता है कि केजरीवाल जी के हाथ में कुछ भी नहीं है। केजरीवाल जी के हाथ में नगर निगम नहीं है लेकिन इस समाज का, इन लाखों कर्मचारियों का भला अगर कहीं से होगा तो एमसीडी से होगा और वो एमसीडी से कब होगा जब एमसीडी में आप लोगों की सरकार आएगी। वो लोग नजरें बिछाए हुए देख रहे थे कि कब दिल्ली का चुनाव आए और कब हम आम आदमी पार्टी की सरकार को नगर निगम में लेकर आएं। उनकी ये उम्मीद थी, उनको ऐसा लगता था। फिर एक नया शगूफा शुरू हुआ कि हम दिल्ली को यूनिफाई कर रहे हैं, उनको लगा चलो यूनिफाई कर रहे होंगे तो कुछ फंड-वंड भी आ रहा होगा। कुछ पैसा वैसा भी आ रहा होगा, बहुत से साथियों ने बताया, नगर निगम की सबसे बड़ी चिंता है वहां का फंड। गुप्ता

जी ने अभी-अभी कहा वहां की सभी की चिंता फंड है, फंडस के बिना कुछ भी नहीं है, पैसा होगा तभी एमसीडी चलेगी और वो पैसा आएगा कहां से। अब जब यूनिफाई हो जाएगी मुझे तो उस पूरे बिल के अंदर उन लाखों सफाई कर्मचारियों की जो समस्या थी जिसके लिए वो दिन-रात बैठकर ध्रना दे रहे थे, उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही है, उनके बच्चों को ट्यूशन की फीस नहीं जा रही है, उनके बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है, चार-चार महीने से, 6-6 महीने से उनकी तनख्वाह नहीं हुई है, उनको पक्का नहीं किया गया, क्या कह-कह के कि हमारे पास पैसा नहीं है। हम पर फंड नहीं है, अब फंड आपपर कहाँ से आएगा, अगर कार्पोरेशन को आप यूनिफाई कर देंगे तो आप पर फंड कहां से आएगा। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं नगर निगम का मैंबर रहा हूँ, मैं काउंसलर रहा हूँ, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन रहा हूँ और मैंने उस जगह पर देखा है कि सबसे बड़ी समस्या फंड की समस्या है, फंड का क्राईसिस है, लेकिन आज उन लोगों को भी धोखा देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने इस बिल को लाकर करने का काम किया है। लोकतंत्र के साथ-साथ उन लाखों लोगों के उम्मीदों के ऊपर पानी फेरने का काम इन लोगों ने करने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करने का काम किया। आज वो लोग जो पक्के होने की राह जोह रहे थे चुनाव होगा नहीं, पैसा आएगा नहीं, ना वो पक्के होंगे, ना उनकी तनख्वाहें मिलेंगी, ना उनके बच्चों के ट्यूशन की फीस

जाएगी, ना उनका घर का खर्चा चलेगा, तो क्या होगा, बताने के लिए कोई तैयार नहीं है। ना विपक्ष के साथ बताने को तैयार है जिन्होंने बिल लेकर आकर आए हैं, ना उनको पता है ना किसी को पता है आगे होगा क्या और दूसरी तरफ जब चुनाव की बात आती है ये चुनाव से भाग जाते हैं। देश की सबसे बड़ी पार्टी, किसी बीजेपी के नेता से पूछो कहेगा प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी, जिस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सबसे यही बात कहेंगे और हम सबसे बड़ी पार्टी हैं दुनिया की, ये देश की भी नहीं कहते, ये कहते हैं दुनिया की। ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी एक छोटी सी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल जी से डर कर भाग गए चुनाव से तो आप सोच लीजिए इनकी हालत क्या होगी। इनकी इतनी बेकार हालत है तो अध्यक्षा जी आज दिल्ली का सफाई कर्मचारी क्या पूछ रहा है। आज दिल्ली का सफाई कर्मचारी आप लोगों से कह रहा है:

''ना पूछो मेरे सब्र की इंतहा कहां तक है,
तू कर सितम तेरी हसरत जहां तक है
तू कर सितम तेरी हसरत जहां तक है,
वफा की उम्मीद जिसे होगी उसे होगी,
उन्हें तो देखना है तू बेवफा कहां तक है।''

उन्हें तो देखना है तुम्हारी बेवफाई कहाँ तक है। तुम्हारी ये जो चोर बाजारी है ये कहाँ तक चलेगी, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि दिल्ली के लोगों ने मन बना लिया है कि वह आपको उखाड़कर फेकेंगे। आप वार्ड 200 करो, 250 करो, 300 करो। एमसीडी को एक करो, एमसीडी को पांच करो। मैं दावे से कह सकता हूँ साहनी जी ने कहा है और साहनी जी कहते हैं,झूठ नहीं कहते। वो तो कह रहे हैं एक भी नहीं आ रही है। मैं कह रहा हूँ जमानत जब्त होगी आप लोगों की। आप लोगों की जमानत जब्त होगी और आपके करप्शन का आयाम क्या-क्या है? ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कारपोरेशन के अन्दर आज से दो साल पहले एक बिल आया। वो बिल क्या था? वो बिल ये था, सबको पता है, विपक्ष के साथी बैठे है। बहुत सारे यमुनापार से आते है। इनको पता है, वो बिल ये था कि एक मेट्रो वेस्ट कम्पनी को ये लोग लेकरके आये। उससे पहले खत्ते से कूड़ा उठाने का काम, ले जाने का काम एमसीडी करती थी, कर्मचारी करते थे, सफाई कर्मचारी करते थे। वो सब काम करते थे। इन्होंने एक बड़ा सा प्रोजेक्टर लगाया। उस प्रोजेक्टर के उपर दिखाया कि कैसे हम डोर-टू-डोर कलेक्शन करके घर से कूड़ा उठाने का काम करेंगे। बड़ी अच्छी पिक्चर थी। हमने विरोध किया। हम विपक्ष में थे। हम कुछ नहीं कर पाये लेकिन उसके बाद भी वो बिल पास हो गया। बिल पास क्या हुआ एक मेट्रो वेस्ट कम्पनी को जो काम 50 करोड़ में इडीएमसी करती थी जिस फण्ड की ये बात करते हैं, उस मेट्रो वेस्ट कम्पनी

को वो काम ढाई सौ करोड़ रूपये में दिया गया अध्यक्षा जी। ढाई सौ करोड़ रूपये में और मैं दावे से कह रहा हूँ इनकी विधान सभा वही पर है। ढाई सौ करोड़ रूपये खर्च हो रहे हैं लेकिन उसके बाद भी रिजल्ट क्या है? जीरो का जीरो। उन सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दी गयी। उन डीबीसी वर्करों की तनख्वाह नहीं दी गयी लेकिन ढाई सौ करोड़ रूपये का भुगतान उसमेट्रो वेस्ट कम्पनी को किया जा रहा है जो चार भाजपा के नेताओं ने मिलकर बनायी थी। उनको भुगतान किया जा रहा है और दिखाया क्या था? एक कूड़े वाला घर पर आयेगा। एक में गीला कूड़ा और एक में सूखा कूड़ा, एक में नीला कूड़ा, एक में पीला कूड़ा। आज तक किसी घर से कोई लेने आया क्या? डोर–टू–डोर कलेक्शन की ये लोग बात करते थे, कोई लेने के लिए आया? ये इनके भ्रष्टाचार का आयाम है और ये जिस बिलकी बार–बार बात करते हैं, एक बात बताता हूँ। जैसे चुनाव से पहले 9 फरवरी से पहले ये लोग एक घंटा पहले जब ये बिल लेकरके इन्होंने लेटर भेजा, ऐसे इन्होंने पहली बार नहीं किया अध्यक्षा जी। ऐसा ये कई बार कर चुके हैं। इडीएमसी के अन्दर, दिल्ली के अन्दर जितने टेन्डर की प्रक्रिया है मैं दावे से कह रहा हूँ। मेरे यहाँ एलेना स्लॉटर हाउस है। पूरी दिल्ली का नहीं पूरे आसपास का सबसे बड़ा स्लॉटर हाउस है वो। गाजीपुर स्लॉटर हाउस जो है मेरे यहाँ पर एलेना कम्पनी उसको चलाती है। क्या हुआ उसके अन्दर अध्यक्षा जी? उस स्लॉटर हाउस के अन्दर हर बार ये क्या करते

हैं। तीन साल में उसका टेन्डर रिन्यू होता है। जब भी अधिकारियों से पूछो, हम टेन्डर को आगे बढ़ा रहे हैं। क्यों बढ़ा रहे है? हम कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाये इसलिए उसको आगे बढ़ा रहे हैं। हर बार एक्सटेन्ड कर देते हैं। सेम वही खेल आज एमसीडी के अन्दर खेला जा रहा है और ये बहुत बड़े भ्रष्टाचार को आगे बढ़ावा देने का कारण बनेगा। मैं दावे से कह सकता हूँ और इन लोगों से मैं फिर कह रहा हूँ वो लाखों सफाई कर्मचारी, वो दिल्ली के लोग आपको, भारतीय जनता पार्टी के लोगोंको छोड़गे नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने सोचा था कि उनका उद्धार होगा। उनका उत्थान होगा लेकिन आप जो चुनाव से भाग रहे हो न वो आपको छोड़ने वाले नहीं। मैं पूरी जिम्मेदारी से इस सदन के अन्दर कह रहा हूँ क्योंकि उन लोगों की पीड़ा।

माननीया अध्यक्षः बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री कुलदीप कुमारः उन लोगों का दर्द आप लोग नहीं समझ सकते क्योंकि आपको शायद उनकी पीड़ा नहीं पता होगी। सुबह 7.00 बजे उठकर दिल्ली की सड़कों की सफाई करते हैं। अगर थोड़ी बहुत इज्जत अगर आपकी बची भी है न वो भी उन लोगों ने बचा रखी है। आपको बता दूँ मैं। वरना अगर वो लोग नहीं होते तो वो इज्जत भी आप लोगों की नहीं बचती और जो आपका ये भ्रष्टाचार का आयाम है ये टूटेगा जरूर। आप ढाई सौ करना, तीन सौ करना, छः करना, आठ करना। जमानतें जब्त होनी है। इस

बात में कोई दो राय नहीं है। मेरी बात लिखकर के आप ले लो। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत आभार।

माननीया अध्यक्षः थैंक यू श्रीमती प्रोमिला टोकस जी।

श्री प्रोमिला टोकसः धन्यवाद अध्यक्षा जी। अध्यक्षा जी मेरे बड़े भाई ओ.पी. शर्मा जी ने कल कहा थोथा चना और बाज घना। थोथा चना बाजता भी कहाँ पर है वो तो उनको अच्छी तरह पता है। जब थोथा चना बाहर जाकर बाजता है, अभी कल आतिशी जी ने बताया कि किस प्रकार से गुजरात में स्कूल बन्द हुए। वो थोथा चना वहाँ बाजके अपने गुजरात में स्कूलों में क्यों नहीं लेकरके गया। अपने जो एमसीडी के स्कूल हैं, विशेष रवि जी, यहाँ पर एमसीडी का स्कूल हैं जो इन्होंने बन्द कर दिया एमसीडी ने। वहाँ क्यों नहीं लेकरके गये उनको स्कूल दिखाने के लिए। कह रहे हैं कि स्कूलों में कुछ नहीं हुआ है। एमसीडी के स्कूल में लेकरके जाते आप। पता चलता क्या हुआ वहाँ पर, क्या नहीं हुआ। जिन स्कूलों को वहाँ पर आप बन्द कर रहे हैं, जो आपकी हेल्थ सिस्टम है, आप वहाँ पर जाकर के देखिये। न उसमें आपको दवाई मिलेगी, न वहाँ पर साफ-सफाई मिलेगी। न इनके एमसीडी केस्कूलों में कोई जाना पसन्द करता है, न एमसीडी के जो डिस्पेन्सरी है उसमें जाना पसन्द करता है और पिछली बार जब आये थे, जब इन्हीं के बड़े-बड़े लीडरों ने माना था कि जो हमारे निगम पार्षद है सारे भ्रष्ट है। नया चेहरा, नई उड़ान इस पहल के साथ ये आये

और इन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया, इतना भ्रष्टाचार किया क्योंकि अभी मैं ज्यादा बोलँगी नहीं, सबने इतना बोल दिया है। इतना भ्रष्टाचार, इतना भ्रष्टाचार, उन नये चेहरों ने इतनी बड़ी उड़ान भर ली कि उनको लैंडिंग की जगह नहीं मिल रही है। वो जमीन पर नहीं आ पा रहे हैं। उन्होंने इतनी ऊँची उड़ान भर दी कि कहाँ उतरे अब उसको कहाँ लैंड करें, इतनी भ्रष्टाचार की हद कर दी। अध्यक्षा जी मैं एक वाक्या बताना चाहूँगी। अपनी मेरी ही विधान सभा का एक कमरा बना रहे थे और उस कमरे के साथ में एक दूसरा भीकमरा बना रहे थे और एमसीडी ने शायद उसने पैसे दे रखे होंगे, ये मुझे नहीं पता है लेकिन एक का कमरा तोड़ दिया और एक का नहीं तोड़ा। तो ये हम सभी समझ सकते हैं कि उन्होंने कुछ न कुछ तो लिया होगा कि एक आमने-सामने कमरे बन रहे है, एक का तोड़कर चले गये और एक का नहीं तोड़ा। तो इतना भ्रष्टाचार ये इन्होंने किया है। उड़ान इनकी इसलिए ये चुनाव शायद नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि इतनी ऊंची उड़ान भरी वो कहाँ भी लैंड नहीं हुई है। इसलिए शायद इनको डर लग रहा है कि चुनाव कैसे कराये। जो वो उड़ान भरी है वो तो अभी नीचे आये नहीं है। अभी इनको पता है कि नीचे जमीन पर आये तो जो पर थे वो कट जायेंगे इनके। अब इस लायक छोड़ेगी नहीं दिल्ली की जनता। आप साफ-सफाई का हाल देखिये। इतना बुरा हाल है पूरी दिल्ली में। बीजेपी ने कूड़ा ही कूड़ा कर दिया। जहाँ पर भी देखेंगे वहीं पर बीजेपी का कूड़ा। जहाँ देखोंगे वहीं बीजेपी का कूड़ा।

काम करना चाह रहे हैं एमसीडी के कर्मचारी। वो तो काम करना चाह रहे हैं लेकिन जो उनके उपर भ्रष्ट पार्षद बैठे हुए हैं वो उनको काम करने नहीं दे रहे हैं। अब थोड़े दिन बाद बारिश आ जायेगी। अध्यक्षा जी, मेरे विधान सभा में 22 कलस्टर है और वो कलस्टर सारे नालों के उपर है, एमसीडी के नाले सारे उन्हीं के उपर है। बारिश आयेगी वहाँ पर इतना पानी भर जाता है, लोगों की झुग्गियों में पानी चला जाता है लेकिन वहाँ का जो पार्षद है वो वहाँ पर देखने तक नहीं जाता है। कोई भी अगर पार्षद के पास जाता है अपनी शिकायत लेकरके, एक तो मिलते ही नहीं पार्षद या बीजेपी के आप लीडर देखेंगे सारे रोडों पर टंगे मिलेंगे। जहाँ पर भी जाओगे सारे रोडो पर दिखेंगे। जमीन पर मिलता ही नहीं कोई। खम्भे पर टंगे मिलेंगे। नीचे जमीन पर कोई मिलता ही नहीं है।

माननीया अध्यक्षः चलिए प्रोमिला जी कम्पलीट कीजिए। कम्पलीट कीजिए मैडम।

श्रीमती प्रमिला टोकसः अध्यक्षा जी, इतना बुरा हाल है। अब इनको ये पता है कि अगर एमसीडी का चुनाव कर लिया तो इनकी हालत क्या होगी। अब हरियाणा में भी अब विधान सभा थी तो अब लोग ये कह रहे हैं कि या तो आप सुधर जाओ नहीं तो केजरीवाल यहाँ पर भी आयेगा। अभी हरियाणा में जब उनका सत्र चल रहा था तो जेजेपी का शायद विधायक थे उन्होंने कहा या तो

तुम सुधर जाओ, काम कर लो, न तो यहाँ पर भी केजरीवाल जी आने वाले हैं। ये डर, मतलब वो डर रहे हैं कि या तो काम कर लो या तो केजरीवाल की तरह काम करो, नहीं तो आपको सत्ता से ही बाहर होना पड़ेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीया अध्यक्षः बहुत-बहुत धन्यवाद मैडम।

श्रीमती प्रमिला टोकसः दो मिनट का ही। अध्यक्षा जी।

माननीया अध्यक्षः आतिशी जी।

सुश्री आतिशीः धन्यवाद अध्यक्षा महोदय कि आपने इस एमसीडी के यूनिफिकेशन के मुद्दे पर मुझे बोलने का मौका दिया। हमारे विजेन्द्र गुप्ता जी चले गये वरना उन्होंने कई चीज। बाहर से देख रहे हैं। चलिये वो अन्दर आ जाते तो हमें अच्छा लगता। तो जैसा आप जानती हैं अध्यक्षा महोदय कि 9 तारीख को, 9 मार्च को एमसीडी के चुनाव की घोषणा होनी थी। 9 मार्च को जो हमारे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं एस.के. श्रीवास्तव जी, उन्होंने कहा कि हम आज शाम को 5.00 बजे एमसीडी चुनाव की घोषणा करेंगे और एक प्रेस कांफ्रेंस का न्यौता दिया कि उससे दो दिन पहले वो पूरा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की गाईड लाइन्स, पद यात्रा हो सकती है कि नहीं हो सकती, रैली हो सकती है कि नहीं हो सकती, सारी गाईड लाइन्स निकाल चुके थे। उन्होंने सुबह मेसेज भेजा कि आज शाम को 5.00 बजे प्रेस कांफ्रेंस होगी और चुनाव

की तारीख घोषित की जायेगी। शाम की प्रेस कांफ्रेंस होती है। सारी मीडिया वाले वहाँ पहुंचते हैं तो वहाँ पर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बताते हैं कि हमें केन्द्र सरकार से एक चिट्ठी आयी है। वो चिट्ठी ये कह रही है कि हम तीनों एमसीडी को एक करना चाहते हैं और इसलिए आप चुनाव न करवाइए। हमें भी अचम्भा हुआ। हम भी चलिए पॉलिटिक्स में तो कुछ साल पहले ही आये हैं लेकिन इस देश की राजनीति को तो बहुत सालों से देख रहे हैं। हमने टी.एन. शेषन जी जैसे भी इलेक्शन कमिश्नर देखे हैं जिनका भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में उनकी चर्चा होती है। ये तो पहली बार सुनने को मिला कि सरकार इलेक्शन कमीशन को बता रही है कि आप चुनाव करवा सकते हो या नहीं करवा सकते हो क्योंकि हमारी तो देखिये जो थोड़ी बहुत कांस्टीट्यूशन की समझ है। ये अधिकार तो हमारा संविधान इलेक्शन कमीशन को देता है न कि पीएमओ को, न होम मिनिस्टर के ऑफिस को। तो वो चिट्ठी लिखकर कहते हैं कि चुनाव मत करवाओ। हम भी ये सोच में पड़ गये कि ऐसा क्या हो गया। क्योंकि अगर यूनिफिकेशन ही करवानी थी तो ऐसा थोड़ी है कि जैसे अभी विजेन्द्र गुप्ता जी बता रहे थे कि जी बहुत प्राब्लम है एडमिनिस्ट्रेशन में, चलती नहीं है तीन अलग-अलग एमसीडी, बहुत समस्या आती है। तो ऐसा तो है नहीं, एमसीडी में भी 15 साल से भाजपा की सरकार है। उन्होंने यूनिफाइड एमसीडी देखी है। उन्होंने ट्राफरकेटेड एमसीडी भी देखी है। पिछले 7 साल से केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। अगर

भाजपा को एमसीडी चलाने में इतनी ही दिक्कत आ रही थी तो पिछले 7 साल से हमें कभी ये सुनने को क्यूँ नहीं मिला, क्यूँ हमारे जो साथी विधायक यहां पर बैठे हुए हैं बहुत मुद्दे उठाते हैं, अलग अलग तरह की तख्तियां लेकर आते हैं, कभी भी इन्होंने ये नहीं कहा कि यहां पर विधेयक लेके आइए, एमसीडी को एक किया जाए, हमें बहुत परेशानी हो रही है। इनके पार्षदों ने कभी केंद्र सरकार को पत्र नहीं लिखा, इनके यूडी मिनिस्टर अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर बहुत प्रेस कांफ्रेंस किया करते हैं, उन्होंने कभी टीवी पर आकर नहीं कहा कि हमें बड़ी दिक्कत हो रही है। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया कि ये फिर रोज न्यूजपेपर में अलग अलग स्टोरी प्लांट करते थे कि हमें यूनिफिकेशन की क्यूँ जरूरत है। तो रोज एक अलग अखबार में एक अलग कहानी आती थी कि जी बहुत बड़े बड़े रिफार्म किए जायेंगे कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 को एक करना है बहुत बड़े बड़े रिफार्म हम करने वाले हैं। तो एक दिन ये स्टोरी आई कि जी मेयर का डायरेक्ट इलेक्शन होगा। तो एक दो दिन तक खबर में ये बात चली कि अच्छा जी हो सकता है मेयर का डायरेक्ट इलेक्शन हो। फिर एक दिन ये खबर प्लांट हुई कि बिल्कुल केबिनेट की तरह पावर दी जाएगी मेयर इन काउंसल का गठन होगा तो एमसीडी को जो अभी स्टेंडिंग कमेटी के माध्यम से काम करने में दिक्कत आती है वो दिक्कत भी चली जाएगी। हमने कहा अच्छा जी, हो सकता है बहुत बड़ा रिफार्म होगा। फिर ये खबर प्लांट हुई कि एमसीडी के पास पैसे

की बहुत समस्या है तो ऐसे प्रावधान होंगे कि पैसा सीधा केंद्र सरकार के पास आ जाएगा और ये सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। हमने कहा हो सकता है जी हो जाएं। तो आज सुबह जब लोकसभा में बिल पेश हो रहा था तो मैं बहुत उत्सुकता से इंतजार कर रही थी कि हमें भी जरा सुनने को तो मिले कि जो इतने बड़े बड़े रिफार्म होने वाले हैं, इतने बड़े बड़े बदलाव आने वाले हैं एमसीडी में तो क्या बदलाव आएंगे? तो जी बिल पेश हुआ। हम बड़ी उत्सुकता से देख रहे थे कि जी अभी पहला क्लॉज है, अब कुछ आएगा, अब दूसरा क्लॉज है, अब कुछ आएगा। लेकिन पूरा बिल पेश हो गया अध्यक्षा महोदय, उस बिल में एक भी रिफार्म नहीं आया। कुल मिलाकर वो बिल सिर्फ 3 चीजें कहता है, मतलब बड़े सारे पन्ने और बड़े सारे आप उनके क्लॉजिज सुनते रहिए, वो बिल सिर्फ 3 चीजें कहता है। वो एक चीज ये कहता है कि जी 3 अलग अलग एमसीडी थी वो 3 होके एक हो जाएंगी। अच्छा ठीक है जी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये था कि जी 3 सदन में वहां के पार्षद बैठते थे अब एक सदन में बैठने लग जाएंगे। तो इससे क्या सुधार आया ये स्पष्ट नहीं हुआ। फिर इन्होंने इनका दूसरा उसमें एक रिफार्म है कि जी पहले 272 वार्ड होते थे उनको चलाने में बड़ी दिक्कत होती थी अब हम एक बहुत बड़ा बदलाव करके 272 से 250 वार्ड पर ले आएंगे। ये कहा उस बिल ने। तो जी 272 से 250 में क्या अंतर हुआ, उसमें क्या रिफार्म हुआ, ये नहीं समझ में आया। फिर

असली मुद्दा उसके बाद आया, असली मुद्दा उसके बाद ये आया कि अब इस सारी प्रक्रिया में जब तक फिर से चुनाव नहीं होता तब तक केंद्र सरकार एक वायसरायनफमा एक एलजी नफमा अपना एक अफसर बिठाएगी जिसका नाम होगा स्पेशल आफिसर जो आने वाले कुछ सालों तक एमसीडी को चलाएगा। तो अब समझ में आया उस क्लॉज से कि ये जो पूरी कवायद हो रही थी ये सिर्फ दो कारण से हो रही थी। पहला कारण क्या था कि जी ये तो सब को पता है कि भाजपा ने क्या बढ़िया काम किया है पिछले 15 साल से। दिल्ली को इतना गौरव प्राप्त हुआ है 3-3 कूड़े के पहाड़ों का, दिल्ली को इतना गौरव प्राप्त हुआ है कि आपकी केंद्र सरकार की जो स्वच्छ रैंकिंग्स हैं उसमें नीचे से पहले नंबर पर दिल्ली की दो एमसीडी आई हैं। तो बहुत गौरव प्राप्त करवाया है भाजपा शासित एमसीडी ने। तो भाजपा को पता था कि अब जब चुनाव होगा तो लोग तो उन्हें निकाल कर बाहर फेंकने वाले हैं तो उन्होंने सोचा जी चुनाव तो जीत नहीं सकते, चुनाव जीतने का कोई तरीका नहीं है चुनाव को बस डिले करवा दीजिए। तो कुल मिला कर 272 से 250 वार्ड लाने में क्या होगा? उससे एक डिलिमिटेशन की प्रक्रिया फिर से शुरू होगी और जैसा हम सब को याद हे 2017 के चुनाव से पहले डिलिमिटेशन हुई थी और उस डिलिमिटेशन की प्रक्रिया को करने में डेढ साल का समय लगा था। तो अब इस बिल के तहत कम से कम डेढ साल का समय लगेगा जब तक नये वार्ड बनेंगे तो डेढ साल तक लोकतांत्रिक

तरीके से जो चुनाव होना था वो डेढ साल तक टल गया। दूसरी बात, अब जब तक डेढ साल तक चुनाव नहीं होता तब एक गैर लोकतांत्रिक अफसर जो किसी ने चुन कर नहीं भेजा, जो किसी इलेक्शन से नहीं आया, उसको केंद्र सरकार यहां पर बैठा देगी जो अब तीनों एमसीडी को चलाएंगे या एक एमसीडी को चलायेंगे। तो भाजपा का कुल मकसद इतना ही है कि चुनाव न करवाए, भाजपा का मकसद इतना ही है कि कैसे चुनावी प्रक्रिया को रद्द करके गैर लोकतांत्रिक तरीके से शासन चलाया जा सकता है और अध्यक्षा महोदय, डर हमें इस बात का नहीं है कि चुनाव में हार जीत किसकी होगी, इन्होंने इतना शानदार शासन किया है 15 साल का कि चुनाव तो ये जब भी करवाएंगे, जीतना तो आम आदमी पार्टी ने ही है। समस्या दूसरी है। समस्या ये है कि आज जब ये एमसीडी का चुनाव हार रहे हैं, जब इनकी एमसीडी की चुनाव में जमानत जब्त होने की हालत आ गयी है, तो ये एक बिल ला कर चुनाव को पोस्टपोन करा देते हैं, कैंसिल करा देते हैं। जब किसी राज्य का चुनाव हार रहे होंगे तो राज्य का चुनाव रद्द करवा देंगे, जब लोकसभा का चुनाव हार रहे होंगे तो Representation of People Act को बदल देंगे और लोकसभा का चुनाव कैंसिल करवा देंगे, ये समस्या है भाजपा की। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि इस देश की जनता बहुत समझदार है। इन्होंने पहले भी एक ऐसा प्रयास किया था 2014 में दिल्ली में जब इन्होंने राष्ट्रपति शासन जब ये लेके आए थे। जैसा आज हमारे भाई सौरभ भारद्वाज

जी ने आपको सुबह बताया मैं वही बात याद करवाना चाहूँगी कि आपका ये प्रयोग सफ़ल नहीं होगा। पिछली बार भी आने जितने दिन तक चुनाव टाला, 2013 में जब चुनाव हुआ था तो आम आदमी पार्टी की 28 सीटें आई थी, जब एक साल तक आपने गैर लोकतांत्रिक तरीके से राष्ट्रपति शासन लगाया तो दिल्ली की जनता ने भाजपा के मुंह पर तमाचा मारा और आम आदमी पार्टी को 67 सीटें दी और भाजपा को 3 सीटों पर लेकर आ गयी। आज चुनाव होता एमसीडी का तो हो सकता है 10-20 सीट आज जीत भी जाते, अब आप चुनाव को एक साल बाद करवाएंगे ये मेरा आपसे दावा है कि जैसे सिंगल डिजिट में आप इस विधान सभा में रह गए हैं दिल्ली की भी म्यूनिसिपल कारपोरेशन में अगर आप सिंगल डिजिट से उपर उठ जाएं तो हम अपनी राजनीति छोड़ देंगे, ये मैं आपको बता रही हूँ। शुक्रिया।

माननीया अध्यक्षः बहुत बहुत धन्यवाद। मदन लाल जी।

श्री मदन लालः थैंक्यू ऑनरेबल मैडम स्पीकर। आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। दिल्ली में 18 मई को एमसीडी का कार्यकाल खत्म हो रहा है। उससे पहले इलेक्शन की सारी तैयारियां इलेक्शन कमीशन ने कर ली थी। नोटिफिकेशन जारी होना था और अचानक पंजाब के रिजल्ट ने बीजेपी को डरा दिया। यही एक कारण था कि उसके तुरंत बाद उन्होंने यूनिफिकेशन के नाम लेकर इलेक्शन को टालने की पूरी कोशिश कर ली है और आज पार्लियामेंट में

Municipal Corporation Amendment Bill पेश कर दिया है। पास भी हो जाएगा, पास हो गया है। जब Amendment Bill की बात कर रहे थे तो उससे पहले हमारे होम मिनिस्टर से एक फ्रेस लिखा कि क्यों जरूरत है, क्या कारण हे कि हमको यूनिफिकेशन की बात कर रहे हैं। मैं उसकी दो लाईनें जरूर पढ़ना चाहूँगा। यहां कहते हैं statement of objectives and reasons पैरा 4 में कह रहे हैं the experience of the last ten years shows that the main objective of infrastructure, in trifuncation sorry, of creating compact municipalities in Delhi to provide more efficient civic services to the public has not been achieved क्या बढ़िया बात कर रहे हैं! ये पहली मर्तबा है कि देश का होम मिनिस्टर पार्लियामेंट में मान रहे हैं कि हम अक्षम हैं, हम Municipal Corporaton में काम सही तरीके से नहीं पाए हैं और हमने पिछले 10 साल इंतजार किया है और उसी अक्षमता के साथ हमने एमसीडी चलाई है। वो आगे और कहते हैं। वो कहते हैं कि instead या मैं पहले पढ़ दूँ आब्जेक्टिव, जो trifurcation का जो impact था municipalities का दिल्ली में वो जो efficient तरीके से बेसिक amenities को प्रोवाइड करने का, उसमें हम फेल हो गए हैं। वो लिखते हैं instead owing to inadequate in resource and uncertainities in fund allocation and release हमारे पास फंड नहीं थे, uncertainities थी उसके कारण हम जनता को वो वायदे जो हमने कहे थे, जो एमसीडी को करना था वो नहीं कर पाए हैं। इसका मतलब एमसीडी में बीजेपी पूरी

तरह फेल रही है ये मानते हैं। और जब ये मानते हैं कि हम फेल रहे हैं और कहते हैं हम रिफार्म करने के लिए इसको unification करेंगे तो उसके लिए जैसा हमारी बहन अभी आतिशी जी ने बहुत विस्तार से बताया। क्या रिफार्म की एक बात भी इस नए बिल में है? उन्होंने एक एक बात को बड़े तरीके से बताया, मैं नहीं कहूँगा औरये बात सही है कि कोई भी नहीं है, पर सवाल ये है बिल लाने की जरूरत क्या थी? ये बिल डिले करने के लिए नहीं ला रहे हैं क्योंकि डिले करने के बाद भी पता है उन्हें आम आदमी पार्टी ही जीतनी है। ये डिले इसलिए भी नहीं ला रहे हैं कि बीजेपी हार जाएगी। इस डिले के पीछे एक कारण है जो स्पेशल आफिसर अप्वाइंट होगा अभी यहां इन्होंने अपने जो बिल है उसका 514 अगर हम देखें तो स्पेशल आफिसर को अप्वाइंट करते हुए कहा कि वो उस समय तक 514 में कहते हैं। 'notwithstanding anything contianed in this Act, the Central Government may, if necessary, appoint a person to be called Special Officer to exercise the power in discharge of functions of the corporation until the date on which the first meeting of the corporation is held.' until the date वो कब आयेगी, इसकी चर्चा नहीं है, कोई चर्चा नहीं, until the new corporation starts और वो ऑफिसर क्या करेगा इतने दिन? जितने इनके पाप हैं तीनों कॉरपोरेशंस के, उनकी सारी फाइलों को खुर्दमुर्द कर देंगे। वो सारे पाप जिसके रहते इन्होंने गबन कियें। स्कूल के मास्टरों की फीस नहीं दी,

डाक्टर्स की फीस नहीं दी, नर्स की तनख्वाह नहीं दी। नदी–नालों की सफाई के नाम पर करोड़ों–करोड़ रूपये कमाये। यमुना की सफाई के नाम पर हजारों करोड़ खा गये। यहां नालों की जितनी कमी थी वो सारी सफाई, सब के सब पर इन्होंने केवल गबन किये हैं। उन सबको अब दबाना है और वो दबाने के लिए समय चाहिए। और समय केवल एक मिल सकता है कि आप इस इलेक्शन को डिले करो। अपना एक अफसर बैठाओ और उस अफसर के थ्रू जितने दिन आपको वो गबन को दबाने का टाइम चाहिए, उतने दिन वो गबन को दबा रहे।

यहां 3ए में कहते हैं कि with effect from such date as the Central Government may, by notification in the official gazette appoint, there shall be a Corporation charged with Municipal government of Delhi to be known as Municipal Corporation of Delhi.The Government means the Central Government. अब तक दिल्ली गवर्मेंट देखभाल कर रही थी, पैसे दिल्ली गवर्मेंट खर्च कर रही थी, चाहे वो सड़कों की सफाई का मामला हो, नालों की सफाई का मामला हो, चाहे वो सैलरी हों, चाहे वो बिजली की सैलरी हो, चाहे वो कोई और खर्चे हों, दिल्ली गवर्मेंट फंडिंग कर रही थी। सेंट्रल गवर्मेंट ने एक बार भी एम.सी.डी. की सुध नहीं ली। पर सवाल ये है इसमें तो कहीं ये भी नहीं लिखा कि सेंट्रल गवर्मेंट पैसे देगी। जब दिल्ली गवर्मेंट का डिपार्टमेंट नहीं रहेगा,

सेंट्रल गवर्मेंट फंडिंग नहीं करेगी तो फिर क्या होगा? फिर उसके लिए एक और नया प्रोविजन बना दिया है। एक प्रोविजन है 14(1) में, if any difficulty arises अब सोचा भई कल को फंड का चक्कर आयेगा, कल को शोर मचेगा एम.सी.डी. कैसे चलायेगी, कौन चलायेगा, ये तो प्रोवीजन ही नहीं था तो इतनी लम्बी मशक्कत के बाद जब आपको और आगे बढ़ाना हो तो एक clause डाल दिया 14 नम्बर, 14(1) में क्या लिखा है, 'if any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act,the Central Government may, by order published in the official gazette, make such a provision not inconsistent with the provision of this Act, as may appear to be necessary for removing the difficulty.' अब भविष्य में अगर कोई डिफिकल्टी आयेगी, जो आयेगी, फंड ही नहीं होंगे, सफाई नहीं होगी। एक पब्लिक ऑफिसर चलायेगा। 272 काउंसलर्स चला नहीं पा रहे थे, अब एक अफसर चलायेगा पूरी दिल्ली को और जब दिक्कत आयेंगी तो कह रहे हैं चिंता न करो एक अगला प्रोविजन है, 'every order made up this section, shall be laid as soon as may be after it is made before each house of Parliament.' हर ऑर्डर इसका पार्लियामेंट को जाएगा और यहां लिखा है 'providedthe order shall be made under this section after the expiry of a period of two years from the commencement of this Act' एक्ट चालू होगा, डिफिकल्टिस आयेंगी, 2 साल के भीतर-भीतर करना पड़ेगा। इसका मतलब 2 साल तो हमने ले लिये हैं। ये जानबूझकर कह दिया है

कि लोग uncertain न माने कि अगर कहीं कोई दिक्कत आई, कॉरपोरेशन न चल पाई, जो नहीं चलेगी क्योंकि फंड्स का एलोकेशन कौन करेगा? आपने गवर्मेंट कहकर कह दिया कि दिल्ली गवर्मेंट नहीं है तो अब तक जो एम.सी.डी. को दिल्ली गवर्मेंट सपोर्ट कर रही थी, जिसका ये बार-बार रोना रोते थे कि टीचर्स की सैलरी नहीं दे रहें, माननीय केजरीवाल जी कह रहे थे दे दी, हमने जितना देना था उससे 3 गुणा दे दिया, उसके बाद भी रोना रोते थे, पर अब तो रो ही नहीं पायेंगे, अब क्या करेंगे? अब तो दिल्ली गवर्मेंट तो देखभाल नहीं कर रही है क्योंकि दिल्ली गवर्मेंट को तो करना ही नहीं है। तो क्या सेंट्रल गवर्मेंट ने अपने ऊपर जिम्मेवारी ली है? नहीं ली है। तो कहां से लायेंगे? चोरी करेंगे, डकैती डालेंगे। एम.सी.डी. का काम पब्लिक को फायदा पहुंचाने का है, वेलफेयर देखने का है। पैसे का अरेंजमेंट स्टेट गवर्मेंट करे या सेंट्रल गवर्मेंट करे। यहां "state government" हटा दिया। सेंट्रल गवर्मेंट ने तो कभी एम.सी.डी. को सपोर्ट ही नहीं करा है। तो ये जानबूझकर 2 साल तक इस बात को लटकाये रहना है। मंशा केवल और केवल ये है कि एम.सी.डी. में बीजेपी के काउंसलर्स ने या बीजेपी ने जो भी पाप किये हैं उन्हें कैसे कंसील करें, कैसे छुपाये, कैसे उन सारे के सारे पेपर्स को वहां से हटाएं और जानबूझकर एक चुने हुए प्रतिनिधि जो चला सकते हैं उससे कैसे इसको हटाएं।

माननीय केजरीवाल जी कल सही कह रहे थे। कभी-कभी कुछ लोग हमारे दोस्त कहते हैं कि देश को खतरा है, देश पर हमला है, constitution नष्ट हो जाएगा, ये देश नष्ट नहीं होता, ये क्षण-क्षण करके बीजेपी नष्ट हो रही है, ये ही नष्ट होंगे, ये देश कभी नहीं हो सकता। न देश कभी नष्ट होगा, न constitution कभी नष्ट होगा।

माननीया अध्यक्षः कम्पलीट कीजिए सर।

श्री मदन लालः केवल बीजेपी नष्टहोगी। इसलिए आज के दिन सारी दिल्ली में केवल एकचर्चा है कि बीजेपी घबरा गई है। माननीय केजरीवाल जी के जिस तरीके से दिल्ली में विकास के काम चल रहे हैं उसको देखकर उनको डर लगने लगा है। अगर ऐसा न होता तो इसमें reforms की बात होती। कुछ प्रोविजंश जरूर होतें जिससे लगता कि पिछले वाले deliver नहीं कर पाये, नया कानून बनाया उससे deliver होगा। यहां ऐसाकुछ नहीं है। यहां केवल और केवल डिले करने की मंशा है जिसके पीछे केवल एक भावना है कि किसी तरह हमारे पापों का उजागर न हो जाएं और हमारे पाप सबको न दिखने लगें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

माननीया अध्यक्षः अभय वर्मा जी।

श्री अभय वर्मा: धन्यवाद मैडम। आज जब से ये चर्चा शुरू हुआ है तब से बार–बार नगर निगम चुनाव और बीजेपी भाग रही है, इन तीन शब्दों के अलावा कोई ज्यादा कुछ कहने का किसी ने जुर्रत किया नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि आज बिल भी पेश हो गया लोकसभा में, बिल की कॉपी भी सबके पास आ गई है तो थोड़ा सा इतिहास में जाने की जरूरत है। जब 2012 में इसी सदन में जो वर्तमान सरकार थी उन्होंने पूरी ताकत लगाकर जब निगम को 3 भाग किया था तब भी भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर प्रदर्शन कर रही थी कि आप नगर निगम को 3 हिस्से करके, दक्षिणी दिल्ली जो संपन्न ऐरिया है उसको आप अलग कर रहे हैं, नॉर्थ दिल्ली जहां पर सारी होस्पिटलें हैं बड़ी–बड़ी, उनको एक जगह कर रहे हैं और पूर्वी दिल्ली जो पिछड़ा हुआ दिल्ली है उसको आप अलग कर रहे हैं। कैसे चलेगा? तो वर्तमान मुख्यमंत्री ने वादा किया था कि जो फाईनेंशल कमीशन कहेगा वो हम पूरा करेंगे। और थर्ड फाईनेंशल कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दिये उसमें से 800 करोड़ रुपया आज 10 साल के बाद भी नहीं मिला है। हालात इतने बिगड़ते गए कि जैसे आज एक सम्भावनाएं जतलाई जा रही हैं न कि 'आम आदमी पार्टी' तो जीती ही हुई है, यही बात 2015 के बाद 2017 के चुनाव में भी कहे थे और क्या रिजल्ट हुआ था वो भी सबको पता है। तो भविष्यवाणी, आप भगवान नहीं है कि आप भविष्यवाणी सच करेंगे। आप बुरी तरीके से हार भी सकते हैं। मोदी सरकार..

...(व्यवधान)...

श्री अभय वर्मा: बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से हारेंगे, जब भी चुनाव होगा बुरी तरीके से हारेंगे, ये मैं भी इस सदन में कह रहा हूँ। और मैडम मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि आप हमें राजनीतिक, राजनीतिक सुझाव दे रहे हैं, मोदी सरकार वो सरकार है जो 2014 में जीतने के बाद 35 बरस के बाद दुबारा पूर्ण बहुमत से आई। और जिस पंजाब चुनाव की बात आप कर रहे हैं उसी समय 4 और राज्यों में चुनाव हुआ और चारों राज्य के मुख्यमंत्री फिर से दुबारा जीतकर आयें और चारों राज्य में सरकार बना, इवन कि गोवा में, गोवा में तीसरी बार बना।

...(व्यवधान)...

श्री अभय वर्मा: कोई बात नहीं। अरे व्यक्तिगत, आप व्यक्तिगत, सरकारों की बात चल रही है, सरकारों की बात चल रही है, व्यक्तिगत न जाएं।

...(व्यवधान)...

माननीया अध्यक्ष: कम्पलीट करने दीजिए। बहुत सारे साथी हैं बोलने वाले।

श्री अभय वर्मा: अध्यक्षा महोदय, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि गोवा में हम तीसरी बार सरकार बनाये है। उत्तर प्रदेश में दूसरी बार और उत्तराखंड और मणिपुर में भी दूसरी बार लगातार सरकार

बनाये है। तो ये भी काम का ही आवाज है जनता के द्वारा। और मैडम आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि थर्ड फाईनेंशल कमीशन का 800 करोड़ तो मिला नहीं, चौथा फाईनेंशल कमीशन आया, उन्होंने 6,000 करोड़ रुपया मदद करने के लिए नगर निगम को कहा। हाउस में भी आया लेकिन लागू नहीं किया गया। जब फिफ्थ फाईनेंशल कमीशन आया तो उन्होंने 13,000 करोड़ रुपया नगर निगम को मदद करने के लिए कहा, वो आज तक पटल पर रखने के बाद कुछ भी नहीं हुआ। मेरा ये कहना है कि अगर आज नगर निगम के बारे में केंद्र सरकार सोच रही है और इस परिस्थिति में आज नगर निगम खड़ा हुआ है तो इसका पूरा का पूरा दोष सामने बैठी सरकार है। अगर ये, राज्य सरकार अगर सिविक बॉडिस को समर्थन देती, उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलती तो शायद ये नौबत नहीं आता। आपको मैडम जब बकाया राशि के लिए बार-बार बात करने का प्रयास हुआ, लगभग 50 प्रदर्शन हुए हैं मुख्यमंत्री के निवास पर। और तीनों मेयर 13 दिन लगातार मुख्यमंत्री निवास के बाहर बैठे रहें। क्यों, क्योंकि इस financial crunch को ठीक कीजिए और राज्य सरकार और Civic body के बीच एक समन्वय बनना चाहिए। नहीं बनाने का रिजल्ट ये आया कि आज केन्द्र को interfere करना पड़ा और।

...(व्यवधान)...

माननीया अध्यक्षः हां हां दो मिनट में खत्म हो रहा है, तुम डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? दो मिनट में खत्म कर लेने दो।

श्री अभय वर्माः आपको मैं बताना चाहूँगा मैडम केवल financial commission की बात नहीं है। आप बजट लेके आते हैं 2019-20 में साठ हजार करोड़ का बजट है। निगम को आप देते हैं 6380 और जब 2021-22 उसके दो साल के बाद जब आप बजट पेश करते हैं तो आप बजट और कम कर देते हैं 6172 छह हजार एक सौ बहत्तर रूपया दे रहे हैं। इसका मतलब सीधा सीधा है कि आप चाहते थे कि निगम कैसे भी कुचल दें, खत्म कर दें financial power zero कर दें ताकि निगम चरमरा जाएगी और हम इस बात की वाहवाही लेंगे। आपने इतना ही नहीं किया।

माननीया अध्यक्षः कंपलीट करें।

श्री अभय वर्माः एमसीडी का जो global share था वो आपने साढे सत्रह परसेंट से घटा के साढ़े बारह परसेंट कर दिया। जो रोड़ बनाने का काम एमसीडी करती थी जिसके ढाई हजार करोड़ बजट थे उसको आपने मुख्यमंत्री सड़क योजना में ट्रांसफर कर दिया और पिक एंड चूज का काम वहां चल रहा है। इसके अलावा community center और rural development का जो 500 करोड़ रूपया बजट नगर निगम का होता था वो आपने खत्म कर दिया। प्रापर्टी सेल में जो तीन परसेंट नगर निगम को मिलता था वो भी आपने एक महीना, दो महीना डिले से देने के बाद उस पर भी आपने सर्विस

चार्ज आठ परसेंट लगाके दिया, ये दो सरकारों के बीच का ये कहानी है कि नगर निगम से आठ परसेंट सर्विस चार्ज दिल्ली सरकार वसूलती रही है। इससे ज्यादा हास्यापद कुछ नहीं हो सकता और बात चल रही थी काम करने की तो मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा कि एलईडी लाईट दिल्ली सरकार भी लगा रही है, मंत्री जी ने सदन में खड़ा होकर के कहा था कि हर विधान सभा में 3 हजार लाईटें लगेंगी। लेकिन अभी भी हम बीएसईएस के अधिकारियों से मिले, उन्होंने कहा 1500 से ज्यादा हम नहीं लगायेंगे जब तक हमें बजट नया नहीं मिलेगा और नगर निगम ने 5,86,000 एलईडी लाईटें लगा दी हैं। इसी तरह आपने एक भी स्कूल नहीं बनाया, सिर्फ कमरे की गिनती करवाते हैं आप। लेकिन नगर निगम ने 92 नये स्कूल बन के शुरू कर दिए। इसी प्रकार कूड़ा घर, जिस कूड़ेघर के कारण पाल्यूशन भी एक कारण था आज कूड़ामुक्त हो चुका है, कूड़ाघर मुक्त हो चुका है दिल्ली। लगभग 92 नए कंपेक्टर मशीन पूरे दिल्ली में लगाए गए हैं और लैंड फिल साईट की बात कर रहे हैं 15 मीटर कम किया गया है कूड़े के पहाड़ का। झूठ तो आप लोग सुबह से लगातार बोल रहे हो मैं तो केवल डाटा दे रहा हूँ। अरे संजीव जी, मैं डाटा दे रहा हूँ।

माननीया अध्यक्षः कंपलीट करिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।

श्री अभय वर्माः दो मिनट, दो मिनट।

माननीया अध्यक्षः धन्यवाद, ऋतुराज जी।

श्री अभय वर्मा: सिर्फ दो मिनट।

माननीया अध्यक्ष: अभी बोलेंगे आपके लीडर ऑफ अपोजिशन। बिधूड़ी साहब अभी बोलेंगे। बैठिए वर्मा जी बैठिए। ऋतुराज जी।

...(व्यवधान)...

माननीया अध्यक्ष: हां हां बोलिए, सुन रही हूँ। हां मुझे ही तो सुनाना है बोलिए।

श्री अभय वर्मा: मैडम, नगर निगम के कार्यशैली पर बात चल रही थी ये बात जरूर आना चाहिए रिकार्ड में। नगर निगम के कर्मचारी पूरे कोविड काल में संक्रमित कूड़ा उठाने का काम किया उन्होंने, पूरे दिल्ली की साफ सफाई की व्यवस्था उन्होंने देखा, पीडब्ल्यूडी के रोड्स को साफ किया, और सभी डिस्पेंसरीज से कोविड का टीकाकरण करने का काम नगर निगम ने किया। स्कूल से टीकाकरण करने का काम नगर निगम ने किया। स्कूल से टीकाकरण का काम नगर निगम ने किया लेकिन मोहल्ला क्लीनिक ने कुछ नहीं किया, मोहल्ला क्लीनिक ने कोई वैक्सीनेशन का काम नहीं चलाया और।

माननीया अध्यक्ष: कोई बात नहीं, सर बैठ जाइए आपका माईक भी बंद हो गया।

श्री ऋतुराज गोविंद: बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए बहुत बहुत ध

न्यवाद। जब 2017 में चुनाव हुए थे तो आदरणीय मनोज तिवारी जी इनकेप्रदेश अध्यक्ष थे। बोले पैसा सीधा उपर से लेकर के आएंगे और जनता के बीच में गए, लोगों को लगा कि हो सकता है गलती का प्रायश्चित कर रहे हैं, नए चेहरे भी लेकर के आए हैं और कह रहे हैं पैसा सीधा उपर से लाएंगे। लोगों ने वोट दे दिया और 5 साल तक क्या स्थिति रही है आप सबको अच्छे से पता है। अभी अभय वर्मा जी कह रहे थे फाइनेंस कमीशन ये कभी भी इनके भाषण सुनेंगे तो एक शब्द का प्रयोग जरूर करते हैं फाइनेंस कमीशन Finance Commission of India क्या कहता है कि 42 percent of the total stake will directly go to the State Government यानि कि अगर दिल्ली की जनता 100 रूपया टैक्स देती है तो 42 रूपया सीधा स्टेट को जाना चाहिए, देशभर में जाता है। दिल्ली को अठन्नी भी नहीं मिलता है। ये finance Commssion की बात करते हैं। आप हमको 42 प्रतिशत दिला दो, आप जितना मांग रहे हैं उससे डबल दे देंगे मुख्यमंत्री जी बहुत बार कह चुके हैं इस बात को। प्रॉब्लम क्या है? टेक्निकल बात, लीगल बात, सब लोग बोल रहे हैं इसमें मैं नहीं पड़ूगा। माजरा सारा पॉलिटिकल है। भारतीय जनता पार्टी शहरों की पार्टी मानी जाती है। शहर में ही यानि कि जो शहरी वोट है, अर्बन वोट है ये इसकी जड़ है। अभी तक ये खुश हो रहे थे, इनको लग रहा था हम कांग्रेस का वोट काट रहे हैं, हम बीएसपी का वोट काट रहे हैं इनको कोई फक्र नहीं पड़ रहा है। प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई? जब तक ये नूराकुश्ती पप्पू और गप्पू के बीच में चल रहा था तब तक सब बढ़िया था, जैसे ही ये विजय दीनानाथ चौहान दीवार कूद कर बीच में आया, दोनों को टेंशन हो गया है। ये विजय दीनानाथ चौहान दीवार तोड़कर कर के आपने देखा होगा 1970 की फिल्मों में क्या जैसे दीवार तोड़

के हीरो आता था, उसकी एंट्री होती थी, ऐसा ही कुछ एंट्री हुआ है। कैसे हुआ है आप समझिए। आप चंडीगढ़ में इनको हरा दिए, इकतरफा। आप दीवार कूदकर के सूरत में पहुंच गए, आप अलग अलग म्यूनिसिपल कारपोरेशन में जो ये एंट्री हो रही है आम आदमी पार्टी की, आप समझिए कि इनके पास हजार-दो हजार नहीं लाख दो लाख निक्करधारियों की फौज है जो सुबह सुबह इसी बात का मंथन करती है कि क्या होने वाला है। इनको ये समझ में आ गया है कि दिल्ली म्यूनिसिपल कारपोरेशन का मतलब है कि आप दिल्ली के अंदर आ रहे हैं ये तो बच्चा बच्चा बोल रहा है, लेकिन आने के बाद होगा क्या ये विजय दीनानाथ चौहान सबसे पहले एमसीडी के स्कूल को ठीक करेगा, एमसीडी के अस्पताल को ठीक करेगा, शहर को कचरामुक्त करेगा, लंदन जैसा साफ सुथरा शहर बनाएगा, तो उसके बाद 70 percent of the Municipal Corporation in India is hold by BJP उसका क्या होगा? जब रिफार्म आप दिल्ली में करेंगे तो उसका असर बंबई में भी होगा, उसका असर भोपाल में भी होगा, उसका असर गुजरात के अहमदाबाद में भी होगा, उसका असर सब जगह होगा और आप किसी कांग्रेस या किसी पप्पू और गप्पू को नहीं यहां पर आप सीधा बीजेपी को हरायेंगे, जिसका डर है, जिसके चलते ये सब ड्रामा हो रहा है। ये म्यूनिसिपल कारपोरेशन इलेक्शन के इंपार्टेंस को हमें समझने की जरूरत है और इसका इंपोर्टेंस सब ये पालिटिकल इंपोर्टेंस है जिसके चलते ये सब हो रहा है। अब इंपोर्टेंट बात समझिए। कोई कंपनी घाटे में जाती है, हम लोग बिजनेस स्कूल में पढ़े थे कि जब कोई कंपनी घाटे में जाती है फाइनेंस मिनिस्टर भी बैठे हुए हैं, और दिल्ली का सरकार जब इन्होंने टेकओवर किया था तो 8000 करोड़ का financial deficit शीला जी छोड़ के गयी थीं। लेकिन

8000 करोड़ के financial deficit को दिल्ली की सरकार पूरा करती है और आज सीएजी कहती है कि Delhi Government is only in India जोकि सरप्लस रेवेन्यू के साथ चल रही है। ये गर्व की बात है। क्योँकि हमने financial deficit को भी पूरा किया। आज जो भी कंपनी घाटे में चलती है हम लोग बिजनेस स्कूल में पढ़े थे कि उसको फायदे में लाने का केवल 3 ही तरीका है। एक आप कोस्ट कटिंग करिए, दूसरा आप जो है प्रोडक्ट का दाम बढ़ा दीजिए, तीसरा लीकेजिज को रोक लीजिए। यानि कि कोस्ट कटिंग करिए, यानि कि जो फिजूलखर्ची कर रहे हैं उसको रोकना पड़ेगा, प्रोडक्ट का दाम तो ये बढ़ा ही रहे हैं, हाऊस टैक्स और जितने भी टैक्स हैं उसको बढ़ाकर के। लीकेजिज जहां जहां पर जो ये पाईप लीक कर रहा है इसको ये रोक नहीं रहे हैं, कोई राकेट साईस नहीं हैं। ये जो पूरा का पूरा म्यूनिसिपल कारपोरेशन आज bankruptcy के कगार पर पहुंच गया है उसके पीछे इनकी मूर्खता है और कुछ नहीं है और लड़ाई इस बात की है कि ये लोग जब जब पप्पू और गप्पू के बीच में जहां जहां लड़ाई होगा वहां तो ये 80–20 कर लेंगे, वहां ये श्मशान–कब्रिस्तान कर लेंगे, वहां ये कुछ भी करके जीत जायेंगे लेकिन जब जब लड़ाई ये विजय दीनानाथ चौहान से गप्पू का होगा तो उसका क्या होगा कालिया आप समझ सकते हैं। तो सारा मसला ये है। तो आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, आप सोचिए हिन्दुस्तान के अंदर उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। उतराखंड है, मणिपुर जीते हैं, और चौथा राज्य कौन है वो – गोवा जीते हैं। 4 स्टेट जीतने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी की ऐसी हालत हो रखी है जो म्यूनिसिपल कारपोरेशन के चुनाव से भाग रही है। आप इसी से इस बात के महत्व को समझ सकते हैं कि किसी भी हालत में ये अभी चुनाव करवाने के पक्ष में नहीं हैं और

ये इस लोकतंत्र के लिए, जनतंत्र के लिए और हमारे संविधान जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि ये बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत बड़ा अपमान है, उन लाखों वीर सिपाहियों का अपमान है, उन लाखों हमारे सेनानियों का अपमान है, शहीदों का अपमान है जिन्होंने अपना जान देकर के इस देश के अंदर में आजादी ली, लोकतंत्र की स्थापना करी और आज हम लोग सब एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर रह रहे हैं लेकिन उस लोकतंत्र की हत्या करने का काम कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, देश का बच्चा बच्चा देख रहा है। आप चाहे कितने भी कुछ समय के लिए खुश हो जाओ लेकिन अब म्यूनिसिपल कारपोरेशन के अंदर में आम आदमी पार्टी आकर रहेगी, हम आपको सूरत में भी हरायेंगे, हमने आपको चंडीगढ़ में हराया और देश के तमाम 70 प्रतिशत से ज्यादा म्यूनिसिपल कारपोरेशन जहां पर भाजपा काबिज है वहां पर आम आदमी पार्टी की एंट्री होगी, इसी बात का डर है जिसके चलते इस चुनाव को टाला जा रहा है, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ धन्यवाद।

माननीया अध्यक्ष: धन्यवाद। बिधूड़ी जी।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: आदरणीय अध्यक्ष महोदया, श्री प्रह्लाद सिंह साहनी जी, जो इस हाउस के ऑनरेबल मेम्बर हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के बारे में जो भावना व्यक्त की है, मैं उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं समझता हूँ। इस हाउस के सभी ऑनरेबल मेम्बर्स के लिए वे दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें, यही ईश्वर से, वाहेगुरू से प्रार्थना करता हूँ।

अध्यक्ष महोदया, तीनों नगर निगमों के स्थान पर एक नगर निगम बनाने की जो केन्द्र सरकार की योजना है। मैं इतना कह सकता हूँ दिल्ली वासियों की बेहतरी के लिए ये कदम हमारी केन्द्र सरकार ने उठाया है और मैं इस हाउस के अंदर जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ कि कुछ समय के बाद दिल्ली के लोग, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी को बधाई देंगे, शुभकामनाएं देंगे और उनका धन्यवाद करेंगे कि उनकी सरकार के द्वारा जो कदम उठाया गया, वे दिल्ली के हित में था।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदया, आखिर जो परिस्थिति पैदा हुई इसके लिए कौन जिम्मेवार है। मैं आज इस हाउस में कह सकता हूँ कि आज नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी है। हो सकता है कि कल आम आदमी पार्टी आ जाए। दिल्ली सरकार में आज आम आदमी पार्टी है, हो सकता है कल भारतीय जनता पार्टी आ जाए। लेकिन ऐसी व्यवस्था देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं कि नगर निगम में कोई पार्टी हो, दिल्ली सरकार में कोई पार्टी हो, लेकिन फंड्स को लेकर किसी तरह का टकराव नहीं होगा। दिल्ली में इंटरनेशनल कम्युनिटी रहती है। जब हम इन छोटी छोटी बातों के लिए झगड़ा करते हैं तो पूरी दुनिया में हमारी छवि खराब होती है। ये छवि खराब न हो और नगर निगम स्मूथली काम करे वगैर किसी टकराव के काम करे, इसके लिए कदम उठाया गया है।

अब चर्चा हो रही है कि चुनाव होते तो आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत हासिल होता। ये बात तो 2017 में भी आम

आदमी पार्टी कह रही थी। लेकिन तीसरी बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई और मैं आज इस सदन में कह रहा हूँ कि जल्दी चुनाव होगा और चौथी बार भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में शानदार जीत हासिल करेगी। मैं आज इसबात को कह रहा हूँ।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदया, देश को पूज्य बाबा साहब ने शानदार संविधान दिया। हम सभी उनका सम्मान करते हैं। दुनिया उनका सम्मान करती है। लेकिन, दिल्ली सरकार ने नगर निगमों को उनके हिस्से का जो पैसा नहीं दिया, कहीं न कहीं बाबा साहब के संविधान का उल्लंघन हुआ है।

आदरणीय अध्यक्ष महोदया, दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को डायरेक्शन्स दी कि नगर निगमों का पैसा जारी किया जाए। दिल्ली के उपराज्यपाल को हम सभी लोग बहुत आदर करते हैं। उपराज्यपाल महोदय ने चिट्ठी लिखी और इसके साथ साथ 5 अप्रैल, 2021 को क्या कहा है हाई कोर्ट ने, एमसीडी कर्मचारियों को तय वक्त पर सैलरी न मिल पाने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि अखबारों में पूरे पन्ने का विज्ञापन देने के लिए सरकार के पास पैसा है, लेकिन निगम को देने के लिए नहीं है। हाई कोर्ट ने ये भी कहा और तल्खटिप्पणी में कहा कि क्या ये अपराध नहीं? ऐसे मुश्किल वक्त

में भी आप पैसा विज्ञापन पर खर्च कर रहे हैं। कोर्ट ने आदेश दिया कि आज ही सभी सफाई कर्मचारियों को मार्च तक का वेतन दिल्ली सरकार तुरंत जारी करें। ये हाई कोर्ट ने कहा है 5 अप्रैल को आप बताइये कि सफाई कर्मचारियों के वेतन किसके द्वारा रोका जा रहा था।

आदरणीय अध्यक्ष महोदया, तीसरे वित्त आयोग का जो समय था वो 2011 में पूरा हो गया। चौथा वित्त आयोग दिल्ली की तीनों नगर निगमों को अलग से 4 हजार करोड़ रुपया देने का प्रावधान करता है। 4 हजार करोड़ रुपया नहीं दिया गया और जो पांचवा वित्त आयोग है, उसने कहा कि दिल्ली सरकार 40,561 करोड़ रुपया दिल्ली नगर निगमों को देगी। लेकिन दिया कितना, केवल 21,056 करोड़ रुपया।

आदरणीय अध्यक्ष महोदया, धन जुटाने के लिए एमसीडी ने नगर पालिका बॉन्ड जारी करने का इरादा किया। उसके लिए दिल्ली की सरकार से अनुमति मांगी। दिल्ली सरकार ने अनुमति नहीं दी।

आदरणीय अध्यक्ष महोदया, कोरोना काल में इन तीनों नगर निगमों के डाक्टर्स, नर्सेस, सफाई कर्मचारी, शिक्षक, माली, मलेरिया कर्मचारी कोरोना पीड़ितों की सेवा करते हुए, उनको कोरोना महामारी से बचाते हुए कोरोना से पीड़ित हो गये और बाद में शहीद हो गये। दिल्ली के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने घोषणा की थी कि हम डाक्टर्स को, नर्सेस को, सफाई कर्मचारियों

को, मलेरिया कर्मचारियों को जो शिक्षक कोरोना महामारी से लोगों को बचाने में लगे हुए हैं, यदि कोरोना से उनकी मृत्यु हो जाएगी तो उनको एक एक करोड़ रुपया देंगे।

आदरणीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से दिल्ली के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से मांग करता हूँ कि इसमें जो भी हमारे सफाई कर्मचारी हैं, डाक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, जिनकी मश्त्यु हुई हैं, जिनको एक एक करोड़ रुपया सरकार की ओर से मिलना चाहिए। ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहां बैठे हुए हैं। इसमें राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। उन सभी कोरोना योद्धाओं को जो शहीद हो गये हैं, उन्हें सरकार की ओर से एक एक करोड़ रुपया दिया जाना चाहिए।

आदरणीय अध्यक्ष महोदया, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब भी यहां बैठे हैं। ऑनरेबल यूडी मिनिस्टर, हैल्थ मिनिस्टर यहां बैठे हुए हैं। मैं आज इस हाउस में बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ कि इनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि दिल्ली की अन-अथोराइज कॉलोनी में, रिसेटलमेंट कॉलोनी में और झुग्गी-झोपड़ी में जो सफाई कर्मचारी सफाई की व्यवस्था कर रहे हैं, उनकी सैलरी दिल्ली सरकार की ओर से दी जाती है। 2018 से सफाई कर्मचारियों की सैलरी बंद कर दी। आप अपना रिकॉर्ड चैक कर लें। अगर मेरी उसमें कोई गलती होगी, मैं इस हाउस में खड़े होकर माफी मागँगा। मैं इसको चुनौती दे रहा है। देखिये अन-अथोराइज

कॉलोनी नगर निगम को ट्रार्स्फर नहीं हुई और जब तक ट्रांर्स्फर नहीं होगी तो सफाई की व्यवस्था दिल्ली की सरकार देख रही थी और दिल्ली की सरकार के आग्रह पर...

...(व्यवधान)...

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः अब ऐसा कोई थर्मा मीटर बना नहीं है जो मेरी छाती में भी लगाया जाए और आम आदमी पार्टी के ऑनरेबल एमएलए हैं, उनकी छाती पर भी लगाया जाए। उनके दिल में जितना दर्द है सफाई कर्मचारियों के प्रति हमारे दिल में भी उससे कम नहीं है।

लेकिन दिल्ली में Municipal Corporation नए प्राइमरी स्कूल्स बनाये, डिस्पेंसरिज़ बनाये, सफाई की व्यवस्था का बेहतर करे और दिल्ली की सरकार एक रणनीति के तहत जो पैसा दिल्ली नगर निगमों को दिया जाना चाहिये वो पैसा जारी न किया जाये। बाबा साहब का संविधान क्या कहता है कि जो टोटल दिल्ली सरकार के पास टैक्स का पैसा आता है उसमें से 17 परसेंट आप दिल्ली नगर निगमों को दोगे ये है बाबा साहब का संविधान जिसको आप नहीं मान रहे हैं। आप इसको वैरिफाई कर लीजिये कि आखिर बाबा साहब का संविधान क्या कह रहा है। अरे भाई आप हमारे साथ झगड़ा करो, आप हमारे ऊपर आरोप-प्रत्यारोप करो, हम चुनाव में मजबूती से लड़ेंगे, एक-दूसरे के चिालाफ जो कुछ कहना हुआ कहना होगा लेकिन मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ अरे इन सफाई

कर्मचारियों का, इन मलेरिया के कर्मचारियों का, ये जो हमारे शिक्षा के डॉक्टर्स, नर्स इन्होंने कौन सा कसूर किया था कि अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना पीढ़ितों की जान बचाई और जान बचाते हुये कोरोना से पीड़ित हो गये शहीद हो गये तो उनके साथ ये नाइंसाफी मत करो समय पर उनका वेतन दो और जो शहीद हो गये हैं अपने वायदे के मुताबिक उनको एक-एक करोड़ रुपया जारी करो, मैं उपाध्यक्ष महोदया ये आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहता हूँ। चुनाव आयेंगे जायेंगे कोई जीतेगा कोई हारेगा, आपकी हमसे लड़ाई हो सकती है हमारी आपसे लड़ाई हो सकती है लेकिन नगर निगमों में जो मेहनतकश लोग हैं उनके साथ यदि कोई सरकार नाइंसाफी करेगी वो तो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय उपाध्यक्ष महोदया आपके प्रति बहुत आभार व्यक्त करते हुये।

माननीया अध्यक्षः बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः इस हाउस के सभी ऑनरेबल मैम्बर्स के प्रति बहुत आभार व्यक्त करते हुये कि मुझे उन्होंने बोलने का अवसर दिया है थोड़ा-थोड़ा interrupt करते रहें उतना तो अधिकार है, करते रहिये लेकिन मैं आपको कमिट करता हूँ कि आप जब भी कुछ बोलेंगे मैं आपको interrupt नहीं करूंगा ।

माननीया अध्यक्षः चलिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: इन्हीं शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदया।

माननीया अध्यक्ष: माननीय मंत्री सतेन्द्र जैन जी।

माननीय स्वास्थ्य मंत्री (श्री सत्येन्द्र जैन): आदरणीय अध्यक्ष महोदया अभी विपक्ष के हमारे साथियों ने बार-बार कुछ चीज़ें कहीं, एक तो बार-बार कह रहे हैं कि भई तीनों निगमों ने बड़ा अच्छा काम किया, बड़ी तारीफें कीं सब काम बड़े अच्छे किये, समझ नहीं आया confuse कहां हो गये हैं। एक चीज़ का जिक्र नहीं है, कुत्तों के बारे में बात नहीं कीं बाकी सारी बात कर ली, ये बड़ा अच्छा काम किया। भई अगर निगमें इतना अच्छा काम कर रही थीं तो फिर निगमों को काहे को इकट्ठा कर रहे हो और इकट्ठा कर रहे हो तो इसका मतलब खराब काम कर रही थीं। तो अपना पहले फैसला कर लो कि सही बात कहां थी गलत बात कहां थी। इन्होंने बार-बार बता दिया इकट्ठा करने से ये होगा वो होगा भई पहली बात तो सात साल थे आपके पास, केन्द्र में सात नहीं आठ साल हो गये अब तो। केन्द्र में आपकी आठ साल से सरकार है और एम.सी.डी. में 15 साल से है तो आठ साल में कभी भी कर लेते हमसे तब भी नहीं पूछना था अब भी नहीं पूछा आपने, ये तो नहीं कह सकते कि हमसे पूछना था जी हमने परमिशन नहीं दी। हमारे परमिशन से तो आज भी नहीं कर रहे, अगर करना था एक साल पहले, दो साल पहले, तीन साल पहले, पांच साल पहले,

सात साल पहले कर लेते। कहानी वो नहीं है कहानी कुछ और है। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि उन्होंने उनके नेताजी ने कहा हम ऊपर से पैसा लेकर आयेंगे। पिछले इलैक्शन में दो ही बातें थीं न कि एम.सी.डी. में सारे अपने candidate बदल दिये सारे, सारे councillor बदल दिए भई क्यों बदले, जोर से बोलो।

...(व्यवधान)...

माननीय स्वास्थ्य मंत्री (श्री सत्येन्द्र जैन): उन्होनें कहा था हमने नहीं कहा था आप ही लोगों से कहा था कि सारे बदल डाले क्योंकि सारे के सारे

...(व्यवधान)...

माननीय स्वास्थ्य मंत्री (श्री सत्येन्द्र जैन): और दूसरी बात क्या कही थी ऊपर से पैसा लेकर आयेंगे। अब करने क्या जा रहे हैं ऊपर डायरेक्ट पैसा लेकर जायेंगे। अब इनको पता लग गया जो पहले काउन्सलरों ने बिचारों ने मेहनत करके दस-दस साल में जितना कमाया था जो नये वाले आये उन्होंने दो-दो साल में उससे ज्यादा कमा लिया और ऊपर से दिया भी नहीं। कहते हैं क्योंकि तुम तो हटा ही दोगे, फिर से टिकट तो मिलेगा नहीं, कह दो ऊपर नहीं देते हम। टिकट दोगे तो देंगे वरना नहीं देंगे। तो इन्होंने क्या किया ऐसा बिल लेकर आये कि अब कलैक्शन सीधी डायरेक्ट होगी ऊपर। डायरेक्ट कलैक्शन और डायरेक्ट कलैक्शन करने के लिए इन्होंने क्या किया है कि निगमों को एक करने के बाद

इन्होंने कहा है कि एक केन्द्र सरकार एक ऑफिसर नियुक्त करेगी जिसको Director Local Bodies केन्द्र सरकार नियुक्त करेगी और वो तीनों निगमों के ऊपर पूरे अधिकार रखेगा। Elected body के अधिकार नहीं होंगे, उसके सारे अधिकार होंगे। भई जो सबका transfer करेगा posting करेगा सबके ऊपर अधिकार रखेगा तो कलैक्शन भी वही करेगा। तो वसूली केन्द्र बनाने के लिए ताकि सारा पैसा सीधा ऊपर जाये उसके लिए ये एक काम किया गया है इस एक्ट के अंदर इसके अलावा कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं बताया उन्होंने कि सफाई कैसे करोगे जी, इन्होंने ये नहीं बताया कि एम.सी.डी. को पैसा कहां से आयेगा जी, सबको पता है एम.सी.डी. की सबसे ज्यादा कमाई किस चीज़ में है?lanter. Lanter माफिया कहते हैं ना, lanter का रेट पूरी दिल्ली में एक lanter का रेट 50 हजार रुपये से लेकर पांच लाख रुपये lanter रेट है।

...(व्यवधान)...

माननीय स्वास्थ्य मंत्री: एक lanter का, पांच lanter डलते हैं तो पच्चीस लाख रुपये मतलब पांच लाख रुपये दस लाख रुपये बीस लाख रुपये, पच्चीस लाख रुपये और तो और जो हमारे विपक्षीय साथी बैठे हैं बेचारे बोल नहीं सकते अगर इनके किसी रिश्तेदार का घर बन रहा हो ना, तो कहते हैं भाईसाहब 25 लाख का काम था 20 में करवा देंगे इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक को नहीं छोड़ा इन्होंने किसी को। बस डिस्काउंट दे देते हैं थोड़ा-बहुत और वो भी कहते हैं जी आप तो इतने बड़े नेता हो उसमें थोड़ा

सा डिस्काउंट दे दिया बाकी आगे बात मत करना, टिकटकी कोई गारंटी नहीं है, जो करना हो कर लेना। भई Councillor तो चौड़े हो गये वो कहते इन्होंने नया तरीका निकाल लिया टिकट तो देते ही नहीं दौबारा, तो इतने पैसे कमा लो, इतने पैसे कमा लो और मुझे authentic sources से बता रहा हूँ मैं आपको। दिल्ली के अन्दर एम.सी.डी. हर साल सिर्फ और सिर्फ building activity से दस हजार करोड़ रुपये की रिश्वत इकट्ठा करती है, दस हजार करोड़ रुपये की रिश्वत इकट्ठा करती है। अब दस हजार करोड़ रुपये की रिश्वत इकट्ठी कर रहे हो। मैंने इनको कहा था, मैंने कहा इलाज बता देता हूँ भाई आसान सा इलाज है। हमने पिछले इलैक्शन में जनता से कहा था तब भी इन्होंने कुछ घुमा लिया था। इन्होंने क्या कहा था, दो ही चीज़ें बोली थीं ऊपर से पैसा लेकर आयेंगे और सारे चोरों को बदल डाला, तो जनता इस झांसे में आ गई। simple solution है आज भी बता देता हूँ अब करा लेना, दौबारा से बता देता हूँ भाईसाहब। एक lanter में जहां पांच लाख लेते हो ना के जी उसके पैसे रखो ढाई लाख सरकार को जमा करा दो, एम.सी.डी. को जमा करा दो। जहां पर दो लाख लेते हों एक लाख रुपये एम.सी.डी. को जमा करा दो। आपका पक्का काम हो गया, वो पैसा सरकारी खाते में आ जायेगा दस हजार करोड़ की जगह पांच हजार करोड़ जब इकट्ठा हो जायेगा ना सरकार के पास, कहते जी कि ये करने थोड़ा ना आये थे। कहते एम.सी.डी. का काम करने थोड़े ही आये थे हम, हम तो अपना पेट भरने आये थे। अब वो

अपना पेट कैसे भरें। तो ये सारा का सारा तंत्र भ्रष्टाचार के ऊपर टिका हुआ है। और बीजेपी को कुछ नहीं चाहिये पैसा इकट्ठा करने के लिए एक तंत्र चाहिये और एक चीज़ बता दूँ दिल्ली की एम.सी.डी. एक चीज़ में तारीफ है जी बहुत बड़ी तारीफ। दिल्ली की एम.सी.डी. फेमस है दुनिया के अन्दर Guinness Book of world record के अन्दर इनका नाम आता है या उसकी मीटिंग में आ जायेगा अगली मीटिंग में आ जायेगा। भ्रष्टाचार के अन्दर दुनिया में gold medalist है दिल्ली की एम.सी.डी.। पहले चौथे, पांचवे, दसवें नम्बर पर होती थी, पन्द्रह साल में इतनी मेहनत की दिल्ली के बीजेपी के काउंसलरों ने इतनी मेहनत की, इतनी मेहतन कि नम्बर वन पर ले आये हैं। अब वो कह रहे हैं ऐसा रिकार्ड बना देंगे कोई उसको तोड़ नहीं पायेगा कभी भी। तो इसके लिए ये एक्ट लेकर आये हैं और देखो जी इनकी बेचारों की मजबूरी है वो कुछ भी लिख दें। मैं पढ़ रहा था कोई reform नहीं लिखा, कुत्तों के बारे में जरूर लिखा है इसके अन्दर कि जी कुत्तों का रजिस्टर, मतलब एक्ट बनाने के अन्दर कुछ नहीं मिल रहा, कहते हैं कुत्तों का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा ये लिख दिया। अरे कोई काम की बात भी लिख देते कि एम.सी.डी. का भ्रष्टाचार कैसे खत्म करेंगे, एम.सी.डी. का काम कैसे करेंगे, एम.सी.डी. में सफाई कैसे करेंगे, ना जी कुत्तों का रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे ये लिख दिया।

...(व्यवधान)...

माननीय स्वास्थ्य मंत्रीः तो ऐसा है मेरा ये कहना है कि जो एक्ट लाया गया है सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए और कलैक्शन को डायरेक्ट ऊपर पहुंचाने के लिए बनाया गया है कि पैसा डायरेक्ट ऊपर पहुंचे और जहां तक बिधूड़ी जी ने कहा है कि जल्द इलैक्शन होंगे, दिल में तो उनको भी पता है कब होंगे। अगर ये सन् बता दें मंथ तो बता नहीं पायेंगे 2022 में होंगे कि 2023 में होंगे कि 2024 में होंगे। अगर हिम्मत है तो बता दें। ये खुद ही कहते हैं कि भाईसाहब अभी इलैक्शन न होंगे और इनकी चले, इनकी अगर चले तो ये कहेंगे हिस्ट्री, अभय वर्मा जी अभी कह रहे थे हिस्ट्री में जाकर देखो जी हिस्ट्री, मुझे लगता है हिस्ट्री काफी पढ़ी होगी इन्होंने। अरे हिस्ट्री ये कहती थी अंग्रेजों ने क्या किया था, अंग्रेजों के सामने elected कोई भी बॉडी की कोई वैल्यू नहीं थी अफसर उसके सिर पर बैठता था। अंग्रेजों के यहां वायसराय होते थे ये एसेम्बली तब भी लगती थी। एसेम्बली के अन्दर लोग चुनकर आते थे उनकी कोई औकात नहीं होती थी, कोई उनकी वैल्यू नहीं होती थी। यही करने जा रहे हैं एम.सी.डी. के अन्दर, उन सारे elected councilors के ऊपर ये अपना एक अफसर बैठायेंगे जो सारा का सारा काम वो देखेगा, सारी पावर उसके हाथ में होगी। ये हिस्ट्री नहीं है ये अंग्रेजों के गुलाम फिर से बनने जा रहे हैं। बाबाजी का नाम लेते हैं,उल्टा काम करते हैं। इनको संविधान में कोई विश्वास नहीं है। ये चाहते हैं कि देश को वापस गुलामी के अंदर लेके जायें। इस एक्ट को मुझे लगता है

कि बिल्कुल बेईमानी के हिसाब से बीजेपी लेके आई है और दिल्ली के अंदर। ये लोग चाहते नहीं है कि कुछ भी काम हो, मैं तो कहूँगा भगवान इनको सन्मति दे, बुद्धि दे और ये इलेक्शन फटॉफट करा दे। धन्यवाद जय हिन्द-जय भारत।

माननीया अध्यक्षः माननीय उप मुख्यमंत्री जी।

माननीय उप मुख्यमंत्री (श्री मनीष सिसोदिया): धन्यवाद माननीय अध्यक्षा महोदय। सबसे पहले तो आपको बधाई आज बहुत लंबे अरसे बाद पूरा दिन का सेशन आपने कंडक्ट किया और बहुत ही एफीशिएंटली, बहुत अनुशासन के साथ में चलाया और हर चीज में बहुत टाइमकीपिंग सबके आपने बनाकर रखी इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। अध्यक्षा महोदय, आज देश की संसद में एमसीडी चुनाव रोको बिल लेकर आया गया है, नाम तो उसका कुछ और रखा है पर असली नीयत वही है। एमसीडी चुनाव रोको बिल आज देश की संसद में लेकर आए हैं। देश की आजादी को 75 साल हो गए, 75 साल के इतिहास में संसद में पहली बार केन्द्र में बैठी हुई सरकार एक म्युनिसिपल्टी का चुनाव रोकने के लिए बिल लेकर आई है, पहली बार घबराई हुई सरकार और देश और शायद मैं कहूँगा दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि किसी देश का खूब पावरफुल प्रधानमंत्री पूर्ण बहुमत की सरकार कई राज्यों में सरकार, सरकारों पर सरकारें इतना ताकतवर प्रधानमंत्री पहली बार उसके मन में नगर निगम चुनाव हारने का डर

पैदा हुआ होगा ये पहली बार हुआ होगा देश में। मतलब मैं ये बिल सोच रहा था क्या है अभी सत्येन्द्र जैन जी बात कर रहे थे इसमें रिफॉर्म-विफॉर्म कुछ नहीं है, अभी सौरभ भारद्वाज जी भी बात कर रहे थे बड़े अच्छे से मैं उनको सुन रहा था। मतलब देश के प्रधानमंत्री को जहां ये चिंता होनी चाहिए कि युक्रेन और रूस के युद्ध में भारत की स्थिति क्या हो, राइटली होनी चाहिए। उस समय देश के प्रधानमंत्री बिल लेकर आ रहे हैं कि करावल नगर में कुत्ते की पोट्टी कौन साफ करेगा। प्रधानमंत्री को चिंता इस बात की हो रही है इसमें लिख रहा है कि दिल्ली नगर निगम की गलियों में कुत्ते घूम रहे होंगे उनकी पॉटी साफ करने के अधिकारी की जिम्मेदारी अब प्रधानमंत्री तय करेंगे। तो अध्यक्ष महोदय, ठीक है, ठीक है।

माननीया अध्यक्षः देखिये संयम बरतें उप-मुख्यमंत्री बोल रहे हैं न। आप तो इतने सीनियर हैं। एक बार बोलने दीजिए न सुनिये न आप, शांति बनाए रखें।

माननीय उप मुख्यमंत्रीः अध्यक्षा महोदय, मैं फिर से कह रहा हूँ कल मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने की डींग हांकने वाली पार्टी को आज भारत की सबसे छोटी पार्टी से डर लग रहा है। कहते हैं हम देश की सबसे बड़ी पार्टी हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पॉलीटिकल पार्टी हैं, देश की एक चिंदी सी पार्टी है हमारी तो आम आदमी पार्टी उससे डर लग रहा है और फिर संसद में बिल लेकर आ रहे हैं उसके नेता को

रोकने के लिए। ये एमसीडी का बिल क्यों लाया गया? ये इसीलिए लाया गया क्योंकि पहले एक होता था 10 साल पहले, 10 साल पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वहां पर तब कौन सा इन्होंने दिल्ली में सफाई कर रखी थी, तब भी कूड़े के पहाड़ ही थे। फिर इन्होंने एक का तीन कर दिया तीन के समय भी कूड़े के पहाड़ हुए हैं, फिर तीन का एक करेंगे कूड़े के पहाड़ ऐसे ही रहेंगे। जो इन्होंने सबने जिक्र किया कि इतना भ्रष्टाचार है वो 10 साल पहले भी होता था जब एक होता था अब तीन हो गये फिर भी होता है फिर एक करेंगे ये वैसे ही रहेगा, न एक के तीन में कुछ बदला न तीन के एक में कुछ बदलेगा। नगर निगम में जब तक भारतीय जनता पार्टी है तब तक कुछ नहीं बदलेगा। अगर नगर निगम में कुछ बदलना है तो उसको तीन का एक, एक का तीन, तीन का एक, एक का तीन मत करो उसको भारतीय जनता पार्टी को हटा दो नगर निगम बदल जाएगा। एक ही तरीका है और ये भी इस बात को अच्छे से जानते हैं और जनता ने इस बार मन बना रखा है और ये बात इनको भी समझ में आ रही है क्योंकि दिल्ली की जनता इस बात को समझती है कि एक का तीन, तीन का एक के झांसे में अब जनता नहीं आ रही। जनता के मन में जगह-जगह से उबलकर आ रहा है एमसीडी में भी केजरीवाल, एमसीडी में भी केजरीवाल, जिस गली में जाओ एमसीडी में भी केजरीवाल। जिस मौहल्ले में जाओ हर जगह से आवाज सुनाई दे रही है एमसीडी में भी केजरीवाल और ये आवाज

प्रधानमंत्री जी के कानों तक भी पहुंच गई। इतनी आवाज आ गई, इतनी आवाज आ गई इसलिए आज दिल्ली के एक-एक आदमी की आवाज को दबाने के लिए कि जनता सोच रही है न ये जो बिल लाया गया है ये दिल्ली की जनता की उस आवाज को दबाने के लिए लाया गया है जिसमें जनता ये कह रही है एमसीडी में भी केजरीवाल, एमसीडी में भी केजरीवाल, एमसीडी में भी केजरीवाल ये इससे घबरा गए हैं। बीजेपी की केन्द्र सरकार, होम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जी सबको दिल्ली की जनता के दिल की बैठी हुई बात से डर लग गया, सबको टेंशन दे दी। आप सोचो इतनी टेंशन दे दी बीजेपी वालों को, इतनी टेंशन दे दी प्रधानमंत्री जी, होम मिनिस्टर साहब को दिल्ली की जनता की इस आवाज ने कि एमसीडी में भी केजरीवाल, एमसीडी में भी केजरीवाल। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि देश में पहली बार हो रहा है कि देश का प्रधानमंत्री किसी अपोजिशन के लीडर को हराने के लिए म्युनिसिपल्टी की टेंशन ले रहा है। देश का प्रधानमंत्री किसी अपोजिशन के लीडर को रोकने के लिए एक म्युनिसिपल्टी के चुनाव में इन्ट्रेस्ट ले रहा है, पहली बार हो रहा है देश में, नहीं तो देश के प्रध ानमंत्रियों ने बड़ी चीजों में इन्ट्रेस्ट लिया ऐसी चीजों में कभी नहीं लिया। ये बिल क्या कह रहा है? कुल मिलाकर ये बिल यही कह रहा है कि अब म्युनिसिपल्टी को एमसीडी को प्रधानमंत्री जी चलाएंगे। देश चलाते-चलाते केजरीवाल जी के डर से म्युनिसिपल्टी चलाने पर आ गए। देश चलाते-चलाते और ये केजरीवाल का डर

अच्छा है, ये जरूरी है, ये डर जरूरी है। देश चलाते-चलाते देश चलाने वाला आदमी केजरीवाल जी के डर से म्युनिसिपल्टी चलाने के लेवल तक आ गया। सबसे बड़ी पार्टी के लीडर को छोटी सी पार्टी के लीडर का इतना डर, देश के पीएम कह रहे हैं कि म्युनिसिपल्टी मैं चलाऊंगा, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि एमसीडी भी मैं चलाऊंगा, नहीं तो एमसीडी में भी केजरीवाल आ जाएगा। क्या डर है अध्यक्षा महोदय इनका? इनका डर है कि अगर एमसीडी में भी केजरीवाल आ गए तो एमसीडी भी वैसे ही काम करने लगेगी जैसे केजरीवाल जी की सरकार में दिल्ली सरकार के विभाग काम करने लगेंगे। ये कहते थे सरकारी स्कूल ठीक नहीं हो सकते पैसा नहीं है इसीलिए प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाओ बच्चों को। आज 7 साल बाद सारा देश इस बात का लोहा मान रहा है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई हो भी सकती है और प्राइवेट स्कूलों से अच्छी हो सकती है। ये कहते थे बिजली महंगी हो गई तो हो गई और दिल्ली में कौन सा बिजली बनती है जो 24 घंटे बिजली आ जाए, ये थे इनके डायलॉग। आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली मिल रही है और 92 परसेंट आबादी को बिजली की स्कीम्स का फायदा मिल रहा है 92 परसेंट आबादी। ये इस बात से घबराए हुए हैं। इन्हें कौन सा सफाई प्रेम है, इनको कौन सा भ्रष्टाचार खत्म करना है जिसकी सत्येन्द्र जी बात कर रहे थे। ये तो इस बात से घबरा रहे हुए हैं कि जैसे केजरीवाल जी ने कहा और सीसीटीवी लग गए, केजरीवाल जी ने कहा और वाई-फाई लग गए। केजरीवाल जी

ने कहा स्कूल ठीक हो गए, मौहल्ला क्लीनिक बन गए। तो केजरीवाल जी ने ये कह दिया कि एमसीडी आ जाएगी, दिल्ली साफ करके दिखाएंगे इसलिए लाए हैं। ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है लोकतंत्र के लिए भी और देश के लिए भी। लोकतंत्र के लिए इसलिए क्योंकि बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है उसमें चुनाव संविधान की आत्मा है। चुनाव को टालना इस संविधान की आत्मा की हत्या करने के बराबर है और देश के लिए इसलिए कि देश के प्रधानमंत्री को अगर किसी म्युनिसिपल्टी की गलियों में डॉगी की पोट्टी याद आती है कि वो कैसे साफ होगी तो इसका मतलब देश के प्रधानमंत्री को और कोई काम नहीं बचा है उनका स्तर वहां तक आ गया है, दोनों चीजें खतरनाक है। मैं जानता हूँ कि अब ये बिल संसद में आया है और संसद में तो पास होगा ही होगा और ये कानून भी बनाएंगे इनके पास में पावर है। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूँ कि चुनाव करवाइए हारिए या जीतिए आम आदमी पार्टी हारे या जीते, लोकतंत्र को जीतने दीजिए। इतना मत घबराइए कि देश का सबसे बड़ा मुखिया देश के एक शहर की म्युनिसिपल्टी के चक्कर में पड़ जाए और प्रधानमंत्री का पद इतना नीचे गिरा दे, प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को गिरा दे। सिर्फ इसलिए कि क्योंकि आप अपोजिशन के लीडर को रोकना चाहते हैं। सिर्फ इसलिए कि क्योंकि आप केजरीवाल जी को रोकना चाहते हैं, केजरीवाल जी नहीं रूकने वाले। कुछ भी कर लो केजरीवाल तो आएगा, केजरीवाल तो आएगा। ये तो होने वाला है, ये नहीं रूकने वाला अब आपसे। आप म्युनिसिपल्टी में इंटरवेंशन

करो, आप वार्ड में इंटरवेंशन करो जिसमें भी करो केजरीवाल जी दिल्ली की जनता के दिल में बैठे हैं, एमसीडी में केजरीवाल, दिल्ली की जनता ने ठान लिया है लेकर आएगी, आप अभी चुनाव कराओ, 6 महीने बाद कराओ, 1 साल बाद कराओ हम भी यही बैठे हैं और आप भी यही बैठे हैं बात कर लेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्षा महोदय।

माननीया अध्यक्षः चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अब सदन की कार्यवाही शनिवार दिनांक 26 मार्च, 2022 को पूर्वान्ह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(सदन की कार्यवाही शनिवार दिनांक 26 मार्च, 2022 को पूर्वान्ह 11:00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।)

... समाप्त ...

© दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 18 (2) के उपबंधों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 281 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित तथा ग्राफिक प्रिंटर्स, 2965 /41, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110 005 द्वारा मुद्रित।